

राष्ट्रपति के सस्मरण

राष्ट्रपति के संस्मरण

नीलम सजीव रेड्डी
— — —



राजपाल एण्ड सन्स

कश्मीरी गेट, दिल्ली

मूल्य पचास रुपये (50 00)

© N Sanjiva Reddy 1989

Hindi translation of **WITHOUT FEAR OR FAVOUR**

Reminiscences & Reflections of a President by N Sanjiva Reddy

ISBN 81 7028-072 9

प्रस्तावना

भारत के राष्ट्रपति के रूप में पाच वष की अवधि (जुलाई 25, 1977 से जुलाई 24, 1982) के अपने कुछ अनुभवों को मैंने इस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। इसका प्रारूप सन् 1982 में तैयार किया गया था, पुस्तक पढ़ते समय पाठकों को इसे ध्यान में रखना आवश्यक है।

मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इसके प्रकाशन में सहयोग दिया।

अक्टूबर 1, 1989
बंगलौर

नीलम सजीव रेड्डी

विषय-क्रम

राष्ट्रपति के पर पर	9
तिरुनति और मद्रास यात्रा	13
अमरीका में मेरी अंतिम सिगरेट	16
राष्ट्रपति भवन इत्यादि विशाल क्यो	18
जयप्रकाश नारायण से प्रेरणापूर्ण सपक	21
राजा जी के वादरा	24
सन् 1979 का संवैधानिक सकट	29
अरुणासिंह से मतभेद	46
विदेश यात्राओं के प्रसंग	48
सोवियत रूस और बलगेरिया में	48
बेन्सा और ज्ञानिमा यात्रा	52
इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स का विवाहोत्सव	55
इण्डोनेशिया और श्रीलंका यात्राओं का स्थगन	58
इण्डोनेशिया और नेपाल में	60
श्रीलंका का लापङ्ग	65
आयरलैंड और यूगोस्लाविया में	71
सार्वजनिक समारोह कुछ विचारणीय प्रश्न	77
असम और दिल्ली दोहरे मानदण्ड	84
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विरोधी दल	89
सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार	92
स्वतंत्रता सप्रान के सेनानी	96
राष्ट्रपति और भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी	100
विश्वविद्यालय और भारतीय राष्ट्रपति	104
मेरा अंतिम गणतन्त्र दिवस संदेश	106
भारतीय परिवर्तन धितनीय विषय	108

राष्ट्रपति के पद पर

फखरुद्दीन अली अहमद जो कि अगस्त 1974 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, उनका स्वगवास सामान्य पांच बप की अवधि समाप्त होने से बहुत पहले फरवरी 1977 में हो गया। इसके पश्चात बी० डी० जती, उपराष्ट्रपति ने कार्यकारी राष्ट्रपति का पद सम्भाला। केन्द्र में नवनिर्वाचित जनता सरकार को जिन समस्याओं को हल करना था उनमें से एक राष्ट्रपति का निर्वाचन भी थी।

मार्च 1977 में लोकसभा के लिए हुए निर्वाचन में, आंध्र प्रदेश से मैं एकमात्र विजयी उम्मीदवार था जो जनता दल के चिह्न पर जीता था। अपने चुनाव के कुछ दिनों बाद मैं स्वसम्मति से लोक सभा का स्पीकर चुन लिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी से अपना सम्बंध तोड़ चुका था और जनता पार्टी उस समय तक औपचारिक रूप से बन नहीं पाई थी। वह 1 मई 1977 को ही विधिवत बन पाई। इस प्रकार उस समय मुझे किसी पार्टी से अपना सम्बंध विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं थी।

अप्रैल 1977 के प्रारम्भ में, जबकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का प्रश्न सरकार के सामने था, मुझे हैदराबाद जाने का अवसर मिला। कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अपने को उस पद की उम्मीदवारी के लिए प्रस्तुत करूंगा। ज़ायद प्रेस तथा जनता के लिए सन् 1969 के ऊर्ण जाहिर विश्वासघात की दृष्टि में रखते हुए मेरे बारे में उस प्रकार विचार करना अस्वाभाविक नहीं था। तथापि मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं चुनाव नहीं सटूंगा। इसके साथ ही मैंने यह आशा प्रकट की कि जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियाँ भारत के राष्ट्रपति पद के लिए स्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने में सफल होंगी।

जनता तथा कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों में से किसी का भी बहुमत राष्ट्रपति का निर्वाचन करनेवाले मतदाताओं को कि ससद के दोनों सदनों और राज्य की विधान सभाओं के सदस्य होते हैं, में नहीं था। जिन राज्यों में मार्च 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी पराजित हो चुकी थी, उन राज्य विधान सभाओं को भंग कर दिया गया था और नये निर्वाचन जून 1977 में हुए थे। भंग होने से

पूव इन विधान सभाओ मे कांग्रेस पार्टी का भारी बहुमत था लेकिन जून 1977 के चुनावो मे जनता पार्टी करीब उतने ही अधिक बहुमत से आयी। शासक जनता पार्टी के पक्ष मे होते इस विकास के कारण वह कांग्रेस से अधिक मत पाने की शक्ति रखती थी तथापि राष्ट्रपति चुनाव मे भाग लेनेवाले मतदाताओ मे उसका बहुमत नहीं था। जनता पार्टी तथा कांग्रेस के बाद, दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण पार्टिया थी—ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कळगम (ए आई ए डी एम के) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्ससिस्ट (सी पी आई एम) उनके पास पर्याप्त मतदान शक्ति थी। केन्द्र मे जनता पार्टी कांग्रेस की सहायता की चिन्ता किए बिना अपने सहयोगी अकाली दल की मदद पर अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती थी परन्तु इस प्रकार की क्रिया खतरों से भरी थी। इसलिए बुद्धिमानीपूर्ण सलाह-मशविरे के बाद यह तय पाया गया कि कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के साथ मिल बैठकर सबसेसम्मति से निर्णय लिया जाय। उस समय भी जब शासक दल का निर्वाचक गणा मे पर्याप्त बहुमत हो और उसके उम्मीदवार की सफलता निश्चित हो, यह बेहतर होता है कि वह मुख्य विरोधी पार्टियों और समूहों से सलाह लेकर उम्मीदवार चुने ताकि राष्ट्रपति जो कि पूरे राष्ट्र की चेतना का प्रतीक होता है, यदि सभी पार्टिया और समूहों द्वारा सबसेसम्मति से नहीं तो कम से कम देश के अधिक से अधिक सम्भावित लोगों द्वारा चुना जा सके।

निर्जलिगप्पा, कांग्रेस पार्टी मे मेरे पूव सहकर्मी और जनता पार्टी की नीव डालनेवाला मे से एक, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए होनेवाले निर्वाचन मे उम्मीदवार बनना चाहते थे। उन्होने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से इस सबध मे बातचीत की। तथापि प्रधानमंत्री ने उनका बताया कि चूँकि उपराष्ट्रपति के पद पर उसी राज्य और उसी समुदाय का व्यक्ति बी० डी० जती पहले से है जिसके निर्जलिगप्पा हैं, जनता पार्टी के लिए उनको अपना उम्मीदवार बनाना समभव नहीं होगा। इसवे बाद निर्जलिगप्पा मुझसे मिलने आय, जो कुछ घटित हुआ था मुझे बताया और बगलौर चले गए।

जुलाई 1977 की शुरुआत मे प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार की खोज करना प्रारम्भ की। जनता पार्टी के पालिया मेट्टी वोड से विचार विमर्श करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और लोक सभा मे विरोधी दल के नेता वाई० बी० चह्माण से भी नामों की एक सूची पर, जिसमे श्रीमती रुक्मिणी अरुण्डेल का नाम सबसे ऊपर था सलाह की। सम्भवतया मोरारजी देसाई और चह्माण मे श्रीमती अरुण्डेल के नाम के चुनाव पर सहमति थी। जब उनकी पसन्दगी के बारे मे सभी को पता चला, दूसरों की प्रतिक्रिया उनसे बहुत विपरीत थी। दोनों नेताओं द्वारा चुने गए नामों से उत्पन्न असन्तोष पार्टी की सीमाओं को पार कर गया। शासन करनेवाली जनता

पार्टी और विरोधी कांग्रेस पार्टी के सदस्यो ने अपनी भावनाओ को खुले-आम प्रकट किया।

सी पी आई एम ने भी अपनी अप्रसन्नता प्रकट की, उसने महसूस किया कि प्रधानमंत्री को जनता और कांग्रेस की सहमति से की गई पसंद उसके सामने रखने के बजाय, उसे सत्ताह में शामिल करना चाहिए था। उसने स्पष्ट कर दिया कि अगर शासक दल ने आगे कारवाई की और श्रीमती अरुण्डेल की अपना उम्मीदवार बनाया, वह अपना उम्मीदवार खड़ा करने में सकोच नहीं करेगी। इविंग मुनेत्र बजगम (डी एम के) और ए आई डी एम के ने भी प्रधान मंत्री द्वारा चुने उम्मीदवार के प्रति अपनी उत्साहहीनता दिखाई। अनेको के विचार से केवल राष्ट्रीय महत्त्व का ऐसा व्यक्ति जिसे सार्वजनिक जीवन का बहुत लम्बा अनुभव हो राष्ट्रपति के उच्च पद के लिए चुना जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि श्रीमती अरुण्डेल इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती।

अतः प्रधानमंत्री के लिए इस समस्या पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक हो गया। यद्यपि जनता पार्टी के नेताओ द्वारा प्रारम्भ में दिए गए सुझावा में मेरा नाम नहीं आया था तथापि संसद के अनेको सदस्यो, जनता पार्टी और कांग्रेस तथा अन्य विरोधी पार्टियों और समूहो के मन में मेरा नाम सर्वोपरि था। इस स्थिति में मैंने दोबारा एक प्रेस बयान जारी किया कि मैं उस समय तक निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हूंगा जब तक कि मैं सभी पार्टियों द्वारा एक संवन्धित उम्मीदवार नहीं माना जाता। यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि श्रीमती रुक्मिणी अरुण्डेल का पक्ष लेनेवाला का अभाव है और शासक दल के लिए उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते रहना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। मोरारजी ने श्रीमती अरुण्डेल का नाम प्रस्तावित करने से पूर्व उनकी सहमति से सी पी ओ वि उस समय यूरोप में कहीं थी, लेकिन जब उनके नाम का विरोध बढ़ता गया, ऐसा जताया गया कि वह उम्मीदवार बनने की इच्छुक नहीं थी। इस प्रश्न पर विस्तृत सहमति पाने की सम्भावना के लिए विभिन्न स्तरों पर विचार विनिमय किया गया।

प्रधानमंत्री ने नए सिरे से अपनी पार्टी के पार्लियामेन्ट्री बोर्ड से सत्ताह की, आम भावना यह थी कि मैं सबसे अधिक सहमति पानेवाला उम्मीदवार हूंगा, तथापि एक दूसरा नाम भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने विरोधी पक्ष के नेता चह्माण से विचार विमर्श किया। चह्माण ने कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के सदस्यो की राय जानने के लिए कुछ और समय चाहिए।

कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली सदस्य (जिनमें से अनेक संसद सदस्य नहीं थे।) सब सम्मति से राष्ट्रपति पद के लिए जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार खड़ा करने के विचार से विरोध रखते थे। उनका तर्क ऐसा प्रतीत होता है, यह था कि कांग्रेस को अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता पर बल देने के लिए अपना उम्मीदवार

छड़ा करना चाहिए, चाहे उसके चुनाव जीतने की आशा कितनी ही कम हो। लेकिन इस दृष्टिकोण को सामान्य स्वीकृति नहीं मिली।

जब मैं 7 जुलाई 1977 को लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा था, के० सी० पन्त जो कि उस समय लोक सभा के सदस्य नहीं थे, मे वागज की एक पच्ची मेरे पास भेजी, जिसमें सूचित किया गया था कि कांग्रेस मेरी उम्मीदवारी के लिए सहमत हो गई है। जम्मू और काश्मीर के कर्णसिंह, जो कि विरोधी पार्टी के सामनेवाली बेंच पर बैठे थे, उन्होंने भी इसी आशय की एक पच्ची मेरे पास भेजी। प्रधानमंत्री इन गतिविधियों को देख रहे थे और उन्होंने भी सूचना भेजी कि मेरा नाम जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उचित पद के लिए चुना गया है। उमी दिन जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री द्वारा जनता पार्टी के नेताओं से सी गयी सलाह में सभी नेताओं की सम्मति मेरे लिए थी। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस, ए आई ए डी एम के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फारवर्ड ब्लाक, अकाली दल, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं से भी सलाह कर ली थी। ससद की इन सभी पार्टियों द्वारा मेरा पक्ष लेने की सम्मति से, राष्ट्रपति पद के लिए मेरा निर्वाचन वास्तव में निश्चित हो चुका था। मैंने टेलीफोन से डी एम के नेता एम० करुणानिधि से बात की और उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा समर्थन देने का आश्वासन दिया।

उस दिन मध्याह्न भोजन की अवधि में, मैं मोरारजी देसाई से मिला और उन्हें अपना नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की सूची में शामिल करने के लिए धन्यवाद दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने गृह नगर जाना चाहता हूँ और अपनी माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। इस विचार से वह बहुत प्रसन्न हुए। बाद में, मैंने शाम को विरोधी पार्टी के अन्य नेताओं को भी उनके पूरा समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद मैं अन्तपुर अपनी मा के दशन करने के लिए चल पड़ा। उनके साथ एक दिन व्यतीत करने के पश्चात मैं दिल्ली लौट आया। राष्ट्रपति पद के लिए कोई प्रतिद्वन्द्वी नहीं था, अतः मैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित कर दिया गया।

मैंने भारत के राष्ट्रपति पद की अपनी शपथ 25 जुलाई 1977 को ससद के सेंट्रल हॉल में ली। भारत के मुख्य 'यायाधीश एम० एच० वेग द्वारा सविधान की धारा 60 के अन्तर्गत चुले शपथ दिलाई गयी। मैंने अपने उद्घाटन भाषण में इस विषय पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार जनता के विचार की शांतिपूर्ण पुष्टि द्वारा देश में एक परिवर्तन आया है जो कि मात्र राजनतिक रूपांतरण नहीं बरन एक मौन क्रांति है। इस प्रकार उसने एक नए युग का प्रारम्भ किया है तथा शांतिपूर्ण परिवर्तन के पथ और अपनी प्रजातांत्रिक प्रणाली के प्रति विश्वास के समर्थन को पुनः पुष्ट किया है। उसे आवश्यकता है एक नवीन

संतुलन की, आपसी समझौते की नयी भावना की जो कि केवल सच्ची समानता, और अधिक अवसरों की उपलब्धता तथा जनता के कमजोर वर्ग के लिए पहले से अधिक सहानुभूति की नई सीमाओं का अधिक विस्तार करने से ही लाई जा सकती है। देश की क्षेत्रीय, धार्मिक और भाषाई विभिन्नताओं के बीच एक आधारभूत एकता स्थित है। हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि विभाजन करनेवाली राजनीति से स्पष्ट रूप से दूर रहे और राष्ट्रीय ऊर्जा का उपयोग जनता का अधिक से अधिक कल्याण करने के लिए करें।

तिरुपति और मद्रास यात्रा

पद ग्रहण करने के बाद मैं शीघ्र से शीघ्र तिरुपति जान और भगवान् वेंकटेश्वर की पूजा करने का बहुत इच्छुक था लेकिन वह मैं स्वतन्त्रतादिवस से मूख नहीं कर सका। कुछ भी हो राष्ट्रपति बनने के बाद मेरी प्रथम यात्रा तिरुपति की थी।

तिरुमलाई और तिरुचनूर में परिवार सहित अपनी प्राथना मेंट करने के बाद मैं 18 अगस्त को मद्रास गया। वहाँ मैंने कामराज की प्रतिमा का अनावरण किया जो कि पतीस वर्षों से भी अधिक तमिलनाडु की विधान सभा मंडल (चैम्बर) में मेरे मित्र और सहकर्मी रहे थे। कामराज से मेरा संबंध इतना सबा रहा था और उनके प्रति मेरा स्नेह इतना महान था कि यह मेरे लिए बहुत सन्तोष की बात थी कि राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम जनसभा जिसमें मैंने भाग लिया उनकी स्मृति में आयोजित हुई थी। मैंने कामराज की राष्ट्र के लिए की गई निस्वाय और सभी देशसेवा के प्रति श्रद्धाजलि अर्पित की। उनमें धन और सत्ता के लिए कोई आकषण नहीं था। उन्होंने एक स्वच्छ और सादा जीवन व्यतीत किया और अपने पीछे किसी प्रकार की भौतिक संपत्ति नहीं छोड़ गए। मद्रास का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया था। जवाहरलाल नेहरू तथा दूसरों द्वारा कामराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसीडेंट चुनना उनकी आन्तरिक अच्छाइयों और राष्ट्र के प्रति सेवा भावना से समर्पित होने का प्रमाण है। कामराज एक विनम्र व्यक्ति थे और अपनी सीमाओं को जानते थे। नेहरू जी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने कुछ नेताओं के इस सुझाव को कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। मुझे उस सभा में याद आया कि किस प्रकार हमारे राजनैतिक करियर समानान्तर रूप से आगे बढ़े, जब वह तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट थे, मैं आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसीडेंट था। मेरा प्रथम बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और उनका मद्रास का मुख्यमंत्री बनना लगभग साथ साथ घटित हुआ। हम दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेंट रहे थे। अपने भाषण में, मैंने इस बात का भी उल्लेख किया कि किस प्रकार हम

दोनों बिना किसी तक वितक और बटुता के मद्रास तथा आंध्र प्रदेश के तिरुत्तानी और अरु सीमा क्षेत्रों की समस्या को हल करने में सफल हुए थे। हम दोनों द्वारा प्रस्तावित समझौता दोनों राज्यों की विधान सभाओं ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। कामराज और मैं अक्सर तिरुमलाई में मिला करते थे। दुर्भाग्यवश कुछ नेताओं को इन मुलाकातों के बारे में गलतफहमी हो गई। हमारी इन मुलाकातों का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दों पर एक दूसरे के विचारों को जानना-समझना होता था। मैंने सभा में बताया कि किस प्रकार कामराज के जीवन के अन्तिम तीन महीने में मैं उनसे कई बार मिला और वह देश की स्थिति से कितना दुःखी थे। उनके स्वर्ग-वास के समय भी देश में 'आपातस्थिति' (इमर्जेंसी) लगी हुई थी। मैंने बताया कि किस प्रकार निपेक्षाओं की अवहेलना करते हुए मैंने कामराज के निधन का समाचार सुनकर अनन्तपुर में शोकसभा आयोजित की और किस प्रकार इस सभा का समाचार किसी भी समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया।

उसी दिन मद्रास में मेरा दूसरा कार्यक्रम था, ऐसा जिसमें भाग लेते हुए मैंने अपने को सम्मानित अनुभव किया। यह गांधी जी के पूर्णकारित्र का अनावरण करना था। मैंने सभा में बताया कि किस प्रकार देश को एक दूसरे महात्मा गांधी की आवश्यकता है जो हमारे अंदर स्वतंत्रता संग्राम के दिनों की स्वामहीन त्याग की भावना को पुनः प्रज्वलित कर सके।

अमरीका मे मेरी अन्तिम सिगरेट

28 अगस्त 1977 को मद्रास और तिरुपति से वापस आने के बाद शीघ्र मैं ऑल इंडिया इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेज मे, कुछ दात औपधिजन्य मूर्छा (एनेस्थेसिया) मे निकलवाने की प्राथमिकता पूरी करने के लिए अपना मेडिकल चेकअप करवाने गया। इस अवसर पर डाक्टरों ने माए फेफड़े के ऊपरी भाग मे एक सिक्के के गोलाकार रूप का घाव पाया। डाक्टरों ने एक पनल मे जिसमे डा० बी० रामासिगास्वामी, डा० जे० एस० बजाज, डा० बी० भागव, डा० एन० गोपीनाथ, डा० डी० जे० जस्सावाला और डा० ए० एस० रामकृष्णन थे, विस्तृत जाच-पड़ताल तथा अध्ययन किया। पहले चार डाक्टर आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेज के थे और भारत तथा विदेशो मे अपने-अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप मे प्रख्यात थे। पाचवें बम्बई के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ थे जिह् विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के स्पष्ट सुझाव पर बुलाया गया था। पैनल के अन्तिम सदस्य मद्रास के प्रतिष्ठित सज्जन थे जो कि तीस वय स भी अधिक स मेरे डाक्टर रहे थे। विस्तृत अध्ययन के बाद पैनल का यह विचार बना कि घाव की सजरी करने के उद्देश्य से तत्काल जाच करने के लिए थेरावट्रॉमी की जाये। सारी परिस्थितियों को ध्यान म रखते हुए पैनल इस निष्कष पर आया कि 'यूनाक का मेमोरियल हास्पिटल और मोलन केटेरिंग इस्टीट्यूट इस केस की पूरी तरह सभासने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा।

मैंने डा० जस्सावाला से जानना चाहा कि क्या आवश्यक सजरी बम्बई मे ही नहीं हो सकती। उन्होंने उत्तर दिया कि भारत मे सजरी सम्भव है लेकिन ऑप रेशन के बाद दी जाने वाली जो रेडियेशन सुविधायें भारत मे उपलब्ध हैं वे उस दशा मे पर्याप्त नहीं होगी यदि घाव कैंसरयुक्त और अधिक फल चुका हुआ। पनल के सभी डाक्टरों का यही मत था। वे सभी अनुभव करते थे कि मुझे सजरी तथा उसके बाद के आवश्यक उपचार के लिए अमरीका जाना चाहिए। उन्होंने इसी आशय की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने वह समस्त प्रबंध करने का निणय लिया जो कि राष्ट्रपति के उपचार के लिए आवश्यक हैं। वेबिनेट सेनेटरियेट द्वारा 30 अगस्त 1977 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मेडिकल रिपोर्ट का सारांश देते हुए कहा गया कि राष्ट्रपति जितना शीघ्र होगा भारत से चले जायेंगे और देश से लगभग एक माह तक बाहर रहेंगे।

उस दिन और उसके बाद वाले दिनों भी मैं पहले से निश्चित अपने सभी कार्यों को बाहर जाने से पूर्व तक पूरा करता रहा। मेरे द्वारा ऐसा न करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि मुझे कोई भी शारीरिक कष्ट अनुभव नहीं हुआ था। सरकार ने शीघ्र मेरी अमरीका यात्रा तथा डाक्टरों के पेनस द्वारा अनुमोदित इस्टीमेट में मेरा उपचार करवाने के सभी प्रबंध कर दिए। मैं चार सितम्बर, 1977 को अमरीका के लिए रवाना हुआ। मेरे साथ मेरी पत्नी तथा मेरा पुत्र डा० सुधीर रेड्डी, (जोकि कुछ सप्ताह पहले ही सजन का उच्च प्रशिक्षण लेकर अमरीका से आया था) थे। विमान पर चढ़ने से पूर्व मैंने अनेको मित्रों और रिश्तेदारों से जो मुझे विदाई देने के लिए एयरपोर्ट पर एकत्रित हो गए थे, विदा ली। मुझे उस ऑपरेशन और उपचार के परिणाम की जो मैं शीघ्र लेने को बाध्य था, कतई चिंता नहीं थी। जिस समय मैं देश से विदा ली, मैं हसमुख और प्रसन्न मनोस्थिति में था। ऑपरेशन सफल रहा तथा पन्द्रह दिन के अंदर मुझे डाक्टरों से भारत वापस लौटने की अनुमति मिल गई। तब स मैं निरन्तर स्वस्थ हूँ। मोरारजी देसाई ने जिस समय मैं विदेश में था, मुझे लिखा था कि किसी भी अन्य वस्तु से अधिक यह मेरा साहस था जिसने मुझे इतना शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करा दिया था। ऑपरेशन से पहले मैं घूँघ्रपान का अभ्यस्त था, बहुत अधिक आदी। मैंने अपनी अन्तिम सिगरेट उस समय पी जब मैं ऑपरेशन थियेटर से जाया जा रहा था और तब से मैं सिगरेट का स्पश नहीं किया है। मैं बिना किसी कठिनाई के अपनी आदत छोड़ सकता था। मुझे कभी-कभी आश्चर्य होता है कि मैं पहले घूँघ्रपान करता ही क्यों था? मैं अपने घूँघ्रपान प्रेमी मित्रों को बताना चाहता हूँ कि यदि वे सचमुच इस हानिकारक और खर्चीली आदत को त्यागना चाहें तो वे ऐसा सरलता से कर सकते हैं।

राष्ट्रपति भवन इतना विशाल क्यों ?

राष्ट्र के नाम स्वतन्त्रता दिवस के अपने प्रथम सप्ताह में मने भेदे दिवाले और अनावश्यक तड़क भड़क को हटाकर परबस दिया। मैं कहा कि मैंने निश्चय किया है कि "राष्ट्रपति भवन को छोड़कर किसी सादा भवन में रहूँ जो कि भारत के राष्ट्रपति के उच्च पद तथा सम्मान के बिम्ब या निपिड नहीं होगा।" मेरे निगम के अनुसार सरकार तथा मेरे सचिवालय के संबंधित अधिकारियों ने हैदराबाद हाउस को राष्ट्रपति निवास के रूप में प्रयोग करने की सम्भावना का परीक्षण किया। तथापि उन्होंने पाया कि यह भवन बरखूरबा गांधी भाग की ऊँची इमारतों के बहुत निचट है तथा भारी आवागमन से भी दूर नहीं है और इसलिए किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है। तब उन्होंने राष्ट्रपति इस्टेट के अन्दर भवन सं० 1 और 2 बिलिंगटन क्रिसेंट पर विचार किया। यहां भी उन्होंने अनुभव किया कि अनको अतिरिक्त निर्माण तथा परिवर्तन करने हूँगे उसने बाद ही वह राष्ट्रपति, उसने निजी स्टाफ और उसने एंडी सी आदि के रहने योग्य बन सकेगा। इसमें 1,25,00,000 रु० से अधिक का अनापराधपूर्ण व्यय तथा लगभग 10,00,000 रु० का वार्षिक परामर्श व्यय आवेगा। राजकोष पर इतना भारी धक्का डालने की सम्भावना को देखते हुए मैंने यह विचार त्याग दिया। किसी साधारण भवन में जाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य सादा जीवन व्यतीत करने का उदाहरण प्रस्तुत करने का था परन्तु यदि उसका परिणाम भारी अतिरिक्त व्यय आता था तो वह अपनाये योग्य नहीं था। इस संदर्भ में भरोजनी नावट्ट द्वारा हसी में यही गयी उक्ति किसी को भी स्मरण आ सकती है—कि गांधीजी को गरीब रहने के लिए राष्ट्र को काफी पैसा चुकाना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त बिलिंगटन क्रिसेंट एवम् व्यस्त मार्ग था जिस पर भारी आवागमन होता रहता था और ठीक सब्ब के पार 'रिज' था जिस पर घने वृक्ष लगे थे। यद्यपि वहां ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे राष्ट्रपति के जीवन को छतरा हो सके तथापि शरास्त्री तत्त्व राष्ट्रपति के लिए मूलतः स्थिति उत्पन्न कर सरकार

को उलझन में डाल सकते थे। इन परिस्थितियों में यह विचार कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन से किसी छोटे भवन में स्थानान्तरित हो जायें, त्याग दिया गया।

इस सदन में, यह सप्तेष में बताना उपयोगी होगा कि राष्ट्रपति भवन का कसे और किन उद्देश्यों के लिए उपयोग होता है। यह एक विशाल भवन है। यह शायद अनेको देशों के राज्याध्यक्षों के भवनों से भी बड़ा है। तथापि राष्ट्रपति अपने और परिवार के सदस्यों के लिए केवल कुछ या छह कक्षों (कमरों) का उपयोग करता है, जिन्हें (फैमिली यिंग) परिवार खंड कहते हैं। भवन का शेष भाग कार्यालय के विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहले, विभिन्न प्रकार के बड़ा विदेशों से आने वाले राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और उनकी सहायक मंडली के सदस्यों के उपयोग के लिए अलग रखे जाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं विदेशी उच्च अधिकारियों का आगमन एक सामान्य बात है, विशेष रूप से अक्टूबर से माघ माह तक। दूसरे, बड़ा विशाल कक्ष है जो कि विशेष अतिथियों के मनोरंजन कार्यक्रमों, औपचारिक सरकारी समारोहों जैसे नागरिक और सैनिक पद ग्रहण आयोजनों, राजदूतों द्वारा अपने अधिकृत सरकारी परिचय पत्र देने, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण का आयोजन करने हेतु सुरक्षित है। राष्ट्रपति द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी प्रतिनिधि मंडलों से भेंट करने के लिए भी अलग कक्ष हैं। प्रायः भारतीय तथा विदेशी प्रतिनिधियों के मध्य होने वाली संधियों पर राष्ट्रपति भवन में ही हस्ताक्षर होते हैं। भारत आने वाले विदेशी राज्याध्यक्षा से भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति भवन आते हैं, इसके लिए भी कमरे सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट सेक्रेटेरियेट, राष्ट्रपति का अपना कार्यालय और सेक्रेटेरियेट, राष्ट्रपति भवन के उपचर्चों तथा अचल संपत्ति की देखभाल रखने वाले विभाग भी स्थित हैं। यदि राष्ट्रपति दूसरे भवन में चला भी जायें तो व्यय में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि राष्ट्रपति भवन को इन समस्त कार्यों के लिए बनाये रखा होगा।

इस प्रकार राष्ट्रपति भवन जनता का भवन है जिसे अच्छी दशा में बनाए रखा चाहिए। इसे जिन विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे दृष्टि में रखते हुए इसका सुव्यवस्थित सुसज्जित करना चाहिए। इसमें मूलतः प्रश्न राज्य की गरिमा का है तथा इसे अच्छी दशा में रखने के विषय में विफायनशायी करना बुद्धिमानो नहीं होगी। इस भवन की अनेकों 'फिटिंग्स', गलतियों, फर्नीचर आदि पुराने हो चुके हैं और उनकी मरम्मत या नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। अच्छा हो, यदि हम यह कार्य बिना देर किए प्रारम्भ कर दें, साथ ही इस भवन की आन्तरिक और बाहरी दशा इसकी फिटिंग्स, फर्नीचर और साज-सज्जा पर भी निरन्तर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है ताकि यह भवन उन सभी समारोहों के अनुरूप बन सके जो इसमें आयोजित होते हैं। मैं यहाँ जो विचार प्रकट कर

रहा हूँ, वह आवश्यक परिवर्तनों सहित विभिन्न राज भवनों पर भी लागू होता है और इसके लिए पर्याप्त धारणा की व्यवस्था करनी होगी।

विदेशों में राज्यकीय यात्राओं के दौरान, मुझे भातों देशों में इसी प्रकार के भवनों को अत्यन्त भव्य स्थिति में देखने का अवसर मिला है। समानवाणी देशों में भी भवनों के पर्तोंपर, फिटिंग्स, साम साम्रा और उनसे रख रखाव में किसी प्रकार की वांछित कमी नहीं छोड़ी जाती। विदेशी अतिथियों के रहने के लिए भवन बना भव्य रख जाते हैं और सरकारी स्वागत के लिए प्रयोग नियोजन वाले विकास काल सर्वोत्तम रूप से परिष्कृत और सजे होते हैं, स्पष्ट है सामाजिक भवनों के रख रखाव पर धर्म में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाती है।

जयप्रकाश नारायण से प्रेरणापूर्ण संपर्क

वर्ष 1975 में, आपात स्थिति की घोषणा से कुछ पूर्व, जयप्रकाश नारायण ने हैदराबाद में एक सावजनिक सभा में भाषण दिया था। मैं उस समय हैदराबाद नगर में था। इसलिए मैं उस सभा में शामिल होने गया। मैं भीड़ में बैठा हुआ था कि मंच पर जे० पी० तथा अन्य लोगो के साथ बैठे हुए किसी व्यक्ति ने मुझे पहचान लिया और मेरी उपस्थिति के बारे में जे० पी० के कान में फुसफुसाया। वह मेरी ओर घूमे और मुस्कराते हुए मुझे मंच पर आने का आमन्त्रण दिया। दूसरो की भी यही इच्छा मालूम पड़ रही थी इसलिए मैं वहां चला गया। तब जे० पी० ने मुझसे सभा को संबोधित करने के लिए कहा। यद्यपि मैंने कभी यह आशा नहीं की थी कि ऐसा करने के लिए वहां जायेगा, मैंने उनके अनुरोध का पालन किया। मैं मुख्य रूप से सावजनिक जीवन में जो पतन आ गया है उस पर बोला। मेरे भाषण को भली प्रकार सुना गया।

उस समय जे० पी० जिसे वह 'संपूर्ण प्राप्ति' कहा करते थे, वे सबंध में अक्सर बोला करते थे। मुझे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि उनका इससे क्या आशय था, मैं पूरी तरह नहीं समझता था। जनता में विभिन्न अवसरों पर कहे गये उनके वाक्यों में मुझे यह ज्ञात होता था कि वे देश के राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में दूरगामी प्रभाव डालनेवाले परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि वे अधिक स्वच्छ राजनैतिक जीवन लाना चाहते थे। स्पष्ट था कि उन्होंने चुनाव प्रणाली में ऐसे सुधार करने का निश्चय कर लिया था जो हमारी विधान सभाओं को सच्चे रूप में जनता के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करनेवाली बना सके। उनका विचार था कि विधायकों को मतदाताओं से अनिष्ट सबंध बनाये रखने चाहिए और उनकी आवश्यकताओं तथा दृष्टिकोणों के प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिए। उनकी इच्छा थी कि कुछ परिस्थितियों में उन्हें विधान सभाओं से बाधित मुला सेने की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने एक ऐसे सच्चे गमानतावादी समाज की स्थापना के लिए आह्वान किया जिसमें जाति, समुदाय

22 नीलम सजीव रेहड़ी

जैसी बातों पर आधारित अन्तर और ऊँच-नीच न हो और सभी को आर्थिक लाभों में समान भागीदारी मिले।

अपने भाषणों में दूसरे जिस विषय की वह प्रायः चर्चा करते थे, वह था दल हीन प्रजातन्त्र।

मैं नहीं जानता कि कभी उन्होंने इस विषय पर अपने विचार विस्तार से रखे हो। तथापि कोई भी सैद्धांतिक रूप से उस रूपांतर का विरोध नहीं कर सकता था जिसे साने का प्रयत्न वे कर रहे थे। मुझे प्रायः आश्चर्य होता था कि उनके मन में जिन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को लाने की इच्छा है, उनको स्वीकार करने तथा उनके लिए काय करने को क्या जनता वास्तव में तत्पर है।

उन्होंने मार्च 1977 के चुनावों में विरोधी पार्टियों को एकजुट संगठित कर कांग्रेस के विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड़ने में जो ऐतिहासिक भूमिका निभायी वह लम्बे समय तक याद की जाती रहेगी। देश के इतिहास में उस क्षण एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता थी जो कांग्रेस को सफलतापूर्वक चुनौती दे सके क्योंकि यदि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी केन्द्र में सत्ताधीश हो जाती, वह और उनकी पार्टी यह दावा करती कि देश ने जून 1975 में लगाई गई आपातस्थिति की स्वीकृति दे दी है। अपने कमजोर स्वास्थ्य पर ध्यान न देते हुए, उन्होंने विस्तृत यात्राएँ की और आपातकाल के अघकार पूरा दिनों के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध जनमत को संगठित किया। यद्यपि जिस जनता पार्टी की उन्होंने नींव डाली थी वह अंत में बिखर गई तथापि इससे देश के सकलपूरा ऐतिहासिक क्षण में राजनैतिक जीवन को उनके द्वारा दिया गया योगदान धूमिल नहीं पड़ता।

जून 1977 या उसके आस-पास जबकि मैं लोकसभा का अध्यक्ष था, मैं एक सप्ताह के मध्यावकाश में जयप्रकाश नारायण से मिलने बम्बई जाना चाहता था जो कि अमरीका से अपना उपचार करवाने के बाद वापिस आये थे। मैंने विचार किया यह मुझे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को सूचित कर देना चाहिए। उनकी प्रति क्रिया जयप्रकाश नारायण के प्रति उतनी ही अनुदार थी जितनी कि उनके स्वयं के अनुपयुक्त। उन्होंने पूछा कि क्या जे० पी० को इतना अधिक महत्त्व देना मेरे लिये वास्तव में आवश्यक है। विरोधी पार्टियों को एक झंडे के नीचे लाने में जे० पी० की प्रमुख भूमिका को सभी मान चुके थे। यह भी सविदित था कि देसाई को प्रधानमंत्री बनाने में जे० पी० का हाथ था। तथापि तीन महीने से भी कम की अल्प अवधि में, देसाई यह झूल चुके थे कि देश और वह स्वयं जे० पी० के कितने श्रेणी हैं।

बार-बार दी जाने वाली 'डाइलिसिस' से जे० पी० को अत्यधिक कष्ट होता था। उनके साथ बम्बई में हुई अपनी भेंट की अवधि में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वे जीवित रहने की इच्छा त्याग चुके हैं। वास्तव में उन्होंने मुझसे कहा कि वे नहीं

राजा जी के आदर्श

दिसम्बर 1978 के प्रारम्भ में मद्रास में आयोजित सी० राजगोपालचारी की जन्म शताब्दी समारोह में मैंने बिना किसी पूर्व तयारी के आशु भाषण दिया। अपने भाषण में, मैंने राजनीतिज्ञों से विशेष रूप से जो उच्च पदा पर हूँ यह अपील की कि वे सावजनिक जीवन में नतिव मूल्यों को बनाये रखने के लिए राजा जी के उदाहरण का अनुकरण करें। मैंने बताया कि किस प्रकार राजाजी ने अपने पुत्र पुत्रियों को सदैव अपने सावजनिक जीवन से दूर रखा तथा किस भाँति उन्होंने जनता का सेवक होने के नाते किये जानेवाले अपने कृत्यों को प्रभावित करने के लिए अपने बच्चे को कभी अनुमति नहीं दी। मैंने यह भी संकेत किया कि किस प्रकार राजाजी ने पद पाने के लिए अपने सिद्धान्तों से कभी समझौता नहीं किया। मैंने कहा कि यद्यपि सावजनिक जीवन में मैं अनेकों से आयु में छोटा हूँ तथापि मैं उनसे राजाजी के उदाहरण का अनुसरण करने की अपील करने की स्वतन्त्रता ले रहा हूँ। मैंने आगे कहा कि हम सभी को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे सावजनिक जीवन से अलग रहें। वास्तव में, मैं स्वतन्त्र और स्पष्ट रूप से बोला परन्तु मेरा इरादा किसी पर साछन लगाना नहीं था।

प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई ने मेरे कथन पर अप्रसन्नता प्रकट की। उन्हें आश्चर्य हुआ कि देश में उस समय उच्च पदासीन व्यक्तियों के पुत्रों और रिश्तेदारों की गतिविधियों पर चल रहे विवाद के सदृश में क्या इस प्रकार की उक्तियाँ की कोई आवश्यकता थी? उन्होंने अनुभव किया कि यदि मेरे मन में किसी विशेष का नाम नहीं था फिर भी लोग अपने तरीके से अर्थ निकालेंगे। उनका निश्चित मत था कि मेरा भाषण भारत के उस राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं था जिस पर मैं आसीन था।

मैंने उनको स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अपने दोनों के लम्बे साथ और उसके बाद भी किस प्रकार मैं उन्हें सदैव बड़े भाई की भाँति मानता रहा का स्मरण दिलाया। तथापि मैंने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित में व्यक्तिगत सम्बन्धों

और कृतव्यो का पालन करने में जनता के प्रति उत्तरदायित्व के मध्य अंतर रखना आवश्यक होता है। मैंने जनता के बढ़ते हुए मोह भग और भ्रम भग का उन्नेत्र किया। हमने उनको दिये गये अपने वायद पूरे करने और जनता की आशाओं के अनुरूप बनने में अयायना दिखाई है। हमारे आदर्शों और कर्मों के बीच बहुत अंतर है। यद्यपि यह अंतर भूतकाल में भी था और यह मेरे विशिष्ट पूर्ववर्तियों को कष्टदायी हुआ था।

मैंने अपने पद के उत्तरदायित्वों और कृतव्यो को पूरा करने के निश्चय की पुन पुष्टि करते हुए कहा कि मैं सदैव प्रधानमंत्री को उनके कृतव्यो का पालन करने में उत्साहित करता, सलाह देता तथा सावधान करता रहा हूँ। मैंने उन्हें स्मरण दिलाया कि किस प्रकार मैं उनका ध्यान बार बार उनके कुछ निवृत्तियों लोगों के व्यवहार की ओर तथा उनके कार्यों द्वारा प्रधान मंत्री की छवि और प्रतिष्ठा को होने वाली क्षति की ओर दिलाता रहा हूँ।

मैंने उन्हें देश के शासन प्रबन्ध की दिशाहीनता और जनता के कल्याण-कारि कार्यक्रमा के कार्यचयन में होनेवाली देरी को स्पष्ट किया। मैंने उन्हें याद दिलाया कि किस भाँति मैंने अपने आप सर्वप्रधानिक उत्तरदायित्व को दृष्टि में रखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी सलाह दी। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा और न उन्होंने उन विषयों के प्रगति के बारे में बाद में सूचित किया जिनके बारे में मैंने उनको पहले बताया अथवा ध्यान दिलाया था। मैंने उनसे कहा कि भारत के राष्ट्रपति और उसके प्रधान मंत्री के मध्य यह एक असामान्य सम्बन्ध की स्थिति है।

मैंने कुछ विशेष विषयों के सम्बन्ध में उन्हें पुन स्मरण दिलाया जिनके अन्तर्गत मैंने उन्हें श्री शंकर एव रिटायर्ड जॉफीसर को अपना प्रधान सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) नियुक्त करने से सावधान किया था। शंकर ने अपने रिटायमेंट के बाद कम वर्षों में अनेकों व्यापारिक हितों के साथ सम्बन्ध बना लिए थे। यद्यपि प्रधान मंत्री का प्रधान सचिव बनने के उपरान्त उन्होंने उन हितों से अपने औपचारिक सर्व वास्तव में तोड़ दिये थे तथापि जनता के मन में उनका लंबी अवधि तक व्यापारिक हितों में सम्बन्ध रखने की स्मृति शेष थी।

मैंने दसई का ध्यान शंकर की ईरान यात्रा तथा विभिन्न मन्त्रालयों से सम्बन्धित विषयों में हस्तक्षेप करने से उत्पन्न विवादों की ओर दिलाया।

दूसरा विषय ईरान के शाह की भारत यात्रा थी। शाह ने अपनी यात्रा के दौरान व्यापारियों के एक समूह को विशेष महत्व देने का प्रयत्न किया था। उनके बाद श्री शाह की बहन भारत आयी। उन्होंने यह जिद्द की कि उन्हें और उनके दल का राष्ट्रपति भवन में स्थान दिया जाय। तब प्रधान मंत्री के पुत्र कांति देसाई ने असाधारण परिस्थितियों में तेहरान की यात्रा की थी। इन सबसे प्रेस, संसद तथा

अब स्थानों पर केवल विपरीत आलोचना ही हो सकती थी। जब मोरारजी देसाई स्वयं अमरीका की यात्रा पर जाते हुए दाबारा तेहरान जाने का विचार कर रहे थे, मैंने इन ईरानी सम्बन्धों पर अपनी अप्रसन्नता से उन्हें अवगत करा दिया था। मैंने उनसे इसके बाद कहा था कि अगर ईरान के शाह, अफगान की स्थिति पर उनसे वार्तालाप करने के इच्छुक हैं तो शाह को दिल्ली जाना चाहिए। एक वर्ष से भी कम अवधि में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा ईरान की दो बार यात्रा करना उनकी अपनी तथा भारत की महत्ता के अनुकूल नहीं है। इससे केवल उन विवादों को बल मिलेगा जो उनके प्रधान सचिव बी० शंकर और काति देसाई की ईरान यात्राओं से उत्पन्न हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने जुलाई 1977 अथवा उसके आस-पास आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री वेंगला राव को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने चत्तापल्ली के राजा की कुछ भूमि को भूमि परिसीमन अधिनियम (सैंड सीलिंग एक्ट) से मुक्त करने के दावे का पक्ष लिया था। यह विषय पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधिकारों के अंतर्गत था। इसलिए मैंने देसाई को स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री के लिए वेंगला राव को इस बारे में पत्र लिखना उचित नहीं था। यह देखने पर कि वेंगला राव को राजा का अनुरोध मानने में सकारण था, देसाई ने कुछ समय बाद डा० चेन्ना रेड्डी को जो कि वेंगला राव के बाद मुख्यमंत्री बने थे, पत्र लिखा। मैंने देसाई से इस पत्र व्यवहार के बारे में कहा और उसे देखना चाहा। देसाई उन पत्रों को मुझे भेजने के अनिच्छुक थे। यद्यपि मैं इन कागजातों को मंगाकर देखने और अपने अनुरोध का उनसे पालन करवाने पर दृढ़ रहने में अपने सवधानिक अधिकारों की सीमा में था, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता था। बाद में डा० चेन्ना रेड्डी ने स्वयं उन कागजातों का राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया। उस स्थिति में, जब कि पत्र जनता के समुख लाये जा चुके थे, मैंने मोरारजी देसाई से उन्हें मगवाया, उस समय उन्होंने मेरे अनुरोध का पालन किया।

एक बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वेंगला राव प्रधान मंत्री भवन में काति देसाई से मिलने के बाद मुझसे भेंट करने आये। वेंगला राव के अनुसार काति देसाई ने उनको सुझाव दिया था कि यदि वह उनके द्वारा बताये गए व्यक्ति को खदान का पट्टा दे दें, वह व्यक्ति उचित राशि देगा। जब मैंने मोरारजी देसाई को इस सब में बताया, उन्होंने यह कहते हुए कि वेंगला राव ने मुझसे अवश्य झूठ बोला होगा, इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं क्रोधित हो उठा, यहां तक कि मैंने उनमें कुछ उत्तेजना संतुष्ट की कि क्या उनके विचार से केवल काति देसाई एकमात्र सत्यवादी व्यक्ति है। धर जान के बाद प्रधानमंत्री ने अवश्य अपने पुत्र से यह प्रश्न पूछा होगा क्योंकि उन्होंने मुझे यह बताने के लिए फोन किया कि

मैंने जो कुछ कहा सत्य था।

अब मैंने उनको उस घटना की याद दिलायी। मैंने उनको यह भी बताया कि एक से अधिक अवसरों पर किस प्रकार मैंने यह स्पष्ट किया था कि उनके पुत्र के व्यापारिक सम्बन्धों और प्रधान मंत्री के सरकारी निवास पर दूसरे व्यापारियों से भेंट करने से सरकार तथा उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँच रही है। मैंने अपने द्वारा उन्हें बार बार दी गई चेतावनियों का ध्यान दिलाया कि उनके पुत्र के निकट और निरंतर व्यापारिक सम्बन्धों के बीच राजनैतिक विवाद का मुख्य विषय बनता जा रहा है। मैंने अनुभव किया कि इन विषयों के बारे में उन्हें सावधान करके मैंने अपना सवैधानिक उत्तरदायित्व पूरा कर दिया था।

देसाई के निरस्त्रीकरण सम्मेलन के विशेष सत्र में जाने से ठीक पहले, मुझे उस वक्तव्य की एक प्रति मिली जिसे उस काफ़ेस में देने का उन्होंने निणय लिया था। इस वक्तव्य में यह घोषणा भी सम्मिलित थी कि भारत परमाणु परीक्षणों को कभी नहीं करेगा। मैंने अनुभव किया कि हम आनेवाले पूरे समय के लिए अपना अधिकांश त्याग दें इसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसी घोषणा भावी सरकारों को ही केवल उत्तमन में नहीं बाल सकती बल्कि देश के हितों को भी हानि पहुँचा सकती है। इसलिए मैंने उनको लक्ष्मण सदेश भिजवाया कि वह इस विषय पर पुनर्विचार करें। उन्होंने तथापि वापस लौटने पर इस विषय में मुझसे बातचीत करने का कष्ट नहीं किया और न अपने वक्तव्य में किसी प्रकार का परिवर्तन किया। मैंने उनको दोबारा अमरीकी दूतावास के एक अधिकारी द्वारा भारत द्वारा ब्रिटेन से 'जगुमास' (विमानों) को खरीदने के निणय की निन्दापूर्ण-आलोचना के बारे में लिखा था, परन्तु उन्होंने उसका उत्तर देने की परवाह नहीं की। मैंने उनका ध्यान इन सभी झूठों की ओर आकर्षित किया।

यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार केवल उनके और देश के हित में पूरे विश्वास के साथ दी गयी सार्वक सलाहों की वह निरंतर उपेक्षा करते रहे मैंने उपर्युक्त सभी उदाहरणों को संक्षेप में दोहराया। मैंने उन्हें बताया कि जनता के सम्मुख दिए गए भाषण में मैंने तेजी के साथ गिरते और मिटते हुए नैतिक मूल्यों से उत्पन्न अपने मानसिक दुःख को अभिव्यक्त किया था। उनको मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार की राजनैतिक भूमिका निवाहन का मेरा कोई विचार नहीं है।

मोरारजी के प्रति निष्पक्षता रखते हुए मेरे लिए यह आवश्यक है कि पहले वर्णन किए गए सभी विषयों पर उनके दृष्टिकोण प्रस्तुत करूँ।

देसाई का अपने प्रधान सचिव (प्रिंसिपल सेक्रेटरी) के पद पर ऐसे व्यक्ति को चाहना पूर्णतः उचित था जिसको वह एक सबी अवधि से जानते थे, जिस पर वह भरोसा कर सकते थे, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता के लिए जाना जाता था और जिसकी योग्यता तथा स्तर ऐसा था जो प्रधान मंत्री के सचिवालय में आने-

वाही पेंचीदा समझाओ हो निपटा सकता था। शहर में यह योग्यतायें थी, उन्होंने उमका चयन कर लिया। नियुक्त होते ही शहर में उद्योग और व्यापार में अपने पूर्ववर्ती सम्बन्ध त्याग दिए, और जाने चयन पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती थी। मोरारजी जब प्रधान मंत्री बने जाने पुत्र कान्ति देसाई ने भी मनी व्यापारिक सम्बन्ध त्याग दिए थे और अभी वह उनके साथ रहने आयें थे। उनका पुत्र निजी रूप से एक नागरिक था और जब तक वह अपने पिता की शासकीय स्थिति में कोई गरवानुनी लाभ नहीं उठाता, उसे अपना जीवन अपनी रीति से व्यतीत करने का अधिकार था। उन्होंने याद दिलाया कि इस सिद्धांत की व्याख्या हम वय पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लोकसभा में उस समय प्रस्तुत की गई थी जब यह प्रथम बार विचार के लिए उठा था। सदन ने इसका नहीं माना था, जाना कि उनकी दृष्टि में उचित था। जहां तब बंगला और कान्ति की आपसी बान्धन का प्रश्न है, मोरारजी देसाई ने बताया कि उस समय वह एक गंभीर दुष्टता के द्वां स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे और उस समय की बात का बतगढ़ बनाना उचित नहीं। इसके अतिरिक्त उस समय अंग्रेजों का भी उपस्थित थे और कान्ति उनके सामने इस विषय की चर्चा नहीं छूड़ सकते थे। ईरान के सम्बन्ध में देसाई का तर्क था कि ईरान के शाह को अपने पक्ष में करने के लिए विशेष प्रयत्नों की, उनको भारत का समर्थन करने के लिए सहमत करने की, और पाकिस्तान के पक्षधर सत्ताह्वारों के प्रभाव को निष्पक्ष करने की आवश्यकता है। उनका लक्ष्य भारत के आर्थिक और राजनयिक लाभ के लिए शाह की मित्रता पाना था। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी हक्कर और घर को ईरान के शाह को अपना मित्र बनाने के लिए भेजा था।

देसाई का तर्क था कि उन्होंने सरकार के परमाणु परीक्षण से सम्बन्धित दृष्टि कोण की समझ के सम्मुख व्याख्या कर दी है। उस विषय पर उन्हें और कुछ नहीं कहना। उन्होंने बताया कि किस प्रकार विदेश मंत्रालय ने अमरीकी वाइसल जनरल के 'जगुभास' की खरीद की आलोचना के मसले को निपटाया और कसे राजनयिक ने उन शक्तियों का जो उसके द्वारा कहे बताये गए थे, अस्वीकार कर दिया। उन्होंने मेरे भाषण पर अपनी अप्रसन्नता को पुनः प्रकट किया।

मुझे मोरारजी देसाई के उत्तर से कोई सतोष नहीं हुआ लेकिन इस विषय को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की बुद्धिमानी नहीं थी। यह कहा जाता है कि 'याप' केवल किया ही नहीं जाना चाहिए वरन् 'याप' होना हुआ भी दिखाई पड़ना चाहिए। इसी प्रकार मावजिनिक जीवन में एक व्यक्ति को विशेष रूप से उच्च पदासीन व्यक्ति और उसके निकटवर्ती साथियों को इमानदार ही नहीं होना चाहिए वरन् उन्हें सभी के द्वारा इमानदार माना जाना चाहिए। उस पर किसी प्रकार के सन्देह का रच मात्र दाग नहीं होना चाहिए।

वास्तव में मोरारजी देसाई अंग्रेजी की इस लोकोक्ति से अपरिचित थे— सीज़र की पत्नी का सन्देह से परे होना आवश्यक है।

सन् 1989 का संवैधानिक संकट

सन 1979 का अंतिम आधा वर्ष मेरे पांच वर्षीय राष्ट्रपति काल का सबसे महत्वपूर्ण समय था। 5 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 की अवधि में देश ने अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रम देखा, जनता मरवार का पतन, लोकदल नेता चरणसिंह के मृत्यु में सरकार बनना (जो एक बार भी संसद के समुख आये बिना इस्तीफा देने के लिए विवश हो गई थी), लोकसभा का भंग होना, लोकसभा के लिए मध्यावधि निर्वाचन होना और इंदिरा गांधी का सत्ता में पुन आना। मुझे ऐसा संवैधानिक प्रश्नो के परीक्षण का सामना और निणय करने पड़े थे जो मेरे पूर्व-वर्तियों में से किसी को नहीं करना पड़े।

इस काल की घटनाओं का वर्णन करने से पूर्व क्या मैं विषयांतर कर उन घटनाओं पर प्रकाश डाल सकता हूँ जो 1977 के आम चुनावों के बाद घटित हुई। उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के मतदाताओं के निणयों में आश्चर्यजनक अंतर था। कांग्रेस पार्टी को उत्तर में पूरी तरह पराजय मिली यद्यपि दक्षिण में सबकुछ मिलाकर उसकी स्थिति अच्छी रही। जनता पार्टी को लोकसभा में जबदस्त बहुमत प्राप्त हुआ और उसने जनता की लोकप्रियता प्राप्त करते हुए सत्ता ग्रहण की।

देश के लिए सन् 1978 का वर्ष सभी प्रकार से अच्छा प्रारम्भ हुआ। सरकार भाग्यशाली थी क्योंकि सन 1977 में अच्छी मानसूनी वर्षा हुई थी और पर्याप्त खेती हुई थी। सन 1977-78 में विदेशी विनिमय की सुरक्षित राशि की स्थिति बहुत ठीक थी और जायिक स्थिति ऊपर उठनी दिखाई दे रही थी। देश में चारों ओर दिखाई देनेवाली सतोषजनक स्थिति ने संभवतया शासक दल में जात्मसंतोष की मनोदशा उत्पन्न कर दी और उसके विभिन्न गुटों के अंतर्विरोध अपने को प्रकट करने लगे। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की विधान सभाओं के आम चुनावों में, जो प्रायः कांग्रेस के मजबूत गढ़ समझे जाते हैं, पार्टी ने एक बार पुन फरवरी 1978 में उल्लेखनीय सफलता का रिकार्ड बनाया और केन्द्र में जनता पार्टी के शासन के बावजूद पूर्ण बहुमत प्राप्त कर दिखा दिया कि जनता उन राज्यों में अपना प्रभाव

वनान में असफल रही है। उत्तरी राज्यों में सन् 1978 में हुए लोकसभा के तीन उपचुनावों में, केन्द्र में शासित जनता पार्टी की हार हुई। इससे यह दिखाई देने लगा कि जिस पार्टी ने लोकसभा के सन् 1977 में हुए आम चुनावों में पूर्ण विजय प्राप्त की थी, अब मतदाताओं पर उसका प्रभाव कम होना प्रारम्भ हो गया है। दक्षिण में कोई प्रगति न करने और उत्तर में अपना प्रभाव कम होना चेतावनी पर जनता पार्टी ने कोई ध्यान नहीं दिया।

मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरणसिंह जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे जो लोकसभा में आम चुनाव जीतकर दोबारा आये। तीनों, सदन में जनता पार्टी के नेता और भारत के प्रधान मंत्री बनने के आकांक्षी थे। तथापि जयप्रकाश नारायण और जे० बी० हृदयलानी के प्रयत्नों से मोरारजी देसाई को इसके योग्य समझा गया। देश के तत्कालीन वातावरण में जयप्रकाश नारायण की सलाह के विरुद्ध कोई खुलेआम नहीं जा सकता था। अतः मोरारजी देसाई जो कि सदन में जनता पार्टी के निर्वाचित नेता थे, सब सम्मति से प्रधान मंत्री चुन गये। मन्त्रिमण्डल तक बनाने में अवरोध आए, जगजीवन राम और उनके एक दो अनुयायियों ने प्रारम्भ में सरकार में सम्मिलित होने से मना कर दिया था। जगजीवन राम का अपने निणय पर पुन विचार करने और अपने साथियों सहित सरकार में सम्मिलित होने के लिए जयप्रकाश नारायण के सशक्त निवेदन की आवश्यकता पड़ी। यह घटना पार्टी के उच्च नेताओं के उन खराब आपसी सम्बन्धों का पूरा प्रकटीकरण थी जो उसके शासनकाल में प्रायः बराबर रहे। उच्च नेताओं में आपसी कलह, चरणसिंह का मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देना और उनके उसमें पुन प्रवेश करने की रीति, तथा राजनारायण का मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र देना आदि से यह बहुत स्पष्ट हो चुका था कि जनता सरकार अपना पूरा कार्यकाल नहीं गुजार पायेगी। जनता पार्टी उन शक्तियों का सफलता से शिकार हो गई जो उसके विरुद्ध कार्य कर रही थी।

भारत का राष्ट्रपति होने के नाते मेरा उपयुक्त विवादों से कोई सम्बन्ध नहीं था। इन विषयों के बारे में मेरी सूचना के एकमात्र स्रोत समाचार पत्र थे।

जब लोकसभा ने अपना भानसून सत्र प्रारम्भ किया मैं उस समय भी हैदराबाद में था, लेकिन 10 जुलाई 1979 को दिल्ली लौट आया। विरोधी दल के नेता बाई० बी० चट्टान ने 11 जुलाई को मोरारजी देसाई के नेतृत्ववाले मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति भवन के अध्ययन कक्ष (स्टडी) में बैठे हुए मैंने उनका भाषण सुना। वह मुझे पारम्परिक से अधिक कुछ नहीं लगा। जनता का लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने से उसे इस प्रस्ताव को मतों द्वारा गिराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। तथापि पार्टी में फूट बलनवाली शक्तियाँ त्रियाशील हो उठी और राजनारायण द्वारा दिये गये नेतृत्व में उनके बाद सदस्यों का एक के बाद दूसरा समूह दल-बदल करने लगा। यह उत्सेह करना रोचक होगा

कि कैबिनेट मिनिस्टर जाज फर्नांडीजने, जिन्होंने 12 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव की बहुसंख्यक बहुसंख्यक सरकार के पक्ष में सन्ध्या भाषण दिया और उसकी उप-लब्धियों की सराहना की, उन्होंने दो दिन बाद अर्थात् 14 जुलाई को सरकार से इस्तीफा दे दिया ।

15 जुलाई की रात शाम को प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई मेरे पास आये और दो पत्र दिये । अपने प्रथम पत्र में उन्होंने कहा कि चार दिन पूर्व जिस समय लोक-सभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, सदन में जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत था परन्तु अब ऐसा नहीं है । यद्यपि अब भी वह लोकसभा में एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी है, देसाई ने आगे कहा कि वह अपना और अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र देना उचित समझते हैं । उत्तर में मैंने कहा कि मैं त्यागपत्र स्वीकार कर रहा हूँ परन्तु उनसे और उनके सहकर्मियों से मेरा अनुरोध है कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती, वे अपने पद पर रहें ।

अपने दूसरे पत्र में मोरारजी देसाई ने कहा था कि सदन में किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं है और जिसको भी नई सरकार बनाने का कार्य दिया जाएगा उसे दूसरी का सहयोग लेना पड़ेगा । जिस जनता पार्टी के वह नेता हैं, वह अब भी लोक-सभा में एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी है और उसे स्थानापन्न मंत्रिमंडल को बनाने की संभावना के लिए प्रयत्न करने का अधिकार है । उन्होंने आगे जोड़ा "इसलिए, मैं सलाह दूंगा कि उसे ऐसा करने के योग्य समझा जाए । पार्टी का नेता होने के नाते मैं अपने प्रयत्नों के परिणाम से आपको शीघ्र-से-शीघ्र सूचित करूंगा ।" मैंने उन्हें तब उत्तर दिया कि यदि उन्हें बहुमत की सहायता पाने का विश्वास है तो वैसे करने के लिए वह जो भी कार्य करना आवश्यक समझते हैं उसे करने और अविश्वास प्रस्ताव को हटाने को स्वतंत्र है तथा उन्हें त्यागपत्र देने का कोई कारण नहीं । उनके त्यागपत्र से अविश्वास प्रस्ताव व्यर्थ हो जायगा और वे लोकसभा में शक्ति परीक्षण से मुक्त हो जायेंगे । त्यागपत्र देने के तत्काल बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रण मागकर वह समय और सहायता पाना चाहते थे । मैंने यह विचार किया कि जिस व्यक्ति ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के बजाय अभी अभी अपना त्यागपत्र दिया है उसे दोबारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना अनुचित होगा ।

आगामी दो दिनों में देश की सभी राजनैतिक विचारधाराओं और सम्मतियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले राजनैतिक पार्टियों के नेतागण मुझसे मिलने आये । मैंने उनके दृष्टिकोण और सलाहें सुनी । कुछ दूसरों से जो मुझसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले उनके भी मुझे पत्र मिले ।

हमारी सदन में इस प्रकार की स्थिति पहले कभी नहीं पैदा हुई थी और मेरे पास अनुकरण करने के लिए कोई पूर्ववर्ती उदाहरण नहीं था । दूसरा कदम उठाने का निश्चय करने से पूर्व मैंने इस विषय पर अत्यन्त गहराई से

मोरारजी देसाई के नेतृत्ववाली जनता पार्टी उनकी अपनी स्वीकृति के अनुसार जिस समय 11 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ पूरा बहुमत में थी परन्तु जब 15 जुलाई को मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दिया उस समय तक वह अपनी पहली वाली स्थिति खो चुकी थी। उसे जना व कोई भी कारण हो, पार्टी स बड़ी सज्ज्या में सदस्यों ने दल बदल कर लिया था जिससे वह सदन में अल्पसंख्या में रह गई थी, यद्यपि वह जता कि देसाई का दावा था अब भी जवेली बहुमत वाली पार्टी हो सकती थी। जिस समय सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोट चल रही थी, अनेकों सदस्यों ने जो अभी तक जनता पार्टी के सदस्य व उसमें त्यागपत्र दे दिया, इससे यह निष्कर्ष निकालना स्वाभाविक और उचित था कि अगर उस प्रस्ताव पर मतदान होता, व सब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते। मन्त्रिमंडल के त्यागपत्र के कारण प्रस्ताव पर मतदान होने की स्थिति नहीं आ पाई थी। यदि वह स्थिति आ जाती, सरकार हरा दी जाती। वास्तव में यह स्थिति बहुत ही स्पष्ट हो चुकी थी और यही कारण था जिसने मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित किया। दूसरे शब्दों में जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का संबंध है, सदन का बहुमत विरोधी पार्टी के नेता वार्डेन बी० चट्टाण का मनमथ करता और सरकार के विरुद्ध मतदान करता।

इन परिस्थितियों में, मैंने विचार किया कि विपक्ष के नेता वार्डेन बी० चट्टाण स सरकार बनाने के लिए वहां जाना चाहिए। उन मैंने उन्हें 18 जुलाई की रात को ऐसा करने के लिए निम्नलिखित शर्तों में आमंत्रित किया

जता कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में आपसे तथा देश की सभी राजनैतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनैतिक पार्टियों के नेताओं से विचार विनिमय किया। मेरी भली प्रकार विचार की गई सम्मति जोकि दूसरों के साथ हुई बातचीत से और भी पुष्टि हुई, वह यह है कि लोकसभा में विरोधी दल का नेता होने के नाते आप जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया और वही मोरारजी देसाई और उनके मन्त्रिमंडल के त्यागपत्र का कारण बना, अतः यह आपका नैतिक कर्तव्य है कि वर्तमान काम चलाऊ (क्वैर टेकर) सरकार का स्थान लेने के लिए शीघ्र से शीघ्र एक सुगठित और स्थायी सरकार बनाने की सम्भावनाओं को खोजें। लोकसभा में मन्त्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए आपके भाषण में राष्ट्र के प्रति आपकी कर्तव्य भावना का उल्लेख था। इसी कृतज्ञता का आग निवाहन के लिए आप से अनुरोध करता हूँ कि विषय को उसके तक संगत निष्कर्ष पर लाने का प्रयत्न करें। निस्संदेह इस सम्भावना के लिए प्रयत्न करते हुए आप किसी न किसी रीति से उन सहकर्मियों और साथियों का अपने साथ लेने का ध्यान रखेंगे जो हमारी जनता के कल्याण और सुख से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य और पृष्ठभूमि रखते हैं।

जब व 18 जुलाई संध्या को मुयसे मेट करने आये सरकार बनाने का प्रयत्न करने के लिए आमंत्रित करने का औपचारिक पत्र उनको दे दिया गया।

यह सामान्य रूप से एक नियम की भांति स्वीकार किया जाता है कि एक सरकार की हार और उसके त्यागपत्र पर विरोधी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बहुत समय से यह परम्परा रही है और अब एक नियम की भांति समझी जाती है। वर्तमान दृष्टान्त में यद्यपि सरकार को इस प्रकार से हराया नहीं गया था परन्तु मोरारजी देसाई के त्यागपत्र से ही यह स्पष्ट था कि यदि सरकार इस्तीफा नहीं देती, वह हरा दी जाती। यह स्थिति वास्तव में पार्टी की आन्तरिक फूट से उत्पन्न हुई थी न कि किसी सैद्धांतिक नीति पर विवाद के कारण। इसके बावजूद मेरे भक्तिष्क मन स्पष्ट था कि सर्वोत्तम उपयोगी तरीका विरोधी पार्टी के नेता को सरकार बनाने की सम्भावनाओं का प्रयत्न हेतु आमंत्रित करना था।

उस समय मोरारजी देसाई को उनकी सरकार के कुछ सदस्यों ने जो पत्र लिख उनमें ऐसा प्रकट होता है कि यदि उन्होंने जनता पार्टी के नेता पद से त्यागपत्र दे दिया होता और उनके स्थान पर जगजीवनराम नेता बन जाते तो वह सदन में बहुमत पाने में सफल होते। इसमें बलाग्न भी पार्टी में वापस आ जाते जो उस पहले छोड़कर चले गये थे। मैं महसूस करता हूँ कि मेरा पार्टी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था और न मेरा इस अनुमान के आधार पर कार्य करना उचित था कि यदि दूसरा आदमी पार्टी का नेतृत्व सम्भालेगा तो वह बहुमत प्राप्त कर लेगी।

श्री वार्ड० बी० चट्टाण ने 22 जुलाई 1979 का मुझे पत्र द्वारा सूचित किया कि उन्होंने अपने विचारोन्मुखी पार्टियों का मिलाकर सरकार बनाने का प्रयत्न किया था परन्तु सफलता नहीं मिली। उन्होंने आगे लिखा कि तथापि हमारे प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ पार्टियाँ और समूहों में सामंजस्य उत्पन्न हो गया है जो मेरे विचार से एक स्थायी और मजबूत सरकार बनाने में समर्थ होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस नयी स्थिति पर विचार करण और अपनी बुद्धिमत्ता से जो उचित समझेंगे वसा करेंगे।

इसी बीच चरणसिंह ने मुझे लिखा कि वह एक स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में है। उनको जनता (एस), कांग्रेस, बहुगुणा दल और समाजवादियों का एक दल अपना समर्थन देगा। उन्होंने जाय लिखा कि वामपन्थी विरोधी दला, अकाली पार्टी, और दूसरा ने अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्हें आल इंडिया जनता द्रविड़ मुन्त्र कजमम से भी समर्थन मिलने की आशा है। उन्होंने कांग्रेस (आई) द्वारा जनता के सम्मुख स्पष्ट की गई स्थिति का भी सदन दिया जिसके अनुसार वह किसी ऐसी सरकार का समर्थन नहीं करेगी जिसके घटक आर० एस०

एस० या जनसघ हो। उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया कि उनकी सरकार मजबूत और स्थायी होगी। उसी दिन चरणसिंह का दूसरा पत्र आया जिसमें वाई० बी० चन्हाण का पत्र संलग्न था। इस पत्र में चन्हाण ने उन्हें अपनी पार्टी का समयन देने का वायदा किया था। यह वायदा पार्टी की वर्किंग कमेटी में पारित प्रस्ताव के अनुसार था।

मैंने 18 जुलाई से 23 जुलाई की अवधि में ससद सदस्यों तथा अन्य लोगों के भी पत्र प्राप्त किये जिनमें तरह-तरह के सुझाव दिये गये थे।

इस स्थिति में एक ओर मेरे सम्मुख मोरारजी देसाई का दावा था कि जनता पार्टी अकेली सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी का नेता होने के नाते उन्हें ही सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए। दूसरी ओर दूसरे दलों से टूटकर बनी नयी पार्टी जनता (एस) के नेता चरणसिंह ये जिन्हें कांग्रेस (एस) का लिखित में दिया गया समयन प्राप्त था। बहुगुणा दल ने अपने पत्र में मुझे लिखित रूप से चरणसिंह को अपना समयन देने की सूचना भेजी थी। इसके अतिरिक्त ससद के कुछ सदस्यों ने भी मुझे लिखा था कि वे चरणसिंह को समयन देंगे।

लेकिन इन सबसे यह स्पष्ट नहीं होता था कि उनमें से किसको लोकसभा में बहुमत मिलेगा और वह एक स्थायी सरकार निर्मित करने में सफल होगा। इसलिए मैंने उन दोनों से लिखित रूप में अपने समयनों के नामों की सूची देने को कहने का निर्णय किया। मैंने प्रत्येक को बताना दिया कि मैं दूसरे से भी उसके समयनों की सूची मंगा रहा हूँ। मैंने 23 जुलाई को उन दोनों को इस आशय के पत्र लिखे और दो दिन का समय दिया।

लगभग इसी समय एक राजनयिक दल, कांग्रेस (आई) के नेता ने मुझे लिखा कि कुछ संविधान विशेषज्ञों के अनुसार अगर इंग्लैंड में मायता प्राप्त विरोधी पार्टी सरकार को हटाने में सफल हो जाती है और फलस्वरूप सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है तब विरोधी दल का यह कर्तव्य होता है कि वह सरकार बनाये या महाराणी को उसका कोई विकल्प बताये। चूंकि विरोधी पार्टी का नेता सरकार बनाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर चुका था परंतु उसने एक विकल्प सुझाया था, इसलिए मेरे लिए उस विकल्प को अपनाना आवश्यक था। उसने आगे यह तक रखा था कि मोरारजी देसाई को जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा है, किसी भी परिस्थिति में सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एवम ऐसे व्यक्ति को जो मतदान में हार चुका और पद से हट चुका है दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर ससद में भजने का समान होगा। यद्यपि कोई भी अपने पक्ष की पुष्टि के लिए संवैधानिक विशेषज्ञों की उक्ति को उद्धृत कर सकता है परंतु उस समय ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था कि विरोधी नेता द्वारा जो विकल्प रखा गया है उससे एक स्थायी सरकार बन सकेगी और सदन में बहुमत

का समर्थन प्राप्त कर गयेगी। परिस्थिति ऐसी थी कि दोनों नेताओं से अपने समर्थकों की विस्तृत सूचना प्राप्त रिये बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता था।

एक मित्र सदेस में 24 जुलाई को ससद के कांग्रेस (आई) नेता ने मुझे सूचित किया कि उनकी पार्टी ने चरणसिंह के नेतृत्व में बानेवासी सरकार को समर्थन देने का निर्णय लिया है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मैंने चरणसिंह और मोरारजी देसाई को दो दिन के अन्दर अर्थात् 25 जुलाई तक अपने समर्थकों की सूची भेजने के लिए कहा था। यद्यपि मैंने अपने पत्र में समय के बारे में नहीं लिखा था, आपसी समझ यह थी कि वे 25 जुलाई को 4 बजे सायं तक अपनी सूचियाँ दे देंगे। 24 जुलाई की रात को मोरारजी देसाई ने मुझे फोन किया और मुझसे एक दिन के लिए समय बढ़ाने को कहा। मैंने उनको बताया कि मुझे समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है अगर चरणसिंह भी इसी प्रकार समय बढ़वाना चाहें। जब चरणसिंह से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह समय सीमा बढ़ाने के इच्छुन नहीं हैं। अतः मैंने अनुमय किया कि केवल एक पार्टी को समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति देना अनुचित होगा। 25 जुलाई की सुबह प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के विशेष सचिव (स्पेशल सेक्रेटरी) टोनपे ने मेरे सचिव माहप्पा को मोरारजी देसाई की ओर से टेलीफोन पर समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। मेरे निर्देशानुसार मेरे सचिव ने उसको सूचित किया कि पहले बताये गये कारणों के फलस्वरूप यह सम्भव नहीं होगा और मोरारजी देसाई को पूर्व निश्चित समय सीमा का पालन करना चाहिए। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि मैं मोरारजी देसाई को अपने समर्थकों की सूची प्रस्तुत करने के लिए और अधिक समय देने के अपने आश्वासन से मुक्त गया। मैंने मोरारजी देसाई को पहले से स्पष्ट कर दिया था कि मैं समय सीमा बढ़ाने के लिए उसी दशा में सहमत हूँगा जबकि दूसरी पार्टी भी यह चाहे अन्यथा नहीं। इन परिस्थितियों में किसी का यह शिवायत करना कि इस विषय में मोरारजी देसाई को मैंने जो आश्वासन दिया था उसका मैंने पालन नहीं किया निराधार होगा।

25 जुलाई को 4 05 बजे सायं राजनारायण अपन दो साथियों सहित आए और उन्होंने मेरे सचिव माहप्पा को चरणसिंह के समर्थकों की सूची दी, जबकि टोनपे, मोरारजी देसाई के विशेष सचिव ने 4 25 सायं को मोरारजी देसाई के समर्थकों की सूची दी। राजनारायण ने कुछ विषयों पर मुझसे मौखिक रूप से बातचीत की। उन्होंने एक पत्र भी दिया जिसमें उन बातों का सारांश था जो उन्होंने मुझसे की थी। उसके बाद चरणसिंह का पत्र आया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के सचिव को मोरारजी देसाई द्वारा दी गई सूची में पुष्टि करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। दोनों सूचियाँ दिय जाने के बाद उनकी पुष्टि में किसी भी प्रमाण

को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। इस नियम का पालन न करने पर अनेको गम्भीर उलझने उत्पन्न हो जाएगी। दूसरे दिन यानी 26 जुलाई को मारारजी देसाई ने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने निम्नलिखित विषयों का उल्लेख किया था—

(अ) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस और जनता (एस) द्वारा बनाई जानवाला किसी भी सरकार का पूरा समयन देने का वायदा नहीं किया है और वह सदन में विराधी पार्टी के रूप में रहेंगे और अपना रवैया नई सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के आधार पर निश्चित करेगी।

(ब) कांग्रेस (आई) ने चरणसिंह को केवल तत्कालिक समयन देने का वायदा किया है, स्थायी नहीं। इसके अर्थ यह हुआ कि वह चरणसिंह की सरकार को प्रत्यक्ष विषय के गुणों के आधार पर समयन देगी।

(स) चरणसिंह द्वारा कांग्रेस के पूरे समयन का दावा सही नहीं है क्योंकि जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, पार्टी के करल प्रदेश के सदस्य चरणसिंह का समयन नहीं देंगे।

(द) अकाली दल न निष्पक्ष रहने का निष्कर्ष लिया है। अतः यह नहीं सोचा जा सकता कि वे चरणसिंह का समयन करेंगे।

वह चाहते थे कि मैं अपना निणय लेने में पूर्व उपयुक्त बातों को ध्यान में रखूँ।

इसी दौरान सदन के कुछ सदस्यों ने मुझे लिखित रूप में सूचित किया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके नाम मारारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में सम्मिलित किए गये हैं और उन्होंने वास्तव में चरणसिंह को समयन देने का निणय लिया है। इसी प्रकार कांग्रेस के पांच सदस्यों ने मुझे लिखकर सूचित किया कि उनकी पार्टी द्वारा चरणसिंह का समयन देने का निणय सब सहमत नहीं है और उन्होंने मारारजी देसाई का समयन देने का निणय लिया है। एच० बी० कामरा तथा तीन अन्य ने एक सम्मिलित पत्र मुझे लिखा। इसमें उन्होंने यह तक प्रस्तुत किया कि चरणसिंह का समयन देने वाला मैं उन व्यक्तियों के वज्राय जो एक सामान्य कार्यक्रम या नीति पर चलते हैं, इस विभिन्न मतों वाले समूह में और ऐसे गठबंधन से कोई भी मजबूत या स्थायी सरकार नहीं बन सकती। इसके विपरीत जनता पार्टी द्वारा दी गई सूची में 219 ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जो सदन के अंदर और बाहर एक गुट के रूप में एक समान नीति तथा कार्यक्रम के आधार पर कार्य करते हैं और पार्टी चरणसिंह की तुलना में कहीं कम बाहरी समयन पर आधारित है। उनकी मायता थी कि इन परिस्थितियों में सरकार बनाने के लिए जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहिए। अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार के विचार लिखे थे। मधु लिमये ने 26 जुलाई को मुझे लिखा कि कुछ लोगों ने पहले जनता पार्लियामेंटरी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था पर बाद में उनका अपना निणय और

समयन बदल कर मोरारजी को देने के लिये मना लिया गया। उन्होंने "संसद सदस्यों द्वारा अपना समयन एक के बाद दूसरे को, दोनों पक्षों को देने" और "राष्ट्रपति द्वारा उनको यह जानने के लिए बुलाना कि वे वास्तव में किस पक्ष की ओर हैं" पर अपना दुश्च प्रवट किया। उन्होंने आग्रह किया कि मैं शीघ्र से शीघ्र अपना निणय किसी पक्ष में ले लू।

मैं भी चाहता था कि दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री की शीघ्र से शीघ्र जांच कर ली जाये। राजनारायण ने सुझाव दिया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के समयकों की सूची दे दी जाये। मोरारजी देसाई के प्रतिनिधि ने भी इस सुझाव का समयन किया। मैंने वगैरह किया। पुन दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की स्वीकृति से मैंने उन लोगों के नाम बांट दिये जो दोनों सूचियों में थे। मेरे मन्त्रिपरिषद् तथा लोक सभा अधिकारियों की सहायता से दोनों सूचियाँ का सावधानी से निरीक्षण करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि चरणसिंह की सूची में 24 का बहुमत है।

यह सुझाव भी दिया गया कि सदस्यों की बदलती हुई पार्टें भक्ति को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रपति के लिए यह उचित होगा कि वह यह निणय करने के लिए कि कौन सा सदस्य बहुमत रखता है, खुद लोकसभा के नाम अपना सदेश भेजें। लेकिन इन सुझावों में यह ठीक से नहीं उताया गया कि यह किस प्रकार किया जाय। यदि उक्त प्रक्रिया अपनाई जाती तो संसद सदस्यों के सम्मुख यह प्रश्न स्वाभाविक रूप में उठ खड़ा होता कि उनकी पसंद केवल चरणसिंह और मोरारजी तक ही सीमित है अथवा किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा दावा करने पर उसे भी इसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस प्रकार की प्रक्रिया इससे पूर्व कभी नहीं अपनाई गई थी। मैं इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट था कि यह प्रक्रिया अनदेखी उलझनों को उत्पन्न कर सकती थी और इसीलिए मैं इस पर कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं था।

उस समय कुछ आलोचकों ने यह तर्क दिया था कि दोनों नेताओं से अपने-अपने समयकों की सूची मागने की प्रक्रिया को अपना कर, मैंने अपने उस मित्र को त्याग दिया जो सन 1967-69 की अवधि में लोकसभा के अध्यक्ष (स्पीकर) रूप में मैंने पुष्ट किया था। स्मरणीय है कि उस समय कुछ राज्यों की सरकारों में बहुत अस्थायित्व चल रहा था विधान सभा के सदस्य प्रायः अपने दल उदल लिया करते थे। फलस्वरूप उनकी अवमर ऐम आन थ जब यह सन्देह उठता था कि कोई मुख्य मंत्री विधान सभा में बहुमत रखता है या खाली है। राज्यों के राज्यपाल (गवर्नर) को प्रायः ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ता था। इसी पृष्ठभूमि में प्रिसाईडिंग ऑफिसर की तृतीयवीं काफ़ेस अप्रैल, 1968 में हुई थी। लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर) होने के नाते मैंने इस सभा की अध्यक्षता की थी। अपने

अध्यक्षीय भाषण में मैंने कहा था —

किसी भी परिस्थिति में यह निणय राज्यपाल (गवर्नर) पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि कोई मुख्य मंत्री विधान सभा में बहुमत रखता है या नहीं, चाहे विधान सभा के सदस्य राज्यपाल को लिखकर ही क्यों न दें। इस विषय में निणय करने का परम अधिकार विधान सभा का ही है।

यह दोष लगाया जाता है कि मैंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 1979 में, उन्हीं सिद्धांतों की पूरी तरह अपेक्षा कर दी जिनकी मैंने लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सन् 1968 में तक द्वारा पुष्टि की थी। यह आलोचना स्थितियों के उस स्पष्ट विभाजन पर ध्यान नहीं देती जिन पर मैंने सन् 1968 की कॉफ़ेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रकाश डाला था और जिनका मुझे भारत का राष्ट्रपति होने के नाते सन् 1979 में सामना करना पड़ा। अपने अध्यक्षीय भाषण में मैं एक ऐसी स्थिति के बारे में विचार प्रकट कर रहा था जिसमें पहले से ही एक मुख्यमंत्री पद पर आसीन था। यदि उसके पद पर बने रहने के दावे को चुनौती इस तक पर दी जाती है कि वह विधान सभा में अपना बहुमत खो चुका है और राज्यपाल (गवर्नर) के सम्मुख यह माग आती है कि वह उसे त्यागपत्र देने के लिए विवश करे अथवा त्यागपत्र देने से इकार करने पर उसे हटा दे तो ऐसी स्थिति (गवर्नर) में राज्यपाल को क्या करना चाहिए? मैंने कहा था कि राज्यपाल को राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होने के नाते अपने ऊपर यह निणय करने का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहिए कि वास्तव में मुख्यमंत्री राज्य विधान सभा में अपना बहुमत खो चुका है। मैंने सुझाव दिया था कि राज्यपाल को यह प्रश्न विधान सभा में ही हल होने के लिए छोड़ देना चाहिए। मेरा अब भी वही मत है। लेकिन सन् 1979 में जो समस्या उठी वह भिन्न थी। मन्त्रिमंडल त्यागपत्र दे चुका था और विरोधी नेता जिससे सरकार बनाने का प्रयत्न करने के लिए कहा गया था, उसने कुछ समय बाद ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। उसने ऐसा करते हुए जिस विकल्प का संकेत दिया था, वह चाहे जिस भाषा शैली में था उसका अर्थ धारणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना था। दूसरी ओर त्यागपत्र दे चुका प्रधान मंत्री था जो सबसे बड़ी पार्टियों का नेता होने के रूप में सरकार बनाने के अधिकार का दावा कर रहा था। संवैधानिक रूप से सरकार बनवाना मेरा कर्तव्य था। यह हर प्रकार से पूरी तरह मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं उन दो विकल्पों में से किसको चुनूँ, यह एक ऐसा उत्तरदायित्व था जो मैं संविधान द्वारा बनायी किसी संस्था को नहीं दे सकता था। मेरे द्वारा किया जाने वाला ऐसा कोई भी प्रयत्न अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना करना होता।

अपने इस निणय के संबंध में मैंने एक बार कहा था कि मैंने अपनी अन्तर्त्मा के निर्देश अनुसार कार्य किया था। कुछ लोगों ने मेरे इस वक्तव्य की आलोचना

की ओर कहा कि मेरे निणय को मेरी अर्थात्मा से नहीं घरन् सविधान से निर्देशित होना चाहिए था। मेरे वक्तव्य का अर्थ यह था कि निणय लेते हुए मैंने स्थिति पर निष्पक्ष और वस्तुगत दृष्टिकोण से विचार दिया था और मेरे ऊपर जो कर्तव्य छोड़ा गया था उसे मैंने अपनी सम्पूर्ण योग्यता और न्याय के साथ किया। उस समय भी और अब भी मैं नहीं समझता कि मैंने कोई काय सविधान के विरुद्ध किया।

जैसा कि पहले कहा है, मैंने पाया कि चरणसिंह को लोकसभा में मोरारजी देसाई से अधिक बहुमत प्राप्त था। इसलिए मैंने उन्हें सरकार बनाने के लिए 26 जुलाई को अपराह्न आने का संदेश भेजा। मैंने अपने संदेश में आगे लिखा— मुझे विश्वास है कि सर्वोच्च जनतांत्रिक परम्पराओं और स्वस्थ सहमति की स्थापना के हितों के अनुसार आप शीघ्राति-शीघ्र प्राप्त अवसर पर लोक सभा में अगस्त 1979 के तीसरे सप्ताह तक विश्वास मत प्राप्त करेंगे। इसमें साथ ही मैंने मोरारजी देसाई को अपने निणय की सूचना दे दी।

28 जुलाई को मैंने चरणसिंह को प्रधानमंत्री पद तथा अन्य मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। चह्वाण को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में आने से पार्टी में वैचारिक अन्तर पड़ जाने के कारण नहीं आये। पार्टी के मनोनीत सदस्यों को दूसरे दिन मन्त्रि पद की शपथ दिलवाई गई। प्रधान मंत्री न शीघ्र ही अपने मन्त्रि मंडल का विस्तार करने की आवश्यकता अनुभव की और बाद में अतिरिक्त सदस्य मन्त्रिमंडल में नियुक्ति किये गये। मन्त्रिमंडल की सलाह पर मैंने 6 अगस्त को एक आदेश जारी कर संसद के दोनों सदनों को 20 अगस्त को आमन्त्रित किया।

20 अगस्त और उसके बाद की घटनाओं का वर्णन करने से पूर्व मुझे उस विषय के बारे में बताना है जिसकी उस समय आलोचना की गई थी। जब मैंने चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया था, मैंने उनसे लोक सभा का सत्र शीघ्र बुलवाने की आवश्यकता पर बल दिया था ताकि चरणसिंह की सरकार विश्वास मत प्राप्त करे। मैं इससे पूर्व ही संदर्भित जगह दे चुका हूँ। चरणसिंह को लोकसभा का सत्र शीघ्र बुलाने की सलाह को उनके द्वारा सरकार बनाने की एक शत का रूप माना गया और कुछ आलोचकों ने खुले आम मेरी इस सलाह देने के औचित्य पर अपना संदेह प्रकट किया। मेरा कथन है कि कोई भी शत थोपी नहीं जा सकती और वास्तव में उस सलाह का अर्थ किसी भी तरह शत नहीं था। सविधान के अनुसार मन्त्रिमंडल के द्रुम, सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, और राज्यों में विधान सभा के प्रति। राष्ट्रपति या राज्यपाल का किसी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करते समय कुछ भी अनुमान हो, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री और उनके साथी अपने पद पर तभी तक रहने की आशा कर सकते हैं जब तक वे लोक सभा या विधान सभा में जैसा भी उदाहरण हो, बहुमत रखते

हो। जब आम चुनावों के परिणाम स्वरूप कोई एक पार्टी अपना पाटियो का गठ बंधन बहुमत प्राप्त करता है और उसका नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का पद धारण करता है तथा सरकार बनाता है, तबे में उसका सदन में बहुमत होने पर सत्तेह करने की गुंजाइश नही होनी और स्थिति स्पष्ट होती है। तथापि चरणसिंह ने जिन परिस्थितियों में अपना पत्र ग्रहण किया और अपना जो भारी समर्थन दिख साया उसको ध्यान में रखते हुए यह जानना आवश्यक था कि क्या वह लोकसभा में अपना बहुमत रखने में समर्थ रहें। इसलिए मैंने उह प्रारंभ में ही लोकसभा का सत्र शीघ्र आमंत्रित करने की गलाह दना आवश्यक तथा उचित समझा।

लोक सभा सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस (आई) ने, जो चरणसिंह के मतृत्व में बनने वाली सरकार को समर्थन देने के लिए सहमत हो गई थी अपना समर्थन वापस लेने का निर्णय कर लिया। उसके बाद चरणसिंह ने विचार कि अब सदन में बहुमत पाने की कोई आशा नहीं है। 20 अगस्त की सुबह हुई बैठक में चरण सिंह और उनकी कैबिनेट ने राष्ट्रपति को अपने त्यागपत्र देने तथा "जनता से नया आदेश प्राप्त करने" की सलाह देने का निर्णय लिया। इस प्रकार चरणसिंह और उनके मंत्रिमंडल ने सत्ता का एक बार भी सामना किए बिना त्यागपत्र दे दिया।

उसके बाद दो दिन तक मुझे अनेक व्यक्ति भेट करने आए। शाम सत्र के "प्रतिपक्ष" सदस्यों और समूहों के नेताओं ने आगामी कदम उठाने के बारे में अपने अपने दृष्टिकोण और सलाह प्रस्तुत की। इस विषय पर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और समूहों ने, वकीलों और पत्रकारों ने मुझे अपने विचार भेजे। मेरे सम्मुख सम्भावित विचार थे (अ) लोकसभा का भंग करना आम चुनावों का प्रबंध कर (ब) विरोधी दल के नेता जगजीवन राम की सहायता से नयी सरकार बनवाने का प्रयत्न कर।

इससे आगे का प्रश्न यह था कि यदि लोकसभा भंग कर दी जाती है और नये चुनाव करने का आदेश दिया जाता है तो उस समय में सरकार चलाने के लिए क्या प्रबंध किया जाय।

चरणसिंह के त्यागपत्र और आम चुनाव द्वारा जनतापक्ष का समाचार फला, जगजीवनराम ने जो उस समय जनतापार्टी और लोक सभा में विरोधी दल के नेता बन गए थे मुझे 20 अगस्त का लिखा कि वह लोकसभा के बहुमत से समर्थित स्थायी सरकार बनाने की स्थिति में हैं और उह सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उ होने लिखा कि यह प्रश्न कि चरणसिंह को लोक सभा में बहुमत प्राप्त था, सदैव सदैव युक्त रहा था और वास्तव में इसी कारण उह मेरे द्वारा विश्वास मत प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस प्रकार चरणसिंह लोकसभा का एक बार भी सामना किए बिना बहुमत न होने के कारण त्यागपत्र देने को विवश हुए थे। उन्होंने तक दिया कि केवल वही

मन्त्रि मंडल जो लोक सभा में अपना बहुमत रखता हो, राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है जिसका पालन करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। चरणसिंह और उनके मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह कि वे नए चुनाव करवाने का आदेश दें कोई महत्त्व नहीं रखती और उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। अन्त में उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

जनता पार्टी के प्रेसिडेण्ट चण्णेश्वर, मोरारजी देसाई की मन्त्रिपरिषद् (केबिनेट) के सदस्य मोहन धारिया तथा अन्य लोगों ने इस दृष्टिकोण के समर्थन में लिखा। लोकसभा के स्वतंत्र सदस्य भावलकर, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो चरणसिंह को समर्थन देने की अपनी पार्टी की नीति से असहमत थे और उसी विचार के पत्रकारों ने भी उसी दृष्टिकोण के अनुसार मुझे लिखा। उनका तर्क था कि उचित कार्य विधि यह होनी चाहिए थी कि मैं सरकार बनाने के लिए तरका-लीन विरोधी पक्ष के नेता जगजीवन राम को आमंत्रित करता जो लोकसभा में 200 से भी अधिक सख्या वाली सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे क्योंकि जब मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई का त्याग-पत्र दिया था उस समय विरोधी पक्ष के नेता चत्तान को उनके दल की सदस्य सख्या 75 थी, सरकार निर्माण करने के हेतु बुलाया गया था। लोकसभा के 102 सदस्यों के साथ कृष्णकांत ने जगजीवन राम के समर्थन में मुझे लिखा। अन्य तर्कों के अतिरिक्त उन्होंने लिखा था कि अगर जगजीवन राम को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया तो देश के सभी पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों को महान प्रसन्नता होगी।

जो लोग मेरे द्वारा दूसरा विकल्प अपनाने का आग्रह कर रहे थे उनके तर्कों को मैं क्रमशः दे चुका हूँ। अब मैं प्रमश उन लोगों के तर्कों दूंगा जिन्होंने दूसरा विकल्प प्रस्तुत किया था।

ऐसा करने से पूर्व मैं कुछ नए विकास पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जिसका वर्तमान सदर्भ में वर्णन करना रोचक रहेगा। एक राष्ट्रपति के नाते विकल्प सरकार बनाने की सम्भावना के लिए प्रयत्न करना मेरा कर्तव्य था। जगजीवनराम द्वारा कांग्रेस (आई) से समर्थन लेकर एक स्थायी सरकार बनाना सम्भव था। वास्तव में कांग्रेस (आई) ने कुछ शर्तों के साथ जगजीवन राम को समर्थन देने को कहा था। परंतु यह माना जाता है कि जगजीवनराम ने उन शर्तों को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए वह विचार त्याग दिया गया था और कांग्रेस (आई) के नेता जब मुझसे मिले उन्होंने मुझसे लोकसभा भंग करने के लिए कहा। मैंने उनसे अपना दृष्टिकोण लिखित रूप में भेजने का आग्रह किया।

चरणसिंह की मन्त्रिपरिषद् के विधि मंत्री ने मुझे 20 अगस्त को ही बता दिया था कि लोकसभा ने 532 सदस्यों में से 291 का बहुमत लोकसभा भंग करने के पक्ष में है, जिसमें जनता (एन) के 97 सदस्य, कांग्रेस (एस) के 75,

कांग्रेस (आई) के 73 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सवादी) के 22, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कळघम के 17 सदस्य सम्मिलित थे। उसी दिन मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महामंत्री (जनरल सेक्रेटरी) द्वारा भेजी गयी उनकी पार्टी द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति मिली जिसमें लोकसभा भग कर नए मध्यावधि चुनाव करवाने का पक्ष लिया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सवादी) के महामंत्री ने भी मुझे अपनी पार्टी द्वारा पारित नए चुनाव करवाने का पक्ष लेनेवाले प्रस्ताव की प्रति भेजी। सदन में कांग्रेस (आई) पार्टी के नेता ने 22 अगस्त को मुझे अन्य बातों के साथ यह भी सुझाव लिखा कि राष्ट्रपति को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा भग कर देनी चाहिए। चरणसिंह स्वयं जनता (एस) के नेता थे उनकी पार्टी की सहमति का इस सबंध में स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा सकता था। कांग्रेस (एस) के प्रतिनिधि जो चरण सिंह के मंत्रीमंडल में थे उनकी सहमति उस सलाह में शामिल थी जो राष्ट्रपति को लोकसभा भग करने हेतु दी गई थी। कांग्रेस (एस) के उन सदस्यों को छोड़कर जो पार्टी द्वारा चरणसिंह को समर्थन देने के प्रस्ताव में शामिल नहीं हुए थे, शेष सबके द्वारा लोकसभा भग करने की सहमति स्वतः स्वीकृत थी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कळघम जो कि मंत्रीमंडल में शामिल थी, उसकी भी स्वीकृति लोकसभा भग करने के पक्ष में स्वतः मानी जाने योग्य थी। इसके अतिरिक्त सदन के कुछ सदस्यों द्वारा भी सदन भग करने के लिए पत्र भेजे गए थे। सदन के कुछ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियाँ जिनमें लोकसभा भग न करने का संदेश था भी प्राप्त हुए।

प्राप्त होनेवाले विभिन्न विचारों और सम्मतियों से यह प्रकट होता था कि लोकसभा सदस्यों का बहुमत उसे भग करने के पक्ष में था।

राजनीतिक पार्टियों और सदन सदस्या के अतिरिक्त जनता के कुछ लोगों द्वारा भी सुझाव तथा सम्मतियाँ भेजी गयी थी। इनके अनुसार जनता कुछ जन प्रतिनिधियों द्वारा पिछले मप्ताहो बार-बार अपनी पार्टी बदलने से दुखी थी। इसलिए वे चाहते थे कि चुनाव फिर न कराये जाए।

मुझे जनता पार्टी के नए नेता जगजीवनराम के इस दावे का परीक्षण करना था कि वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में सफल होंगे और उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। उस समय उनकी पार्टी की शक्ति कुल 538 सदस्या में केवल 200 से कुछ ऊपर थी। कांग्रेस (आई) और जनता (एस) ने स्पष्ट रूप से जनता पार्टी द्वारा सरकार बनाये जाने का विरोध किया था। कांग्रेस (एस) भी इसी दृष्टिकोण की थी। दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा जनता पार्टी की सरकार का विरोध करते हुए लोकसभा भग करने का आग्रह किया गया था। आल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कळघम और मुस्लिम लीग भी इसी दृष्टिकोण

की थी। इसके अतिरिक्त सदन के कुछ सदस्यों ने मुझे लोकसभा भग करने का सुझाव लिखकर भेजा था। इन तथ्यों और सध्याओं को धृष्टि में रखते हुए मैं इसे निष्पक्ष पर पहुँचा कि दो सौ से कुछ अधिक के अपनी पार्टी सदस्यों की शक्ति से जगजीवनराम बहुमत समर्थित सरकार कठिनाई से भी नहीं बना सकते।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक माह से भी कम समय पूर्व जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से दिया दिया था कि वह लोकसभा में बहुमत रखने का दावा नहीं कर सकती। यह सत्य था कि इस बीच एक भिन्न व्यक्ति ने पार्टी का नेतृत्व सम्हाल लिया था परन्तु मैं अपने आपको इस बात से सन्तुष्ट नहीं कर सकता था कि नया नेता भी बहुमत का समर्थन जुटा पायेगा।

जब मोरारजी देसाई के द्वारा जुलाई में त्यागपत्र देने पर विरोध के नेता ब्रह्माण को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया गया था, कुछ लोग ने तक दिया था कि उसी के अनुरूप विरोधी पक्ष के नेता जगजीवनराम को चरणसिंह मन्त्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा देने पर सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए था। इस तक का सामना करने के लिए मुझे परिस्थितियों के एक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर जगजीवनराम को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाता और उनकी सरकार भी बहुमत प्राप्त न करने के कारण त्यागपत्र देने को विवश होती, जैसा की पूरी तरह सम्भव था, तो वैसी परिस्थिति में क्या कदम उठाया जाता? क्या उस समय भी यह आवश्यक नहीं होता कि तत्कालीन विरोधी पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाय? स्पष्ट है कि यह एक कभी समाप्त न होनेवाली प्रक्रिया होती।

मेरे सामने जितने विकल्प थे, उनके गुण दोषों के बारे में मैंने सावधानी पूर्वक विचार किया। स्थिति की वास्तविकता के वैद्रीय तथ्यों को मैं सक्षिप्त में प्रस्तुत करूँगा। सदस्यों द्वारा बड़ी सध्या में दल-बदल किए जाने के कारण जनता पार्टी अल्पमत में रह गयी थी और मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देने के लिए विवश होना पड़ा था। आमन्त्रित किए जाने पर विरोध पक्ष के नेता ने सरकार बनाने का प्रयत्न किया था पर असफल रहा था, तथापि उसने सलाह दी थी कि पार्टियों का ऐसा गुट उभर रहा था जो चरणसिंह के नेतृत्व में सरकार बना सकता है। मैंने त्यागपत्र दे चुके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और चरणसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से अपने को सन्तुष्ट कर लिया कि चरणसिंह को बहुमत प्राप्त है। इसी के अनुसार मैंने चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जो उन्होंने बनाई। वह शीघ्र ही त्यागपत्र देने को विवश हो गए क्योंकि एक महत्वपूर्ण समूह ने जिसने उन्हें समर्थन देने का वायदा किया था, अपना इरादा बदल दिया और एक माह से कम समय के अंदर उनका विरोध करना उचित समझने लगे। त्यागपत्र देते हुए चरणसिंह ने लोकसभा भग करने की सलाह दी। इस प्रकार वे मुझे ऐसी स्थिति

मे छोड़ गए जिसमे मुझे पहले बनाए गए विधियों मे मे किसी एक को चुनना था ।

जगजीवनराम को सरकार बनाने मे विरोध मे जो तर्क थे, उन्हें मैं पढ़ा बता चुका हूँ । चरणसिंह सरकार द्वारा दी गई सलाह से स्पष्ट था कि जनता पार्टी को छोड़ सभी राजनैतिक पार्टियाँ लोकसभा को भंग करवाना चाहती थीं । इन परिस्थितियों मे, मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि देश के राजनैतिक गतिरोध को समाप्त करने का एकमात्र उपाय लोकसभा भंग करने के पक्ष मे बहुमत द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट किए गए विचार को स्वीकार कर लेना है ।

इसी के अनुसार मेरे आदेश पर 22 अगस्त की शुबहु राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट सेनेटरी, प्रधानमंत्री का मन्त्री, राष्ट्रपति का सेनेटरी और अन्य उच्च अधिकारी लोकसभा भंग करने के आदेश का आवश्यक प्रारूप तैयार करने और इसके फलस्वरूप उत्पन्न होयाली परिस्थितियों का प्रबंध करने हेतु एकत्रित हुए ।

जिस समय उपर्युक्त अधिकारी काय मे व्यस्त थे । मेरे आमत्रण पर जनता पार्टी के जगजीवनराम और चन्द्रशेखर मुझसे मध्याह्न 11.30 बजे भेंट करने आए । मेरा विचार उनमे देश मे चल रही राजनैतिक स्थिति पर बातचीत करने का था । वार्तालाप के दौरान जब दोनों नेताओं ने जगजीवनराम के सरकार बनाने के दावा पर बल दिया, मैंने उनमे पूछा कि क्या किसी दूसरी राजनैतिक पार्टी का जगजीवनराम को समर्थन देने का वायदा किया है । जगजीवनराम ने उत्तर दिया अब कोई पार्टी शेष नहीं रही है, सब टूट चुकी हैं । अगर उन्हें सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाएगा, वह अपने समर्थकों की सूची प्रस्तुत करेंगे । मैंने उन्हें बताया कि क्या यही विधि नहीं थी जो मैंने इससे पूर्व अपनाई थी । मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया कि जनता पार्टी को छोड़कर शेष समस्त प्रमुख पार्टियों ने लिखित रूप मे लोकसभा भंग कर नए निर्वाचन करवाने का आग्रह किया है । यह भेंट लगभग पंद्रह मिनट तक चली । जगजीवनराम के पास मुझे बताने के लिए कोई नई बात नहीं थी । मैंने अनुभव किया कि मेरे जिस निषय के फलस्वरूप काय बाही प्रारम्भ हो चुकी है उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है । जब वे जा रहे थे, चन्द्रशेखर ने कहा कि यह मुझसे भेंट करने दोबारा आएंगे । मैंने उत्तर दिया कि जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनका सदैव स्वागत है । ये शब्द जो मैंने सही भावना से कहे थे इनका अर्थ यह था कि उन्हें मुझसे दोबारा भेंट करने के लिए शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं तथापि उनका सदैव स्वागत है । इससे मेरा आशय यह कदापि नहीं था कि मैं उस समय की राजनैतिक स्थिति पर कोई निर्णय लेने की जल्दी मे नहीं हूँ । दुर्भाग्यवश मेरे शब्दों का अर्थ गलत समझाया गया, जैसा कि भावी घटनाओं से ज्ञात होता है । मैं उन शब्दों से बसा अर्थ

निकालने की कभी कामना नहीं कर सकता था, जबकि मैं पहले ही निणय ले लिया था और इससे भी आगे जबकि मैंने उच्च अधिकारियों को अपने निणय को कार्यान्वित करने का आदेश दे दिया था और व आवश्यक 'नोटिफिकेशनस्', प्रेस विज्ञप्ति और दूसरी सामग्री बनाना प्रारम्भ कर चुके थे।

अब उन घटनाओं पर विचार करते हुए आश्चर्य करता हूँ कि मैंने उन्हें आमंत्रित ही क्यों किया। सही भावना से कहे गए मेरे कुछ शब्दों को जो रूप दिया गया वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था।

अपराह्न में एक प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित की गई जिसमें बताया गया था कि भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की धारा 85 के खंड (क्लाज 11) के उपखंड (बी) के अन्तर्गत लोकसभा को भंग कर दिया है। इसमें यह भी बताया गया था कि नवम्बर-दिसम्बर 1979 की अवधि में निर्वाचन होंगे। चुनावों के लिए प्रस्तावित समय कार्यक्रम में यह ध्यान रखा जाएगा कि वे संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और एंग्ला इंडियन समुदायों के लिए सुरक्षित 'सीट्स' के प्रावधानों की अवधि समाप्त होने से पूर्व किए जाएं। जब तक चुनाव नहीं हों जाते और उनके आधार पर नई सरकार नहीं बन जाती चरणसिंह का मन्त्रिमण्डल अपना पद भार समाले रहेगा। इस अवधि में सरकार ऐसे कोई निणय नहीं लेगी जो नवीन नीतियां शुरू करे या महत्वपूर्ण अंश में कोई नया व्यय करे अथवा मुख्य शासन या कार्यकारिणी सम्बन्धी निणय लें। राष्ट्रीय हित में नियमित रूप से होनेवाले काम को रूकने नहीं दिया जाएगा।

उस समय चरणसिंह मन्त्रिमण्डल को चुनाव होने तक अपने पद पर बने रहने के सम्बन्ध में कुछ सहाय प्रकट किया गया। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह तथा सहायता देने के लिये एक मन्त्रिमण्डल का होना आवश्यक है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अथ रीति से कार्य नहीं कर सकता। सबसे स्पष्ट बात उस समय तत्कालीन मन्त्रिमण्डल की सरकार चलाने के लिये पद पर बनाये रखना था। मन्त्रिमण्डल ने मुझे आश्वासन दिया कि चुनाव स्वतंत्र, सही और शांतिपूर्वक होंगे और मुझे आश्वासन पर सदैव करने का कोई कारण नहीं दिया।

मुझे विश्वास था चुनाव कमीशन तथा केन्द्र और राज्यों का शासन सभी स्तरों पर चुनावों को अनुशासित, शांतिपूर्ण और उचित रीति से करवाने का ध्यान रहेगा। इस घटना में यह विश्वास पूरी तरह बर्बाद हुआ था और लोक सभा के लिये 1979-80 शरद ऋतु में होने वाले चुनाव इतने अनुशासित, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण तथा उचित रीति से हुये जितने कि इससे पूर्व कभी हुए थे।

चुनावों के बाद जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी के प्रधान मन्त्रित्व में नयी सरकार बनी। इससे वह राजनैतिक अस्थिरता जो देश में 1978 के अंतिम आधे वर्ष में व्याप्त थी, समाप्त हो गई।

चरणसिंह से मतभेद

सन 1979 अगस्त से दिसम्बर तक की अवधि में जबकि लोकसभा भंग कर दी गई और चरणसिंह अभिरक्षक (केयर टेकर) सरकार के प्रधान मंत्री थे, मेरे लिये यह आवश्यक था कि मैं सरकार को समय समय पर नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न करने के लिये सलाह देता रहूँ। यह सत्य है कि संविधान में किसी अभिरक्षक (केयरटेकर) सरकार का सदन नहीं है, न वह पदभार सभालने वाली सरकार की शक्तियों पर चुनाव होने और उनके परिणामों के आधार पर सरकार बनने तक कोई पाबंदिया लगाता है। जब अगस्त 1979 के अन्त में, मैंने लोकसभा भंग करने और चरणसिंह को अपने पद पर उस समय तक बने रहने का आदेश दिया था जब तक चुनाव होकर उनके आधार पर नई सरकार नहीं बन जाती, यह स्पष्ट रूप से समझ लिया गया था कि चरणसिंह की सरकार कोई ऐसे नियम नहीं लेगी जो नयी नीतियों का प्रारम्भ करे या जिन पर महत्वपूर्ण घनराशि व्यय हो अथवा जो महत्वपूर्ण शासकीय या कार्याकारिणी परिवर्तन से सम्बंधित हो। इस के अतिरिक्त वैसे भी एक बार जब संसद भंग हो जाती है चुनाव आयोजित होने वाले होते हैं और चुनावों के बाद विधिवत सरकार बनने वाली होती है, यह एक स्थापित रीति है कि इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किये जाते। नीतियों में ऐसे परिवर्तन जिनके दूरगामी परिणाम हो, चुनाव घोषणा पत्र का अंग होना चाहिये और उनके अनुसार जनता का आदेश प्राप्त करने के बाद ही कार्या किया जाता चाहिए।

इस विषय में चरणसिंह मन्त्रिमण्डल द्वारा सघीय सरकार के नियंत्रण में होने वाली सेवाओं में पिछड़ी जातियों को संरक्षण देने का विचार एक महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन का था। चुनावों द्वारा जनता का आदेश पाने से पूर्व इसे क्रियान्वित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए था, यद्यपि एक संवैधानिक प्रावधान द्वारा सरकार को इस प्रकार का संरक्षण देने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण कुछ राज्यों में भी प्राप्त किया गया। परंतु इस विचार को शायद सरकार

की अदहनी विचार भिन्नता के कारण आगे नहीं बढ़ाया गया ।

समय-समय पर चुनावों में सुधार करने के सम्बन्ध में जो विचार रहे गये हैं, उनमें से एक सरकारी कोष द्वारा उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक सहायता देना है । यहा इस विचार के गुणों पर प्रकाश डालने का मेरा कोई विचार नहीं । मैं यहा केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वह दश के निर्वाचन सम्बन्धी कानून में एक मुख्य परिवर्तन था और उस पर जनता द्वारा पूरी तरह वाद-विवाद हो जाने के बाद उसे निर्वाचन कानून और प्रणाली के सम्पूर्ण सुधार के एक अंश रूप में लिया जाना चाहिए था । इसलिये जब चरणसिंह ने अध्यादेश जारी करवा कर यह विचार प्रियान्वित करवाना चाहा और वह भी जबकि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जा चुका था और उम्मीदवारों के नाम आ चुके थे, मैंने उनकी नाराजगी की हद तक प्रतिवाद किया । उन्होंने तक दिया कि उनकी सरकार विभिन्न कार्यों के लिये इस विशेष उद्देश्य की सुलता से वही अधिक बड़ी धनराशि खर्च कर रही है और उनकी इस पहल पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैंने उनको समझाया कि इसमें व्यय की मात्रा का नहीं बरन् दश के निर्वाचन कानून में मुख्य परिवर्तन करने का प्रश्न महत्वपूर्ण है । उनकी सरकार को इसे नहीं लाना चाहिये और वह भी जबकि चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो । मैंने आगे कहा कि यदि उनकी सरकार नहीं मानी, मुझे सरकारी आदेश को रद्द ही नहीं करना पड़ेगा बरन् अथ वठोर कार्यवाही भी करनी पड़ेगी । उन्होंने देख लिया कि उनके सामने उस विचार को त्यागने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है ।

उस अवधि में दूसरा उदाहरण जिसमें मैंने दृढ़ता अपनायी, एन बिदशी पार्टी के साथ लम्बी अवधि का वाणिज्य सम्बन्धी अनुबंध था । मैंने सम्बन्धित मंत्री को सलाह दी कि वह चुनाव तक बाई निणय न ले ।

एक दूसरा प्रस्ताव जिसके विरुद्ध उस अवधि में मैंने सलाह दी, न्यायिक नियुक्तियों से सम्बन्धित था । दिसम्बर 1979 के अन्त में, वास्तव में माह के अंतिम सप्ताह में मुझसे उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों की नियुक्तियों पर अपनी सहमति देने के लिये कहा गया । जैसा कि सभी जानते हैं, जनवरी 1980 के प्रथम सप्ताह में दश में चुनाव होने वाले थे और चुनावों के परिणामों के आधार पर महीने के मध्य तक नई सरकार पदासीन होने वाली थी । उन परिस्थितियों में कोई भी नियुक्ति करना विरोधी आलोचना को आकर्षित करना था । अतः मैंने सरकार को उसके विरुद्ध अपनी सलाह दी । मेरी सलाह स्वीकार कर ली गई और वह प्रस्ताव त्याग दिया गया ।

विदेश यात्राओं के प्रसंग

सोवियत रूस और बल्गेरिया में

राष्ट्रपति के पद पर तीन वर्ष तक कार्य करने के उपरान्त ही मैंने अपनी प्रथम सरकारी विदेश यात्रा की। मैं सितम्बर सन 1977 में अमरीका अपना आपरेशन द्वारा उपचार करवाने गया था। सितम्बर 1980 के अंत में, राष्ट्रपति पद धारण करने के तीन वर्ष से कुछ अधिक समय बाद मैं सोवियत यूनियन और बल्गेरिया की दो सप्ताह की राजकीय यात्रा पर चल दिया। इससे पूर्व मैंने दो बार केन्द्रीय सरकार के इस्पात मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री के रूप में सन् 1965 में और लोक सभा अध्यक्ष रूप में सन् 1968 में यात्राएँ की थी और उस विशाल देश को कुछ देखा था। इससे दस वर्ष पूर्व सन 1970 में वी० वी० गिरि ने राष्ट्रपति के नाते यात्रा की थी। यह सत्य कि राष्ट्रपति के रूप में मेरी प्रथम विदेश यात्रा सोवियत यूनियन की थी, उस महत्व को दर्शाता है जो दोनों देश पारस्परिक मित्रता को देते हैं। यात्रा में अमर लोगो के अतिरिक्त मेरी पत्नी तथा पेट्रोलियम मंत्रालय के केन्द्रीय मंत्री वीरेन्द्र पाटिल मेरे साथ थे। हम 29 सितम्बर 1980 को स्थानीय समय के अनुसार साय ८ बजे मास्को पहुँचे (भारतीय मानक समय से लगभग डेढ़ घंटे पूर्व), हवाई अड्डे पर सोवियत प्रेसीडेंट लेयनाइड ब्रेझनेव, प्रधानमंत्री तिरखोन्व, विदेश मंत्री ए० ग्रोमीकोव और उनके उच्च साथियों ने हमारा स्वागत किया। हम क्रैमलिन में ठहरे।

दूसरी सुबह मैंने वी० आई० लेनिन के स्मारक और अज्ञात सिपाहियों के स्मारक पर पुष्पहार अर्पित किया। इसके पश्चात् सोवियत प्रेसीडेंट के साथ मेरी लगभग सौ मिनटों तक विस्तृत वार्ता हुई। यह वार्ता शाब्द-फ़ानूसों और चमक दमक से सुशोभित क्रैमलिन के विशाल वक्ष (हाल) में हुई थी। दोनों पक्षों ने भारत सोवियत संबंधों के पहले से अधिक मजबूत होने पर प्रसन्नता प्रकट की और सहमति प्रकट की कि दोनों पक्षों को अपने सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का उपयोग विश्व

शान्ति की वृद्धि में करना चाहिए। सोवियत पक्ष ने अपनी अफ़ग़ानिस्तान सम्बन्धी सवविधित स्थिति की पुष्टि की और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया से सम्बन्धित विकास पर भारत की स्थिति और समझदारी की सराहना की। ब्रेझ्नेव ने भारत की तटस्थता नीति की बहुत प्रशंसा की।

साथ एक भोज में सोवियत प्रेसीडेंट ने कहा कि ईरान और ईराक को अपने विवाद मित्रता की भावना से हल करने चाहिए और जो विषय समझौते से शोध हल न हो पाए, उन्हें बाद में और अधिक उचित दिन हल करने के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का भी जिक्र किया।

मैंने अपने उत्तर में बताया कि किस प्रकार विज्ञान और तकनीकी से एक एक ओर मानव जाति को अपार लाभ पहुँच रहा है, वहीं दूसरी ओर किस प्रकार इसने कुछ देशों को अपार विनाश करने वाले नए अस्त्रों का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की है। मैंने कहा कि मुझे भय है कि विश्व शीतयुद्ध के नए युग की ओर बढ़ रहा है। मैंने आगे बताया कि इसके बावजूद भी भारत आशा करता है कि सदबुद्धि की विजय होगी और वह मानवता की रक्षा करेगी। मैंने ब्रेझ्नेव द्वारा यूरोप में तनाव कम करने के प्रयत्नों की प्रशंसा की। मैंने बताया कि सोवियत यूनियन ने जिसे कठिनाई से एक पीढ़ी पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ा था, आज दश के आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए अपने को समर्पित कर दिया है और इसलिए विश्वशान्ति के प्रति उसकी आस्था स्वाभाविक है। अन्त में मैंने भारत द्वारा सोवियत यूनियन के साथ अपने सम्बन्धों को दिए जाने वाले महत्व पर बल दिया।

मास्को यात्रा के अन्त में, मैंने सोवियत वासियों को टेलीविजन के माध्यम से सम्बोधित किया। इसमें मैंने बताया कि सोवियत यूनियन के प्रेसीडेंट से हुई मेरी वार्ता सौहार्दपूर्ण तथा उन घनिष्ट सम्बन्धों की विशेषताओं से संपूर्ण रही जो भारत और सोवियत संघ के मध्य हैं। मैंने घोषित किया कि दोनों देशों की आपसी मित्रता किसी के भी विरुद्ध नहीं है। हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रणाली में अन्तर होना बावजूद, हमारे दोनों देशों में घनिष्ट सहयोग से कार्य करने की इच्छा है और इसमें हम विश्वशान्ति के महान और समान सत्य से प्रेरित हुए हैं।

मैं यहाँ एक घटना का वर्णन करना चाहूँगा जिसने हमारी मास्को यात्रा के आनंद को कम कर दिया। यह मेरे द्वारा प्रथम अक्तूबर को ब्रेझ्नेव के सम्मान में दिए जाने वाले रात्रि भोज में उनकी अनुपस्थिति से सम्बन्धित थी। दूसरे दिन सोवियत विदेश मंत्री मुझसे भेंट करने आए और मेरे साथ करीब आधा घंटा गुजारा, और ब्रेझ्नेव की अनुपस्थिति के कारण बताते रहे। लेनिनग्राद की विदा होत समय प्राण काल ब्रेझ्नेव ने बिना पूर्व निश्चित कार्यक्रम के मेरे साथ लगभग चौराई घंटे तक भेंट वार्ता की। वास्तव में, यह मुझे शांत करने के लिए मेरे

साथ हवाई अड्डे तक आए। रात्रि भोज में अपनी अनुपस्थिति के कारण पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि उनको कुछ पूरा निश्चित आवश्यक कार्य करने थे और उनके एक घनिष्ठ मित्र और सहकर्मी के यहां मृत्यु शोक हो गया था जिसमें उन्हें व्यस्त होना पड़ा। यह कारण सन्तोषजनक नहीं लगते थे। कुछ स्रोतों ने बताया कि सोवियत प्रेसीडेंट प्रायः आने वाले विदेशी अतिथियों द्वारा दी गई दावतों में उपस्थित नहीं होते। यह भी मुझे स्वीकार योग्य नहीं लगा क्योंकि अगर ऐसा होता, मास्को में स्थित हमारे दूतावास को इसकी जानकारी अवश्य होती और उसने मुझे सूचित कर दिया होता। दूसरा कारण यह बताया गया था कि सोवियत नेता हमारी सरकारी वार्ता में मेरे इस कथन “अफगानिस्तान की बलशाली स्वतंत्र जनता के प्रति हमारी मित्रता की भावना” पर नाराज हो गए थे। मुझे सदेह है कि अफगानिस्तान से सम्बंधित मेरे कथन में कोई ऐसी बात रही हो जो पहले ही सरकारी रूप से इस समस्या के प्रति भारतीय दृष्टिकोण में नहीं बही गई हो। विशेष रूप से उद्धृत उपयुक्त शब्दों द्वारा कोई नाराजगी नहीं हो सकती।

सोवियत प्रेसीडेंट ने जिन्हें रात्रि भोज में मुख्य अतिथि होना था, यह सन्देश भिजवा दिया था कि वह नहीं आ सकेंगे, मैंने रात्रि भोज में नहीं जाने का निणय किया। केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री जो मेरे साथ गए थे, उन्होंने रात्रि भोज में आतिथेय की भूमिका निभाई।

तथापि इस घटना से हमारे दोनों दलों के आपसी सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

सोवियत राजधानी में अपने ठहरने की अवधि में मुझे मास्को राज्य विश्व विद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया।

मैं 3 अक्टूबर को मास्को से लेनिनग्राड के लिए विदा हुआ। मास्को हवाई अड्डे पर ब्रेझ्नेव, ग्रेमीकोव और अन्य लोगो ने मुझे विदाई दी। लेनिनग्राड में, मेरा स्वागत लेनिनग्राड कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव तथा केन्द्रीय पोलितब्यूरो के सदस्य, गिओर्गी रोमानोव ने किया। यहां के कार्यक्रम में अन्य कार्यों के अतिरिक्त लेनिनग्राड की रक्षा करने वालों के स्मृति स्थल पर पुष्पमांसा अर्पित करना, स्मोलनी जाना जहां से लेनिन ने अपनी 1917 की त्रांति का प्रारम्भ किया था, लेनिन स्मृति संग्रहालय देखना था। रोमानोव ने मुझे यह स्थल दिखलाए।

मैंने 5 अक्टूबर को वोल्गोग्राड (पहले स्टालिनग्राड) देखा। वहां लड़ी गई भयानक लड़ाइयां और वहां के लोगों के वीरतापूर्ण बलिदान ने द्वितीय विश्व युद्ध का नक्शा बदल दिया था और नाज़ियों की पराजय का प्रारम्भ किया था। मैंने नगर के पांच लाख लोगों के वीरतापूर्ण युद्ध और अपनी मातृभूमि की रक्षा में उनके अनुपम बलिदान के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैंने इससे पूर्व इस नगर का

दशम यूनियन केबिनेट मंत्री के रूप में किया था। मैं ऐतिहासिक स्थलों को, जिनमें नगर के मध्य में स्थित स्मृति स्तम्भ है, भी देखे। बाद में, मैं जियोर्जिया के तिविनिसी नगर गया, स्टालिन इंगी रिपब्लिक का निवासी था।

मेरे सम्मान में 6 अक्टूबर को जियोर्जिया की ससद और मंत्रिपरिषद ने एक रात्रि भोज दिया। रिपब्लिक की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव, प्रेसीडेण्ट तथा प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं से भी मेरी भेंट हुई। मैंने जब एक सप्ताह अवधि की अपनी यात्रा समाप्त की उस समय देश के जन प्रचार माध्यमों द्वारा मेरे आगमन की दो भिन्न सामाजिक व्यवस्था और दृष्टिकोण वाले देशों के मध्य आपसी सम्बन्धों तथा सहयोग के 'उज्ज्वल उदाहरण' के रूप में सराहना की गई।

7 अक्टूबर को मैं तिबलिसि से बुलगारिया की राजकीय यात्रा पर चल दिया। जैसे ही हम उस देश में पहुँचे, राष्ट्रपति के विमान की रक्षा के लिए बुलगारिया की वायु सेना के जेट्स विमान कुछ दूर तक चले। राजधानी नगर सोफिया पहुँचने पर मेरा स्वागत बुलगारिया के प्रेसीडेण्ट टोडोर शिवरॉव, प्रधानमंत्री टोडोरोव तथा अन्य राज्यकीय अधिकारियों ने किया। हवाई अड्डे से बोयाना स्टेट रजिडेन्स तक के बीच बीच लम्बे मार्ग में असाधारण संख्या में लोग हमारा हृषपूर्ण स्वागत करने के लिए आए थे। स्टेट रजिडेन्स जाने के मार्ग में (मेयर) नगर महापापद ने नगर निवासियों तथा नगर शासन की ओर से मेरा स्वागत किया। सदभावना और स्वागत के प्रतीक रूप में मुझे नमक और मिर्च के चूण के साथ रोटी का एक टुकड़ा खाने के लिए भेंट किया गया। किसी के साथ मिलकर रोटी खाना अच्छे साथी होने का पारम्परिक प्रतीक है।

बाद में मैं शिवकोव और बुलगारिया के अन्य नेताओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा आपसी सम्बन्धों पर एक घंटे से ऊपर तक वार्तालाप किया। दोनों पक्ष दूसरे युद्ध को छिड़ने से रोकने की परम आवश्यकता पर सहमत थे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के लिए शान्ति एवं अनिवाय और तटस्थानिक आवश्यक आवश्यकता है। बुलगारिया के नेताओं ने भारत की तटस्थ विदेश नीति की प्रशंसा की।

मैंने अपने सम्मान में दिए गए एक भोज में, समार के लोगों से आधिक्य अमानता की समस्या को और अधिक राजनयिक इच्छा शक्ति से हल करने का आग्रह किया।

दूसरे दिन मैंने मित्राणी विमित्राव का स्मारक देखा और पुष्पहार अर्पित किया। मैं राजनयिक मिशन के उच्च अधिकारियों से भी मिला और बुलगारिया में रिमन भारतीय राजदूत द्वारा दिए गए स्वागत समारोह में सम्मिलित हुआ। इसके बाद मैंने बुलगारिया के प्रेसीडेण्ट के सम्मान में एक रात्रि प्रीतिभोज दिया। इसके बाद के तीन दिनों की अवधि में मुझे स्टारा जामोरा और वर्ना के अनेकों दर्शनीय स्थल दिखताए गए। मैं रविवार, 12 अक्टूबर को नई दिल्ली वापस लौटे।

केन्या और जाम्बिया यात्रा

नई दिल्ली से मैं केन्या और जाम्बिया की राजकीय यात्रा पर शनिवार 30 मई, 1981 को रवाना हुआ। इस यात्रा मेरे साथ अमर सोनो के अतिरिक्त रेलवे के केन्द्रीय मंत्री वेदार पाण्डेय थे। मेरा स्वागत नरोवी में जोमो केन्याटा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केन्या के प्रेसीडेण्ट डेनियल अरप मोइ ने किया। हवाई अड्डे पर दिए गए अपने भाषण में मैंने कहा कि इस क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए पहली आवश्यकता सर्वोच्च स्तर पर दृष्टिकोणों का आपसी विनिमय करके तनाव कम करने की है। मैंने आगे कहा कि भारत और केन्या राष्ट्र निर्माण के क्षण में एक दूसरे के अनुभवों से काफी लाभ उठा सकते हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य और अधिक सहयोग बढ़ाने का मैंने आग्रह किया।

बाद में, मैंने केन्या के प्रेसीडेण्ट के साथ जाये घंटे में अधिक समय तक वार्तालाप किया। प्रेसीडेण्ट मोइ ने भारत की तकनीकी प्रगति की प्रशंसा करते हुए अनुभव किया कि केन्या जैसा विकासोन्मुख देश आत्मनिर्भर होने के प्रयत्नों में भारत के अनुभव से लाभ उठा सकता है।

शाम को प्रेसीडेण्ट मोइ ने मेरा सम्मान में भोज दिया। इस अवसर पर अपने भाषण में उन्होंने मुझसे कहा कि तीसरी दुनिया के देशों को अपने स्रोतों को मानव उन्नति के लिए एकजुट करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपने किसानों, अधिकारियों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को एक दूसरे के दश में भेजेंगे ताकि दोनों देश अधिक निकट आ सकें जिससे तकनीकी और व्यापारिक निवेश का स्थानान्तरण हो सके। उनके भाषण के उत्तर में, मैंने दोनों देशों के लिए विश्वमहत्त्व के विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला। सन 1971 के संयुक्त राष्ट्र सभ (UN) के प्रस्ताव के बावजूद भी भारतीय सागर शांति क्षेत्र घनन का बहुत दूर है। इसके विपरीत, समुद्रतटवर्ती तथा पश्चिम स्थित राज्यों की घोषित इच्छाओं के विरुद्ध महाशक्तियों की संयोजित शक्तियाँ बढ़ रही हैं। मैंने समार के विभिन्न भागों में बतते हुए विश्वव्यापी आपसी विरोध के प्रति भारत की चिन्ता प्रकट की। मैंने कहा कि इस आपसी विरोध का प्रभाव भारतीय सागर और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में भी अनुभव किया जा सकता है। दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता आन्दोलन, नामिबिया की स्वतंत्रता तथा रणनीति की अमानवीय प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष करने के प्रति मैंने भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया। मैंने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, पशुपत्ता और तटस्थ स्थिति को पूरा सम्मान दिये जाने का भी समर्थन किया। जहाँ तक पश्चिम एशिया का संबंध है मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक इजरायल को समस्त अरब क्षेत्र से पीछे जाने के लिए

विवश नहीं किया जाता, तब तब उचित और स्थायी शान्ति की कोई सम्भावना नहीं है।

दूसरे दिन रविवार था, मैं प्रसिद्ध भसाई मारा अभय वन देखन गया। यह नैरोबी के पश्चिम में 270 किलोमीटर दूर स्थित है। हम वन्य जीवन को देख सके इसलिए हमारी मोटरकारों का दल सूखी लबी घास से गुजरा। शेरों, हाथियों, जेबरा, जिराफ, जंगली भैंसों, दरियाई घोड़ों का पता लगाने के लिए बैया वायु सेना का एक विमान हमारे ऊपर नीची उड़ान भर रहा था और ऊपर स रडियो द्वारा हमारे मोटरकार दल को दिशा निर्देशन दे रहा था।

इस प्रकार हमने वन्य जीवन को बहुत निकट से देखा और मैंने अपने मेजबान को इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे एक ही निराशा थी कि मैं चीता नहीं देख सका जिसके लिए वह प्रदेश पूरे विश्व में विख्यात है।

सोमवार पहनी जून को मैं बैया के स्वशासन वार्षिक मदाराका दिवस समारोह का विशेष अतिथि बना। बैया के राष्ट्रपति ने सस्कृति, प्रतिभा और कुशलता के क्षेत्र में भारत और बैया के मध्य माध्यक तथा क्रियात्मक सहयोग विकसित करने का निश्चय प्रकट किया। अधिकारिक औपचारिकता की चिंता न करते हुए उन्होंने मुझे वहां विशाल सभ्या में उपस्थित श्रोताओं को भाषण देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया। हमने अपने भाषणों में नामिबिया से दक्षिणी अफ्रीका की तत्काल वापिसी की और उस देश को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की। हमने यह भी दोहराया कि किस प्रकार हमारे दोनों देशों ने रंग भेद की अमानवीय प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष में साथ साथ काम किया ताकि दक्षिणी अफ्रीका की जनता अपने मानवीय और राजनैतिक अधिकार प्राप्त कर सके।

उस दिन बाद में, भारतीय मूल के निवासियों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुआ। मैंने उनको बैया निवासियों की महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के साथ एकात्म होने की सलाह दी।

मैंने 2 जून, मंगलवार को नैरोबी से जाम्बिया की चार दिवसीय राज्यकीय यात्रा के लिए लुसाका प्रस्थान किया। विमान पर चढ़ने से पूर्व हवाई अड्डे पर दिए अपने संक्षिप्त भाषण में मैंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केन्या द्वारा की गई औद्योगिक प्रगति से मैं प्रभावित हुआ हूँ और हमारे दो देशों के बीच वृत्ता हुआ आर्थिक और तकनीकी सहयोग दोनों के लिए लाभदायक होगा।

जाम्बिया की राजधानी पहुँचने पर मेरी अगवानों वहाँ के प्रेसीडेण्ट केनेथ कुआंडा, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हम्फ्री मुलेम्बा, प्रधानमंत्री नालूमिनो मुडिया तथा अन्य ने की।

उस दिन सरकारी वार्तालाप से पूर्व मैंने उन लोगों के सम्मान में जिन्होंने जाम्बिया के स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन त्याग दिया था, स्वतंत्रता की मूर्ति

54 नीलम सजीव रेड्डी

पर पुष्पहार अर्पित किया।

सरकारी वातालाप के दौरान एक घंटे में भी अधिक समय तक आधिक विषय से सबधी विस्तृत विनिमय हुआ। मैंने प्रेसीडेण्ट काण्डा (Kaunda) को बताया कि दक्षिणी अफ्रीका के पिउपित्स औरगेनाइजेशन (स्वापो) को दिल्ली में अपना कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देना भारत की दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन को सहायता देने की नीति के अनुरूप है। मैंने जाम्बिया के प्रेसीडेण्ट को आश्वासन दिया कि भारत उन सभी ठोस प्रस्तावों पर ध्यान देगा जो जाम्बिया कृषि और ग्रामीण विकास तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्र में करेगा। लगभग पांच हजार भारतीय विशेषज्ञ जाम्बिया में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। उस समय भी भारतीय रेलवे मंत्रालय का प्रतिनिधिमंडल वहां पर यह पता लगाने के लिए है कि जाम्बिया में रेलवे के विकास में भारत किस प्रकार सर्वोत्तम रीति से सहायता कर सकता है। भारत और जाम्बिया आधिक विकास में सहयोग के लिए एक ज्वाइंट कमिशन बनायेंगे।

दूसरे दिन मैं सुसाबा से लगभग 350 किलोमीटर दूर किटवे की सम्पन्न ताबा खानों को देखने गया। किटवे में भारतीय मूल के अनेकों लोग हैं। नगर की लगभग सारी जनता हमारे स्वागत के लिए आई। वहां पहुंचने पर अपने स्वागत तथा मध्याह्न भोज में भाषण दते हुए मैंने दोनों देशों की आपसी और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों की समानता के बारे में बताया। मैंने जाम्बियावासियों को आश्वासन दिया कि जब भी आवश्यकता होगी उन्हें भारतीय विशेषज्ञ उनकी सम्पन्न धातुओं की संपत्ति का सदुपयोग करने में सहायता देने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए मैंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए 1979 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी मत्सन्-मंडेला को प्रदान करना भारत का दक्षिणी अफ्रीका की जनता के उद्देश्य के प्रति दृढ़ वचनबद्धता का प्रतीक है। अनेकों वर्षों पूर्व महात्मा गांधी द्वारा उनके लिए सघर्ष करने का मैंने वचन किया। मैंने कहा कि भारत और जाम्बिया दोनों के आदर्शों की समानता के कारण वे एक दूसरे के निकट हैं, दोनों देशों ने साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और जाति भेदवाद के विरुद्ध सघर्ष किया और वे एक ऐसे समाज की स्थापना का प्रयत्न करने में जुटे हैं जिसमें मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण न हो और जो समानता तथा ध्वजित की गरिमा पर आधारित हो। मैंने बताया कि गुटनिरपेक्षता की नीति विश्वशांति के लिए एक स्वतंत्र और सक्रिय शक्ति है। मैंने भारतीय मूल के निवासियों से आग्रह किया कि जिस देश को उन्होंने अपना लिया है उसके साथ एकात्मकता का भाव रखें और जाम्बिया के राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो, उनकी सम्पन्नता जाम्बिया की सम्पन्नता से जुड़ी है। यह देखकर कि उनमें से अधिकांश व्यापार अथवा सावजनिक सेवा में लगे हैं,

मैंने सुझाव दिया कि वे कृषि भी शुरू करें क्योंकि जाम्बिया में कृषि विकास की विशाल संभावना है।

उसी दिन स्वापो (SWAPO) के प्रेसीडेंट मुझसे भेंट करने आए।

बृहस्पतिवार 4 जून को मैं लिंविगस्टन में 'विक्टोरिया फाल' देखने गया। यह लुसाका से 475 किलोमीटर दूर एक पयटन वेड्र है। 'विक्टोरिया फाल' सतार के आश्चर्यों में से एक माना जाता है, यहाँ जाम्बेसी नदी का 1600 मीटर चौड़ा मुहाना सीधे सौ मीटर नीचे भूमि पर गिरता है।

शुक्रवार 5 जून को प्रेसीडेंट कॉण्डा ने मेरे सम्मान में रात्रि भोज दिया। मैंने इस अवसर पर कहा कि पूरे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह गहन चिन्ता का एक विषय है कि जिम्बावे में स्वतंत्रता का आलोक हो जाने के बाद भी दक्षिणी अफ्रीका के जातिभेद से शासित शेष क्षेत्रों में स्वतंत्रता की आशाओं को बुझाने के घुणित प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैंने जाम्बिया तथा दक्षिणी अफ्रीका का सामना करने वाले अल्पराज्यों और मुक्ति आंदोलनों को भारतीय जनता और सरकार द्वारा दिये जाने वाले समर्थन को दोहराया ताकि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की बहुत समय से दमित जनता को स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की प्राप्ति हो सके। मैंने इस विषय में सन्तोष प्रकट किया कि दोनों देश राष्ट्रमंडल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र सभ और अल्पराज्यों में घनिष्ठ सहयोग से कार्य कर रहे हैं, तथा आज की मुख्य आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं को हल करने एवम् विश्व तनाव को कम करने में अपना योगदान कर रहे हैं। जहाँ तक आपसी संबंधों का प्रश्न है, मैंने कहा कि भारत जाम्बिया के हित से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र उद्योग, कृषि, शिक्षा और कार्मिक प्रशिक्षण में अपने अनुभव और विशिष्ट ज्ञान का सहयोग देने के लिए तत्पर है।

शनिवार 6 जून को मैं घर वापिस चल दिया।

इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स का विवाहोत्सव

जून 1981 में विदेश मंत्रालय के माध्यम द्वारा मुझे 29 जुलाई 1981 को प्रिंस चार्ल्स के विवाह में सम्मिलित होने का निमन्त्रण मिला। चूँकि यह निमन्त्रण राज्य की अध्यक्षता इंग्लैंड की महारानी की ओर से सिंहासन के स्पष्ट उत्तराधिकारी अपने पुत्र के विवाह में भारत के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित करने के लिए था, मैंने सोचा कि मेरे लिये निमन्त्रण स्वीकार करना और विवाह में सम्मिलित होने के लिए लंदन जाना उचित होगा।

इसी बीच मुझे अनौपचारिक रूप से यह सूचना मिली कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके परिवार ने विवाह में सम्मिलित होने के लिए लन्दन जान की तैयारियाँ प्रारम्भ कर दी हैं। समाचार पत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में प्रधान मंत्री और उनके पारिवारिक सदस्यों की प्रस्तावित यात्रा के बारे में लिखते हुए जोड़ा गया था कि राष्ट्रपति को 'भी' आमन्त्रित किया गया है।

यह विचित्र प्रतीत होता है कि मुझे भेजे गये निमन्त्रण के सम्बन्ध में मुझसे बिलकुल बातचीत नहीं की गई। उमे प्राप्त करने के बाद मैं पर्याप्त समय तक दिल्ली में था। मैं जब हैदराबाद में जून के माह में था, यह खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। तब मैंने अपने सेक्रेटरी को आदेश दिया कि वह तत्काल दिल्ली जाये और सरकार के संबंधित अधिकारियों द्वारा मेरे शाही विवाह में सम्मिलित होने के लिए इंग्लैंड जाने का प्रबन्ध करवाये।

इस स्थिति में, विदेश मन्त्रालय के मंत्री पी०वी० नरसिंहा राव हैदराबाद मुझसे मिलने आये। उनका उद्देश्य मुझे विवाह में शामिल न होने के लिए राजी करना था। जब उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री जाने का निश्चय कर चुकी हैं और मुझसे दिया कि मैं विवाह में सम्मिलित होने का अपना विचार त्याग दूँ। मैंने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया कि भारत में राज्य का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए दूसरे राज्याध्यक्ष द्वारा भेजे अपने पुत्र के विवाह के निमन्त्रण पर जाना सवया उचित है। मैंने उन्हें बताया कि यह मात्र एक समारोह अवसर है जब प्रधानमंत्री को इंग्लैंड की सरकार के सदस्यों तथा अन्य राज्याध्यक्षों से कोई सायक वार्ता करने का अवसर नहीं मिल पायगा। इन परिस्थितियों में, मैंने कहा, प्रधान मंत्री का यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड) जाने का वास्तव में कोई लाभ नहीं है। इसके बावजूद भी यदि वह जाना चाहती हैं तो वह भी जा सकती हैं। मैंने आगे बताया कि क्योंकि मैं पहले से जाने का निश्चय कर चुका था इसलिए मैंने अपने सेक्रेटरी को अपनी यात्रा के आवश्यक प्रबन्ध करने लिए दिल्ली भेज दिया है।

तब मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का एक ही समय देश से बाहर रहना अनुचित होगा। मैंने उत्तर दिया कि लन्दन जाने का मेरा निश्चय निश्चित है और जब मेरे लिए निमन्त्रण भेजा गया था, सरकार को मुझसे सलाह लेकर मेरी इंग्लैंड यात्रा के लिए प्रबन्ध करने चाहिए थे। यदि किसी कारणवश, यह विचार गया था कि मुझे इंग्लैंड नहीं जाना है, प्रधान मंत्री को इस विषय पर मुझसे व्यक्तिगत बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने पहले कोई काय-वाही नहीं की थी और काफी समय बाद विदेश मंत्री मुझे जाने से रोकने का आग्रह करने आये थे। मैं इससे पूर्व कई बार इंग्लैंड हो आया था और मेरी दो या तीन दिन के लिए लन्दन जाने की कोई बड़ी इच्छा नहीं है। मुझे दिए गए निमन्त्रण को

सरकार ने जिस साधारण रीति से लिया था, उसने मुझे दृढ़ स्थिति लेने के लिए विवश किया। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तथा गवर्नर जनरल दोनों ही इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए काफी समय तक अपने देश से बाहर रहे।

सोमवार 27 जुलाई को मैं विवाह तथा अय समारोहों में शामिल होने के लिए सन्तन गया और 1 अगस्त को भारत वापिस आ गया।

मेरे सौटने के शीघ्र बाद एक समाचार पत्र में एक पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट मेरी इंग्लैण्ड यात्रा को गलत रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि मेरी यात्रा पर सरकारी कोश से 50,00,000 रुपये की राशि व्यय हुई और राष्ट्रपति पर सरकारी अधिकारियों तथा जन प्रचार माध्यमों द्वारा बहुत कम ध्यान दिया गया। अपनी यात्रा की पुष्टभूमि जानने के कारण यह स्वाभाविक था कि यह मुझे किसी के द्वारा प्रेरित की गई रिपोर्ट लगे। मैंने अनुभव किया कि इस रिपोर्ट को सही करवाना आवश्यक है। अधिकांश घन एयरइंडिया के घाटब विमान पर हुआ था, जिसे मेरे सन्तन में ठहरने के दौरान कुछ दिनों के लिए वहाँ रुकना स्वाभाविक था। विमान की सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार रोक़ा गया था। मैं अपने साथ न्यूनतम कमचारी ले गया था। अपने स्टाफ के उच्च सदस्यों सहित मैं लन्दन के भारतीय उच्चायुक्त भवन में ठहरा था। हमारे ठहरने पर जो व्यय हुआ था वह किसी तरह से अधिक नहीं था। सरकार द्वारा मुझे उचित सम्मान दिया गया था और विवाह समारोह, महारानी द्वारा दिये भोज और प्रधान मंत्री द्वारा दिये मध्याह्न भोज पर मेरे साथ उचित एवं सम्मानपूर्ण व्यवहार किया गया था। यह कहना विलुलसच नहीं है कि जन प्रचार माध्यमों द्वारा मेरी उपेक्षा की गयी थी। मेरे सबंध में समाचार पत्रों, अय प्रचार माध्यमों में लिखा गया था और मेरा फोटोग्राफ कुछ दैनिक पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। मेरा इस प्रकार लिखना अहंकार प्रतीत हो सकता है परंतु गलत तथ्य को सही लिखने के लिए मैं विवश हूँ।

तथापि यह विदेश मंत्रालय ही था जिसने अनिच्छा से मेरी यात्रा का प्रबंध किया था, जैसा कि वह राष्ट्रपति की सभी विदेश यात्राओं का प्रबंध करता है। अतः यह उस मंत्रालय का काय था कि वह इस बारे में सही स्थिति प्रेस को बताये या प्रेस नोट जारी करे। तथापि उसने क्योंकि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, मैंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वह तत्काल विदेश सचिव से इस सबंध में बात करें। फलस्वरूप उस मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने अपनी दैनिक प्रेस बैठकों में शीघ्र ही स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अन्य विषयों के साथ उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उक्त प्रेस रिपोर्ट में यात्रा पर हुए व्यय को बहुत अधिक बताया गया था।

इण्डोनेशिया और श्रीलंका की राजकीय यात्राओं का स्थगन

अगस्त 1981 में मेरी इण्डोनेशिया और श्रीलंका की राजकीय यात्राओं की योजना उन दोनों देशों की सरकारों से मिलाहू लेकर बनाई गई थी, परन्तु यह बाद में विचित्र परिस्थितियों में स्थगित कर दी गई। इण्डोनेशिया की यात्रा के साथ ही उसके बाद मेरी श्रीलंका की यात्रा होनी थी।

सन् 1981 के जून माह में जबकि मैं हैदराबाद में था, प्रधानमंत्री ने मुझसे फोन पर बात की और मुझे अपनी श्रीलंका यात्रा स्थगित करने की सलाह दी। उन्होंने मुझे बताया कि वह 'ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों' पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने का निणय कर चुकी हैं जो कि उसी अवधि में है जबकि मेरी प्रस्तावित श्रीलंका यात्रा है और उन्हें सलाह दी गई है कि परम्परा अनुसार राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री दोनों एक ही समय में देश से बाहर नहीं रह सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि वह जिस परम्परा की बात कर रही हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है और हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि बहुत पहले से अतिथेय देश के साथ निश्चित की गयी यात्रा को स्थगित या रद्द कर दिया जाये। यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें मेरा स्वदेश लौटना आवश्यक हो जाये तो मैं लंका से विमान द्वारा एक घंटे के अंदर भारत लौट सकता हूँ तथा मेरे द्वारा अपने कार्यक्रम के अनुसार चलने में कोई बड़ी आपत्ति नहीं उठायी जा सकती। इस पर प्रधानमंत्री बोली कि तामिलनाडु के एक मसद सदस्य ने उन्हें सलाह दी है कि ऐसे समय में जब उस देश में तमिल विरोधी दंगे हो रहे हैं राष्ट्रपति द्वारा श्रीलंका की यात्रा करना उचित नहीं होगा। मैंने उत्तर दिया कि उस मसद सदस्य को बहुत पहले से जानता हूँ, कि मैं उसे सही निणय देने वाला व्यक्ति नहीं समझता और उसने चाहें कितने सही इरादे से सलाह दी हो हमें उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। तथापि प्रधानमंत्री अपनी बात पर दृढ़ दिखाई दी। अंत में उनकी बात स्वीकार कर ली परन्तु मैंने यह भी साफ-साफ कह दिया कि यदि मेरी श्रीलंका यात्रा स्थगित होती है तो मैं इण्डोनेशिया भी नहीं जाऊंगा। मैंने तर्क दिया कि दोनों देशों की यात्रा एक समय में ही निश्चित हुई थी और एक के बाद दूसरे देश जाना था। यदि मेरी इण्डोनेशिया की यात्रा पूर्व कार्यक्रमानुसार होती है और उसके तत्काल बाद होने वाली श्रीलंका यात्रा नहीं होती, दूसरे देश को शिकायत करने का कारण मिल जायेगा। इसके अनुसार ही अगस्त 1981 में होने वाली मेरी इण्डोनेशिया और लंका की यात्रायें दोनों ही स्थगित कर दी गई।

विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों की मेरी यात्राएँ उस समय से बहुत पहले निश्चित की थी, जबकि प्रधानमंत्री ने नरोवी सम्मेलन में जाने का विचार भी नहीं किया था। नेरोवी सम्मेलन का विषय महत्वपूर्ण था, वह विशेष रूप से

तकनीकी वादविवाद के उद्देश्य से था। सरकार के शीपस्थ अधिकारियों की उपस्थिति की वही आवश्यकता नहीं थी और यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ केवल एक अंग देश के शीपस्थ अधिकारी ही उपस्थित थे। मैं अब एक ऐसी उलझन भरी घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ जो मेरी श्री लका यात्रा स्थगन के फलस्वरूप उत्पन्न हो गई थी। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि मैं जुलाई 1981 के अंत में लंदन में प्रिंस चार्ल्स के विवाह समारोह में सम्मिलित होने गया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने भी वही थे। जब हम एक दूसरे से मिले उन्होंने मेरी श्रीलंका यात्रा के स्थगित किये जाने पर निराशा प्रकट की। मैंने उनको समझाया कि ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री को भी उसी समय देश से बाहर जाना था और हम दोनों एक ही समय में देश से बाहर नहीं रह सकते हैं अतः यह निर्णय लिया गया कि मैं देश में ही रहूँ। मैंने उनको आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र अवसर मिलते ही श्रीलंका यात्रा पर आऊँगा। दुर्भाग्यवश जबकि हम दोनों लंदन में ही थे, प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने श्रीनगर में कहा कि लंका में कुछ स्थानों पर तमिल विरोधी दलों के कारण मेरी श्री लंका यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित उनका यह वक्तव्य श्रीलंका के राष्ट्रपति की दृष्टि में पड़ा। प्रधानमंत्री द्वारा बताया गया कारण मेरे द्वारा श्रीलंका के राष्ट्रपति को कहे गये कथन से इतना भिन्न था कि उसने मुझे बड़ी बेडगी स्थिति में डाल दिया। मैं उनसे यही कह सकता था कि जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरी यात्रा स्थगित होने का कारण वही है जो मैंने उन्हें पहले बताया था।

जब दोनों देशों की यात्रा स्थगित की गई थी, विदेश मंत्रालय के सैक्रेटरी गोनसाल्वस को उन देशों को इसका कारण बताने के लिए भेजा गया था। वह श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले थे और उनको बताया था कि मुझे अपनी यात्रा इसलिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि प्रधानमंत्री को भी उस समय एक आवश्यक सम्मेलन में जाना था और हम दोनों एक ही समय देश से बाहर नहीं रह सकते। इस प्रकार सरकारी स्पष्टीकरण भी मेरे द्वारा बताये गए कारण के अनुरूप ही था।

हमारे देश में यह दुर्भाग्य की बात है कि समय-समय पर हिंदू-मुस्लिम दंगे होते रहते हैं। क्या हम किसी मुस्लिम देश के शीपस्थ अधिकारी का इन दंगों के आधार पर भारत यात्रा स्थगित करना उचित और सही कारण समझेंगे? इसका उत्तर स्पष्ट रूप में नकारात्मक है। प्रधानमंत्री का अग्रान् वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण और दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बंध बनानेवाला नहीं था। ठीक इसके बाद 1981 के अगस्त-अक्टूबर में, विदेश मंत्रालय ने मुझे शीघ्र नेपाल यात्रा पर जाने के लिए सहमत करने का प्रयत्न किया। उनका तर्क था कि नेपाल नरेश ने इस

बात पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है कि यद्यपि वे कई बार हाल ही में भारत आये हैं, भारत के राष्ट्रपति इसने बदले में कभी नेपाल नहीं गये। मैंने विदेश मंत्रालय को कहा कि इण्डोनेशिया और श्रीलंका की यात्राएँ क्योंकि पहले स्पष्ट कर दी गई थी, अतः अब मंत्रालय को तीनों देशों की यात्राओं का एक विस्तृत कार्यक्रम मेरे विचारों बनाना चाहिए। इस सुझाव के फलस्वरूप ही मेरी दिसम्बर 1981 में इण्डोनेशिया और नेपाल की यात्राएँ और फरवरी 1982 में श्रीलंका की यात्रा हुई।

इण्डोनेशिया और नेपाल में

3 दिसम्बर 1981 की सुबह मैं इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति के निमन्त्रण पर वहाँ की राजकीय यात्रा के लिए चल दिया। मेरे साथ घमपत्नी के अतिरिक्त केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री शंकरानन्द थे। प्रधानमन्त्री उस देश की यात्रा सितम्बर 1981 में जब वह आस्ट्रेलिया जा रही थी थोड़े समय के लिए घर चुकी थी। मेरी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के पारम्परिक और घनिष्ठ सम्बन्धों को दृढ़ करना था। मुझसे पूर्व सन् 1976 में भारत के राष्ट्रपति इण्डोनेशिया की यात्रा पर गए थे।

जाकार्ता में हवाई अड्डे पर हमारी अगवानी राष्ट्रपति सुहार्तो और उनकी पत्नी ने की। यद्यपि आकाश पर बादल छाये थे फिर भी हमारे स्वागत के लिए भारी सङ्ख्या में लोग हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। वहाँ पर पारम्परिक स्वागत करने के बाद हमें राज्यकीय अतिथि भवन में ले जाया गया।

मेरे सम्मान में ऐतिहासिक 'मेरुदेका' महल में दिए गए भोज में राष्ट्रपति सुहार्तो ने कहा कि मेरी यात्रा भारत तथा इण्डोनेशिया की जनता के बीच स्थित मित्रता को प्रतिबिम्बित करती है। उन्होंने इसके बाद यह बताया कि हमारा सत्तारक्षी विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से भरा है और निर्गुट आन्दोलन के सिद्धान्तों एवं आदर्शों को आगे बढ़ाना व पुनः मजबूत बनाना आवश्यक है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि किस प्रकार उस समय कुछ देश निर्गुटता के सिद्धांतों और आदर्शों से विचलित हो रहे हैं और किस प्रकार इसके फलस्वरूप निर्गुट आन्दोलन के सदस्य देशों के विचारों में मतभेद उत्पन्न होने से एकता के लिए सकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने सतोष प्रकट किया कि भारत, इण्डोनेशिया तथा कुछ अन्य सदस्य देश निर्गुट आन्दोलन के मूल सिद्धांतों को साकार करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों पूर्व भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा तथा मेरी

यात्रा इण्डोनेशिया और भारत के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और अधिक बढ़ाएगी। इण्डोनेशिया में सीमेट और चीनी उद्योगों के निर्माण में भारत सरकार तथा भारत के निजी क्षेत्रों की भागीदारी आर्थिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बढ़ते हुए अत्यन्त सक्रिय सहयोग का ठोस उदाहरण है।

उत्तर में, मैंने कहा कि महाशक्तियाँ की प्रतिद्वन्द्विता के कारण हमारे क्षेत्र में नवीनतम अस्त्रों के प्रसार बनने की संभावना है। मैंने अपने पड़ोसी देशों में नौसेना के जमाव की ओर संकेत करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र के देशों में साथ-साथ विचार विमर्श और सहयोग ही सर्वोत्तम तरीका है जिससे इनको प्रभावहीन बनाया जा सकता है। हमारे दोनों देश अपने समीपस्थ सागरों में एक ही प्रकार की भूकेंद्रिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आपसी सहायता तथा घनिष्ठ आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में मैंने कहा—हमारे बढ़ते हुए द्विपक्षीय सहायता से हमारे दोनों देश अब एक-दूसरे से ऊँची आशाएँ रखने के युग में आ गए हैं। वास्तव में हम प्रसन्न हैं कि आर्थिक और औद्योगिक विषयों में एक विस्तृत समझदारी हमारे दोनों देशों के बीच आ चुकी है और हमारे विशेषज्ञों ने उन क्षेत्रों का पता लगा लिया है जिनमें आपसी सहयोग की बहुत अच्छी संभावनाएँ हैं।

दूसरे दिन इण्डोनेशिया के विदेश मंत्री से विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। हमारे दोनों देश कपूचिया के सम्बन्ध में मत विभिन्नता रखते थे, यह सभी को पता था। तथापि उन्होंने उचित ही कहा कि कुछ प्रश्नों पर हमारा मत वैभिन्न्य होने से कोई हानि नहीं है। इससे हमारा आपसी मित्रतापूर्ण संबंधों में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

भारतीय समुदाय के सदस्यों की एक सभा को सम्बोधित करते हुए मैंने बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत के पड़ोस में शीत युद्ध के पुनः शुरू होने पर अपनी चिन्ता प्रकट की। हथियारों की होड़ को बढ़ने से रोकने और तनाव कम करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयत्नों का उल्लेख किया। मैंने दोनों देशों के बीच वर्षों पुराने और विभिन्न संबंधों का स्मरण कराया, अनेकों भारतीयों ने इण्डोनेशिया को अपना घर बना लिया है और वहाँ की पत्र-पुष्पों से युक्त सुंदर संस्कृतियों बनाने में अपना योग दिया है। इस सदन में, मैंने इण्डोनेशिया में भारतीय लोगों की उपस्थिति और उनके द्वारा राष्ट्रीय गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में भाग लेकर देश की उन्नति में सहयोग करने का भी उल्लेख किया।

अपने सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन में मैं उन प्रयत्नों के बारे में बोला जो भारत और इण्डोनेशिया के मध्य सहयोग का बढान के लिए किए जा रहे थे। मैंने राष्ट्रपति सोहार्तो की भारत यात्रा को दोनों देशों के मध्य बढ़ते हुए मित्रतापूर्ण संबंधों का एक महान चिह्न बताया। मैंने इण्डोनेशिया की राजधानी जाकार्ता को शिक्षा, उद्योग और कला का एक स्पन्दनशील वेद्र बताया और कहा

कि जिस गमजोशी से मेरा स्वागत और आतिथ्य हुआ है, वह इण्डोनेशिया की भारत मैत्री का एक प्रतीक है।

राष्ट्रपति सोहार्तो के साथ मैं तामान लघु इण्डोनेशिया इटाह देखने गया। यह सुंदर इण्डोनेशिया को अत्यन्त लघु रूप में दिखलानेवाली स्थायी प्रदर्शनी है।

उस दिन प्रातः काल मैंने बालिवाटा सैनिक समाधि पर युद्ध वीरो की स्मृति में पुष्पमाला अर्पित की।

5 दिसम्बर को मैंने बाली द्वीप प्रस्थान किया। राग में, मैं प्रतिष्ठित बोरोबन्दर मंदिर देखने के लिए जोगजाकार्ता गया। यह मंदिर बौद्ध स्थापत्य और भूर्तिकला के चमत्कार हैं। सप्ताह को सड़कें वर्षों तक इनकी जानकारी नहीं हुई थी, परन्तु पिछली शताब्दी में इनको पुनः खोज निकाला गया। मुझे इस मंदिर की एक अमूर्त भेंट की गई।

बाली में, मेरा स्वागत गवर्नर तथा अन्य सरकारी अधिकारियों ने किया। इस टापू के वृक्षों के सौंदर्य से आकर्षित होकर दूर-दूर से पर्यटक यहां आते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं। मैं भारत का दूसरा राष्ट्रपति या जिसने इस द्वीप की यात्रा की।

जब हम द्वीप के सबसे प्राचीन मंदिर पुरातामानाआयून मेनगुरी, जो कि हमारे ठहरने के स्थान, पेरतामनिआ सागर तट कुटीर से 25 किलोमीटर दूर था पहुंचे, आस पास के ग्रहों और गांवों के हजारों लोग अपनी रंग बिरंगी पोशाकों में मंदिर में हमारा स्वागत करने के लिए आए। उन्होंने मेरा इस प्रकार स्वागत किया जैसे मैं एक प्राचीन हिन्दू राजा हूँ जो मंदिर तथा द्वीप की तीर्थ यात्रा पर आया है।

इण्डोनेशिया के द्वीपों में बाली एक ऐसा द्वीप है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है। यद्यपि यह आकार में छोटा है, इसकी जनसंख्या लगभग 25 लाख है जो कि पूरी तरह हिन्दू है। यह जानना रुचिकर होगा कि इण्डोनेशिया की 90 प्रतिशत जनसंख्या इस्लाम धर्म को माननेवाली है। यह लोग हिन्दू तथा बौद्ध धर्म से और कुछ प्राचीन धार्मिक परम्पराओं एवं विश्वासों से अत्यधिक प्रभावित कहे जाते हैं।

भारत वापस आने पर मैंने हिन्दू संस्कृति पर कुछ पुस्तकें द्वीप के एक विश्वविद्यालय को जहां हिन्दू धर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है भिजवा दी।

दूसरे दिन मैं इण्डोनेशिया से नेपाल को रवाना हुआ। मुझे जाकार्ता हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति सोहार्तो और उनकी पत्नी विदा देने आए। मैंने उन दोनों को भारत आने का आमन्त्रण दिया जो उन्होंने स्वीकार कर लिया।

सोमवार 7 दिसम्बर को काठमांडू के त्रिभुवन हवाई अड्डे पहुंचने पर महा राजा बीरेन्द्र और महारानी ऐश्वर्या ने हमारी अगवानी की। हमारे विदेश मंत्री द्वारा उस देश की यात्रा करने के दस दिन के अन्दर मेरे वहां जाने का उद्देश्य

नेपालियों को भारत की उनके प्रति सदेच्छा और स्नेह की भावना से और अधिक आश्वस्त करना था। हवाई अड्डे से हमार ठहरने के स्थान तक 6 किलोमीटर के मार्ग पर हप से भरी हुई भीड़ थी।

हमार पहुंचन के तत्काल बाद मैंने पत्नी सहित महाराजा और महारानी के साथ चाय-पान किया। इसके पश्चात् प्रधानमंत्री सुय बहादुर थापा से हमारी बातचीत हुई। इस वार्ता में हमार दाना दशा के राजदूता और राजनयिकों ने हम सहायता दी। रात में महाराजा बीरे द्र तथा महारानी एश्वर्या ने हमारे सम्मान में रात्रि भोज दिया।

इस रात्रि भोज में महाराजा बीरे द्र ने कहा कि प्राकृतिक साधना से सम्पन्न होने के बावजूद भी भारत और नेपाल अपने को गरीबी व पञ्च से मुक्त नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी दूसरे देश की भांति नेपाल सम्मान और गौरव से रहना चाहता है और इसी लक्ष्य की प्राप्त के लिए उसने अपना मित्रता का हाथ सभी देशों की ओर बढ़ाया है, विशेष रूप से उनकी ओर जा उसका क्षेत्र एवं पड़ोस में हैं। उन्होंने घोषित किया कि उनका देश ऐसा सहयोग चाहता है जिससे वह अपने साधना का उपयोग करने की क्षमता प्राप्त कर सके। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रयास में नेपाल को सहायता देने के लिए उनका देश आगे जाए है, जिनमें भारत अग्रणी है। उन्होंने बताया कि नेपाल और भारत के संबंधों की विशेषता आपस में अत्यधिक सद्भावना और सम्मान होना है और इनको दृष्टि में रखते हुए वह अपने वर्तमान सहयोग के बंधनों को और अधिक मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी देश जिसमें पंचशील की महान परंपराओं में अपने को विकसित किया है, इस विश्वास का नहीं हो सकता कि एक की सम्पन्नता दूसरे की गरीबी के शोषण पर आधारित हो। तब उन्होंने अपने शांति क्षेत्र के विचार के बारे में बताया और कहा कि जहां तक पूरे एशिया और दक्षिणी एशिया के समीपवर्ती स्थानों का संबंध है, नेपाल जिस भी योगदान के योग्य था उसने दिया है। नेपाल किसी भी मूल्य पर आने वाले क्षेत्र में शांति रखने के लिए दृढ़ है और नेपाली जनता की यह हार्दिक इच्छा है कि नेपाल का एक शांति क्षेत्र का मायता से संबंधित प्रस्ताव में अभिव्यक्त हुई है।

मैंने अपने उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत नेपाल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और नेपाली जनता के कल्याण के प्रति उसका ध्यान उतना ही दृढ़ है जितना कभी था। मैंने कहा कि यह सन्तोष का विषय है कि दाना पक्षा ने जन साधनों का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करने के लिए आपसी सहयोग का आवश्यकता का अनुभव किया है जो कि दोनों के हित में है। बरनाली और पंचखर जसी परियोजनाओं से इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। यह सही समय है जब हमें नेपाल से बहकर भारत आने वाली मुख्य नदियों के जल का सदुपयोग करना

चाहिये। ये परियोजनायें बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, सिंचाई और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों में अत्यधिक लाभ देने के अतिरिक्त उन क्षेत्रों के विकास का भी परिवर्तन स्रोत सिद्ध होगी जो इनकी सीमा से बाहर हैं। मैंने आगे कहा कि राष्ट्रीय चेतना के अनुसार प्रत्येक देश को अपनी सरकार का रूप विकसित करना होता है और यह देखना होता है कि स्थायीत्व तथा उन्नति करने का सबसे सही माध्यम क्या होगा। मैंने नेपाल के शांति दौरे प्रस्ताव या जिक्र नहीं किया।

दूसरे दिन पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने और गद्दीदा की समाधि पर माल्यापण करने के बाद मैं 'सिटो हॉल' पहुँचा, जहाँ नागरिकों द्वारा स्वागत होता था। काठमांडू नगर पंचायत के महापौर (चयरमेन) प्रेम बहादुर शाक्य ने बताया कि ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। बुद्ध न भारत में ज्ञान आलोक उपलब्ध किया और भारत को अपना कार्यक्षेत्र बना।

मैंने अपने उत्तर में कहा कि भारत और नेपाल की जनता के मध्य मित्रता तथा बंधुत्व के बंधन सदब से बने आ रहे हैं। यह बंधन भूगोल और इतिहास द्वारा निर्मित हुए हैं। भारत और नेपाल की जनता के बीच विस्तृत आपसी सम्बन्ध है। दोनों देशों को मिली सांस्कृतिक विरासत भी समान है और उसने भारत और नेपाल के बीच अटूट मित्रता स्थापित की है। मैंने आगे बताया कि रामेश्वरम नेपाल का है और पशुपतिनाथ भारत का, तथा मैंने मुख्य पशुपतिनाथ मन्दिर में दोनों देशों तथा उसके लोगों के लिए मित्रता तथा सम्पन्नता की प्राप्ति की है। हिमालय की नदियों का सदुपयोग करने पर मैंने बल दिया। ये नदियाँ प्रतिवर्ष लाखों लोगों की हानि तथा नाश करती हैं। इन्हें दोनों देशों की जनता की सम्पन्नता तथा संपत्ति के स्रोत के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दोनों देशों का प्रमुख कार्य गरीबी तथा भूख को मिटाना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है। मैंने एकत्रित जन समुदाय को आश्वासन दिया कि दोनों देशों के बीच कभी कोई संधय नहीं होगा और न इससे पहले भी कभी कोई हुआ है।

नागरिक अभिनंदन में, प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त अनेक दूसरे देशों के राजनयिक तथा विशिष्ट नागरिक भी थे।

प्रधानमंत्री ने बाद में मेरे सम्मान में मध्याह्न भोज दिया।

नेपाल भारत मंत्री सच ने 9 दिसम्बर को जनकपुर में मेरे सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया। मैंने अपने भाषण में कहा कि भारत बुद्ध का विचार तक नहीं कर सकता है क्योंकि सरकार तथा जनता द्वारा अधिक उन्नति के लिए पिछले पैंतीस वर्षों में किया गया कठोर परिश्रम का फल युद्ध होने पर उतने ही मिनटों में नष्ट हो जायेगा। भारत यह देखने का इच्छुक है कि उसके नेपाली भाई भी किसी संधय में न पड़े। अपने तैयार किये गए भाषण से हटकर मैंने आगे कहा कि मैं सुना है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके सम्बन्ध में दोनों देश।

के बीच विचार विमर्श होना चाहिये, ऐसा ही एक प्रस्ताव नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने का है। मैंने महाराजा बीरेन्द्र और नेपाल के प्रधानमंत्री को भारत आने का आमंत्रण दिया है ताकि वे हमारे प्रधानमंत्री के साथ इस प्रस्ताव पर वार्तालाप कर सकें और सभी विषयों को सन्तोषजनक रूप से हल कर सकें।

इससे पूर्व पोखरा में 'एक्स सर्विस मैन' के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मैंने कहा कि भारतीय सेना में गोरखाओं की सेवाएँ अमूल्य हैं। मैंने उनके उस उच्च युद्ध कौशल, वफादारी तथा वक्तव्य भक्ति की जिसके फलस्वरूप वह भारतीय सेनाओं में रहते हुए युद्ध करते हैं, प्रशंसा की। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि हमारी सरकार हृदय से 'एक्स सर्विसमैन' और उन पर निर्भर रहने वालों का कल्याण चाहती है।

जनकपुर को जानकी की जन्मभूमि माना जाता है। यह भारतीय सीमा से आठ किलोमीटर दूर है। मैं इस नगर में गया और जानकी मंदिर में पूजा की। जनकपुर की मेरी यात्रा का, हसी में राजा दशरथ के बाद किसी भारतीय राज्याध्यक्ष की प्रथम यात्रा के रूप में वर्णन किया गया। राजा दशरथ वहाँ सीता को अपने पुत्र राम की वधू के रूप में लेने गये थे।

मैंने दस दिसम्बर को काठमाण्डू से नई दिल्ली प्रस्थान किया। मुझे विदाई देने के लिए हवाई अड्डे पर महाराजा बीरेन्द्र, महारानी ऐश्वर्या, प्रधानमंत्री तथा अन्य उच्च अधिकारी आये। उड़ान के दौरान मौसम इतना स्वच्छ और चमकीला था कि नई दिल्ली सैटल से पूछ हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत की शानदार झलक देखने को मिल गयी।

लका का लावण्य

मंगलवार दो फरवरी 1982 को मैं दिल्ली से लका की राजकीय यात्रा के लिए चला। मेरे साथ अय्य लोमो के अतिरिक्त मेरी पत्नी और केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री वसन्तसाठे थे। लका की सरकार ने मुझे 4 फरवरी को अनुराधापुर में अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रूप में आमंत्रित किया था। हम उस दिन मध्याह्न में पहुँचे। लका के राष्ट्रपति जयवर्धने तथा उनकी पत्नी, उनके मंत्रिमण्डल और अन्य लोगो ने हमारी अवगानी की। मुगलबेरा नगाद बजाये गये और स्वागत के प्रतीक रूप में शख छ्वनि की गई। हम हवाई अड्डे से बीस किलोमीटर दूर कोलम्बो में स्थित राष्ट्रपति भवन पहुँचे। कहा जाता है कि उपनिवेश

वादी दिनों में इस महल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल निवास करता था। नीलम्बो में हमें यहीं ठहराया गया।

अपराह्न में लका के राष्ट्रपति अनौपचारिक रूप से मिलने आये। मैंने बिना पूर्व कार्यक्रम के नगर का तथा कोलम्बो से कुछ मील दूर स्थित जयवर्धनपुरा का भ्रमण किया। जयवर्धनपुरा में एक नया शानदार भवन संसद के लिये बना है। परन्तु उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ था।

राष्ट्रपति जयवर्धने ने मेरे स्वागत में एक भोज दिया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने श्रीलंका को जो सबसे बड़ा कोश दिया है, वह महात्मा गौतम बुद्ध का दशन है। भारत का सबसे महान पुत्र और उसका दशन आज तक श्रीलंका के अधिकांश लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि भारत और श्रीलंका की निकटता केवल एक भौगोलिक विषय नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों की निकटता है। यह भूत काल का सत्य था और वर्तमान का भी है। और तब उन्होंने कहा कि यह उचित ही है कि भारत के राष्ट्रपति उनके देश की स्वतंत्रता के वार्षिकोत्सव पर उपस्थित हुए हैं। लका के स्वतंत्रता आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध छेड़े जाने वाले भारत के ऐतिहासिक स्वाधीनता संग्राम से प्रेरणा ली थी। राष्ट्रपति ने मेरे युवा काल और उस समय मेरे द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में निभायी गयी भूमिका तथा स्वतंत्रता के बाद मेरे द्वारा ग्रहण किये गए अनेक पदों का उल्लेख करके अपनी सदा श्रमिता दिखलाई। उन्होंने कहा कि भारत की तरह उनके देश में उनकी पीढ़ी का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं से प्रभावित नहीं हुआ हो। उन्होंने प्रशंसा के साथ उन महान पुत्रों के साथ अपने सम्पर्क और व्यक्तिगत सम्बन्धों से उठाये गये लाभों का स्मरण किया। उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार आकार और विस्तार में भारत से भिन्न होते हुए भी श्रीलंका और भारत अनेकों बातों में समान हैं जिसमें प्रजातन्त्र प्रणाली की सरकार के प्रति वचनबद्धता भी शामिल है। जबकि तीसरी दुनिया में जनतंत्र का प्रकाश एक के बाद दूसरे देश में बुझता जा रहा है, लका और भारत जो कि अनेकों सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के सहभागी हैं अपनी स्वतंत्रता और प्रजातान्त्रिक सर्वोच्च सत्ता बनाये हुए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत और लका की अनेकों समस्याओं के प्रति समान दृष्टि है। यह निर्गुट आन्दोलन को सफल बनाने के समान प्रयत्नों में प्रकट होती है। उन्होंने 1954 के कालम्बो सम्मेलन का जिसमें उन्होंने भाग लिया था स्मरण किया। वह वास्तव में निर्गुट आन्दोलन को लानेवाला सम्मेलन था। उसी सम्मेलन से 'निर्गुट' शब्द अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक शब्दावली में आया। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने इस आन्दोलन में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है और श्रीलंका की

यह कामना है कि भारत को यह भूमिका निभाते रहना चाहिए ।

उसके पश्चात् बोलने के लिए मैं उठा । मैंने उन बयानों का उल्लेख किया हमारे दोनों देशों के इतिहास, हमारी संस्कृति और वास्तव में हमारी जीवन शक्ति को प्रभावित करते हैं । मैंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे दोनों देशों ने ज प्रणाली को अपनाया और लागू किया है, जनता जो कि अतल सबसे शक्ति है समय-समय पर अपनी सरकार निर्वाचित करती है और हम दोनों को अपने विभिन्न मत वाले समाज पर गव करना चाहिए । हमारे लोगों की विभिन्न हमारी संस्कृति तथा परंपरा को सम्मान बनाया है । श्री लंका की राजर्षि काया भारत से आने वाले लोगों द्वारा सपना बनी है । इन लोगों ने देश की अर्जुनता में सहयोग दिया है, इन्होंने देश की संपूर्ण सांस्कृतिक संपन्नता में अपना दिया । मैंने श्रोताओं को स्मरण दिलाया कि बुद्ध की शिक्षाओं में निहित मूल हमारे दोनों देशों को कुछ सहजशीलता, कुछ अश्व तथा आपसी समझदारी और भक्तता सिखाता है जिससे हमें अपने समय की पेंचीदा समस्याओं को हल कर अधिक सरलता होती है । उसके बाद मैंने सन् 1954 के कोलम्बो सम्मेलन राष्ट्रपति जयवर्धने के सग का उल्लेख करते हुए कहा कि निगुट आंदोलन में श्री का योगदान अद्वितीय है । भारत तथा श्रीलंका को पहले से और अधिक घनि के साथ निगुट आंदोलन के उद्देश्यों को पाने हेतु कार्य करना चाहिए, विशेष अपने पड़ोसी दशा में । मैंने आगे कहा कि दस वर्ष से भी पूर्व यह श्रीलंका या भारतीय सागर को शांति क्षेत्र स्वीकार करवाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी क्षेत्र में रहने वाले हम लोगों के लिए सागर में महाशक्तियों की बढ़ती हुई स्थिति स्पष्ट रूप से ऐसा विकास है जो संकट का सूचक है क्योंकि इससे दो शक्तियों के मध्य संघर्ष छिड़ने की स्थिति में हम उसके बीच पोंस जा सकते हैं परिस्थितियों में सभी सागर तटीय राज्यों का स्पष्ट मतव्य है कि वे समुक्त संघ के हिंद महासागर को शांति क्षेत्र मानने के प्रस्ताव की पालना पर अतल द दें । क्षेत्रीय सहयोग के प्रश्न के संबंध में मैंने कहा कि यह कोई आकस्मिक या कि इस विषय पर प्रथम बैठक श्रीलंका की राजधानी में हुई । मैंने श्रोताओं आश्वासन दिया कि हमारी सरकार दृढ़तापूर्वक और पूरी तरह क्षेत्रीय सहयोग लिए वचनबद्ध है । इसमें हमारा यह विश्वास निहित है कि हममें से प्रत्येक कल्याण में सभी का कल्याण निहित है और हम केवल अपने ज्ञान, साधन विशिष्टताओं में परस्पर भागीदार बनकर अपने लोगों के उज्ज्वल भविर् निश्चित कर सकते हैं । मैंने ध्यान दिलाया कि भारत और श्रीलंका के संबंध पड़ोसी होने का एक उदाहरण है । जिस रीति से हमने विभिन्न समस्याओं सामना तथा हल करने का निश्चय किया वह हमारे दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय और रचनात्मक रीति से कर लिये गये हैं ।

किया कि हमारे दोनों देश आपसी साम बे लिए साथ-साथ काम करते रहेंगे और राष्ट्रपति जयवर्धने के नेतृत्व में भारत और श्रीलंका के संबंधों में निरंतर अभिवृद्धि होगी।

दूसरे दिन मैं एव स्पेशल ट्रेन द्वारा अनुराधापुर गया। यह सिल्वेन घनित्र के गावों से गुजरती हुई 200 किलोमीटर में अधिक दूरी की यात्रा थी। अनुराधापुर सिंहल के बौद्धवाद की प्रथम राजधानी थी। श्रीलंका की अधिकांश भवन निर्माण कला के महत्वपूर्ण स्थान अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और भारत तथा श्रीलंका की युगा पुरानी मित्रता के प्रमाण हैं। मुझे सबप्रथम एक वृक्ष के समीप से जाया गया जो कि सर्वाधिक पवित्र समझा जाता है। इसके चारों ओर रेलिंग लगी हुई थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह उत्तरी भारत के बोध गया में स्थित उस बोधि वृक्ष की शाखा से उगा है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यह भी विश्वास किया जाता है कि यह शाखा सम्राट अशोक की पुत्री लका साई थी। मैंने उपवनो, झीलों और प्रभावपूर्ण स्तूपों के इस नगर के अनेकों ऐतिहासिक स्थानों के दर्शन किए।

दूसरी सुबह मैं श्रीलंका की स्वतंत्रता के चौतीसवें वार्षिक समारोह में सम्मिलित हुआ और प्रभावोत्पादक सैनिक परेड देखी। साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें देश की अनेकों प्रसिद्ध कला मंडलियों ने भाग लिया। अनुराधापुर के छोटे से नगर में चारों ओर उत्सव के चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे थे। देश के सभी भागों से लोग इस भव्य समारोह की धूमधाम को दखन के लिए एकत्रित हो गए थे।

5 फरवरी को मैं हेलीकोप्टर से केडी नगर गया। उड़ते हुए मैंने उस समय निर्मित होते बिजटोरिया बाघ को देखा। केडी पहुँचने पर मुझे रॉयल बोटनिकल गार्डन, पराडिनोवा में एक वृक्ष का पीछा लगाने के लिए आमंत्रित किया गया जो मैंने सहज आरोपित किया। उसके पश्चात् मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया। इसके बाद भारतीय मूल के निवासियों द्वारा मेरा तथा पत्नी का 'क्वींस होटल' में स्वागत हुआ। केडी उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहाँ बुद्ध का दात सुरक्षित रखा गया है। अपराह्न में श्रीलंका के प्रेसीडेंट के साथ मैंने पवित्र पुरातन चिह्न के विशेष दर्शन के लिए ढालाडा भालिमावा गेया। (देश भ्रमण पर आने वाले महत्वपूर्ण राज्याध्यक्षों के लिए पुरातन चिह्न का विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाता है।) एक तीथयात्री के रूप में अपनी थढ़ाजलि बुद्ध को भेंट करते हुए मुझ प्रसन्नता हुई और मैंने बौद्धमत तथा हिंदूमत के बीच स्थित संबंधों का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त भाषण दिया। शाम को मैं हेलीकोप्टर में कोलम्बो लौट आया।

6 फरवरी को भारत श्रीलंका व्यापार, सांस्कृतिक और मंत्री सच द्वारा मेरे

सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने कहा कि भारत और श्रीलंका दोनों अपने आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव करते हैं और इसलिए उन्हें यह सुरक्षित करने के लिए वि.वे.हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले किसी संघर्ष या तनाव के शिकार नहीं बने, साथ-साथ कार्य करना चाहिए। मैंने आगे कहा कि हिंद महासागर को वास्तव में शांति क्षेत्र के रूप में भाग्यता मिलनी चाहिए।

साय कोलम्बो कार्पोरेशन, उसके सदस्यों और मेयर द्वारा दिए गए नागरिक अभिनंदन समारोह में बोल्ते हुए मैंने, घोषणा की कि भारत जितना तकनीकी ज्ञान देने की क्षमता रखता है, उसे लंका को देने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक रहेगा।

उसी संध्या को बाद में राष्ट्रपति जयवर्धने और उनकी पत्नी के साथ मैंने सपत्नीक नवम महापौराहेरा देखा। एक जुलूस निकाला गया जिसमें रथ पर बुद्ध की मूर्ति थी, इसमें देश के संकटों भक्तों ने भाग लिया।

तत्पश्चात् मैंने श्रीलंका के राष्ट्रपति के सम्मान में एक प्रीतिभोज होटल ओवेराय में दिया। वास्तव में यह मेरी लंका की राजकीय यात्रा की समाप्ति का चिह्न था। सात फरवरी की सुबह हमने दिल्ली प्रस्थान किया।

मेरी श्रीलंका की यात्रा से उत्पन्न दो मुख्य बातें हैं जिनका यहां वर्णन करना आवश्यक है।

प्रथम श्रीलंका द्वारा अपनाई गई यह परंपरा है कि वहां देश में राष्ट्रीय दिवस समारोह क्रमशः विभिन्न स्थानों पर होता है। ऐसा करने के पीछे यह विचार है कि विभिन्न स्थानों की जनता को एक बार परेड देखने को मिल जाती है और उन्हें समारोहों के कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के अवसर मिल जाते हैं।

श्रीलंका एक छोटा देश है और राजधानी कोलम्बो देश के दूसरे छोर पर स्थित भाग से भी अधिक दूर नहीं है। इसके बावजूद वहां की सरकार ने ऐसी परंपरा का विकास किया है जिससे जनता को राष्ट्रीय दिवस समारोह देखने और उसमें शामिल होने का सतीष प्राप्त होता है। भारत श्रीलंका से कई गुना विशाल देश है, राजधानी किसी भी दृष्टि से केन्द्र में स्थित नहीं है। देश के अनेक भागों के निवासियों को राजधानी देखने के लिए पर्याप्त घन और समय खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार राजधानी में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की शोभा और दूर दूर तक प्रसिद्ध प्रदर्शन को देखने का आनंद हमारी जनता के अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाता। केवल वे लोग जो दिल्ली अथवा उसके आसपास रहते

हैं, साल-दर-साल यह समारोह देखने की सुख सुविधा का साम उठाते हैं। निस्संदेह विभिन्न राज्यों में भी गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित होते हैं परन्तु उनमें वह शान और शक्ती नहीं होती जो दिल्ली के समारोह में होती है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से यह समारोह विभिन्न राज्यों में क्रमशः आयोजित किया जा सकता है जिससे देश के भिन्न भिन्न स्थानों के निवासियों को इसे देखने का अवसर मिल सके और राष्ट्रीय उत्सव में शामिल होने की भावना उत्पन्न हो सके। यह एक महत्वहीन विषय प्रतीत हो सकता है परन्तु इस प्रकार के छोटे छोटे कार्य लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने में अवश्य सहायता देते हैं।

दूसरा विषय मेरे विचार से श्रीसका सरकार द्वारा भाषा के प्रश्न को महत्व देना है। मैंने पाया कि अनुराधापुर के सांस्कृतिक प्रदर्शन में सभी घोषणायें तीन भाषाओं—अंग्रेजी, सिन्धी और तमिल में हो रही थी। इसी प्रकार सरकार द्वारा मेरी यात्रा के बारे में जारी किये गये निर्देश और दूसरे पर्चे आदि सभी, जिन्हें देखने का अवसर मुझे मिला तीनों भाषाओं में गृहित थे। वश के किसी भी भाषा समूह की अपेक्षा नहीं की गयी थी। इससे मैं अपने देश के तीन भाषा फामूले के बारे में घोषित उदासीनता के बारे में विचार करने लगा। काफी वादविवाद के बाद, जवाहर लाल नेहरू के समय में ही हमने निर्णय किया था कि बच्चा को उनकी मातृ भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए। हिन्दी भाषी राज्यों के बच्चा जिनकी मातृ भाषा हिन्दी है, से आशा की गई थी कि वे एक दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा सीखेंगे। दुर्भाग्यवश यह फामूला कार्यान्वित नहीं हुआ। हिन्दी भाषी क्षेत्रों में बच्चे दसवीं कक्षा या उससे ऊपर तक भी केवल हिन्दी और थोड़ी सी अंग्रेजी सीखते हैं अथवा अंग्रेजी बिलकुल नहीं सीखते। वे उन केन्द्रीय सेवाओं की प्रतियोगिताओं में जिनमें दसवीं कक्षा 'यूनतम शिक्षा योग्यता' है, बैठ सकते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी राज्यों के बच्चों को हिन्दी और अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, जिनमें से एक भी उनकी मातृ भाषा नहीं। वे हिन्दी भाषी राज्यों के उम्मीदवारों से समान धरातल पर प्रतियोगिता नहीं कर सकते। तीन भाषाई फामूले का पूरे देश में सफल क्रिया-व्ययन, हिन्दी को प्रयोग में लाने की कष्ट पूर्ण कोशिश किए बिना शासन में अंग्रेजी के उपयोग को जारी रखना, और केन्द्रीय तथा अखिल भारतीय सेवाओं में सभी स्तरों पर भर्ती होने के अवसरों की पूर्ण समानता होना राष्ट्रीय एकता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार का कोई संदेह होने की भावना नहीं होनी चाहिए कि हिन्दी बोलने वाले लोगों को भर्ती होने के स्तर पर कोई सुविधा होती है। इस भावना के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि केन्द्रीय सरकार शासन में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी बहुत शीघ्रता से ला रही है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा माता-पिता की इस इच्छा पूर्ति को कि उनके बच्चे अंग्रेजी का व्यवहार करने का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले, मायता न देना भी बुद्धिमानी नहीं होगी। यह इच्छा किसी मिथ्या अभिमान के कारण नहीं वरन् इस वास्तविकता के कारण है कि अंग्रेजी का ज्ञान व्यक्ति को देश या विदेश में नौकरी पाने में अधिक सहायक होता है। भाषाई समस्या का कल्पनाहीन रीति से हल करने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और अतः यह देश की अखंडता के लिए सखट उत्पन्न कर सकती है।

आयरलैंड और यूगोस्लाविया में

3 मई, 1982 को मैं एक सप्ताह के लिए आयरलैंड और यूगोस्लाविया के सरकारी दौरे पर गया। मेरे साथ जानेवाले अन्य व्यक्तियों के साथ जहाजरानी मंत्री वीरेन्द्र पाटिल भी थे। आयरलैंड के सरकारी दौरे पर जानेवाला मैं दूसरा भारतीय राष्ट्रपति था। मेरे से पहले सितम्बर, 1964 में डा० राधाकृष्णन् जा चुके थे। जब हमारा विमान आयरलैंड की सीमा पर पहुँचा तो वहाँ की वायुसेना के विमानों ने हमें सुरक्षण दिया। हवाई जड़ों पर उतरने पर आयरलैंड के राष्ट्रपति डा० पट्रिक हिलेरी ने हमारा स्वागत किया। प्रधानमंत्री चात्स हेगे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य तथा डब्लिन नगर के मेयर भी वहाँ मौजूद थे। औपचारिक समारोह के बाद मैं आयरलैंड के राष्ट्रपति के साथ नगर की खूबसूरत सड़कों पर से एक लम्बे चौड़े उद्यान में स्थित राष्ट्रपति के महल की ओर चला। उद्यान में मुझे एक पीछा सगाने के लिए आमंत्रित किया गया। आयरलैंड के राष्ट्रपति के साथ कुछ समय बिताने के बाद मैं अपने सहकारी दल के साथ बकले होटल चला गया, जहाँ हमारे ठहरने का प्रबंध किया गया था।

आयरलैंड के राष्ट्रपति ने उसी शाम मेरे सम्मान में सहभोज का आयोजन किया। उसमें केवल उच्च अधिकारी ही नहीं, भारी मात्रा में वे आयरलैंड वासी भी थे जो किसी समय भारत में रहकर विभिन्न क्षेत्रों में काम करते रहे थे। उनसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। उन लोगों में एक मिशनरी दम्पति भी थे जिन्होंने 25 वर्ष से अधिक मेरे प्रदेश आंध्र क्षेत्र में काम किया था। आयरलैंड के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में दोनों देशों के युगा पुराने सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देशों के लोग स्वतंत्रता, लोकतन्त्र और पूर्ण आजादी में आस्था रखते हैं। उन्होंने कहा कि आयरलैंड सदा से भारत से मंत्री बनाये रखेगा। सत्कार के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और भावना

मंत्रीपूण सबधो का उल्लेख किया और कहा कि हमारे दोनो देशो ने लगभग ही समय तक औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए सघन किया है। मैंने इस का स्मरण कराया कि स्वतंत्रता के लिए सभी स्थानों पर सघन करनेवालों के किस प्रकार आयरलैंड के देशभक्त एमन दी वेलरा प्रेरणा के स्रोत रहे। मैंने राष्ट्रीय स्थिति और आपसी सहयोग की प्रक्रिया के बिगड़ने के सबध में चिन्ता की। मैंने हिंद महासागर में तनाव बढन की स्थिति पर भी प्रकाश डाला और प्रकाश प्रकट की कि अथ देश युद्ध की सम्भावनाओं को दूर करने और शांति क्षेत्र बढने में सहयोग देंगे। इसके साथ मैंने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सबध में प्रकाश डाला। अन्ततः मैंने इस बात पर विश्वास प्रकट किया कि भारत आयरलैंड इन महत्वपूर्ण विषयों पर सहयोग करते रहेंगे।

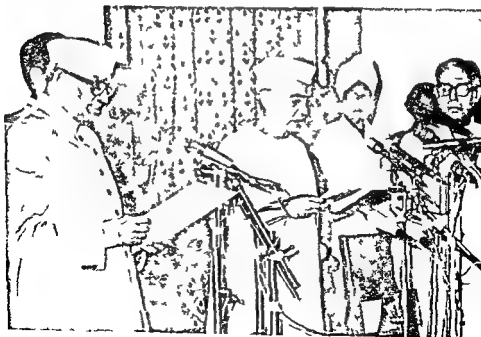
अगले दिन शाहीदो के स्मारक पर जाने का मेरा कार्यक्रम था। वहाँ आयरलैंड सामन्ती ने मेरी अगवानी की। मैंने आयरलैंड के देश भक्तों, जिन्होंने देश की प्रता के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, के सम्मान में पुष्पाञ्जलि अर्पित

मेरा दूसरा कार्यक्रम वहाँ के चैस्टर बेंडी पुस्तकालय का दौरा था। मेरे साथ आयरलैंड की शिक्षामन्त्री थी। वह एक महिला ही थी। उस समय भारत में भी एक महिला ही शिक्षामन्त्री थी। कहा जाता है कि प्राचीन पांडुलिपियों का यह बहुत ही पूण सग्रह है। इसलिए भी यह अदभुत है कि यह सारा सग्रह एक अकेले में ही किया है।

मेरे सम्मान में दोपहर का भोज आयरलैंड के प्रधानमन्त्री चार्ल्स हागी ने जिन किया। उस अवसर पर भाषण करते हुए आयरलैंड के प्रधानमन्त्री ने आदोलन की आधारशिला रखनेवाले सदस्य के रूप में भारत की प्रशंसा की तथा कि उनका देश भी 'यामपूण अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए भारत की सहायता के लिए तयार है। उन्होंने कहा कि आयरलैंड के नेता भारत के राष्ट्रपति ने विश्वव्यापी ज्वलत विषयों पर जो विचार किया है दोनों के एक से विचार हैं। अपने उत्तर में मैंने आयरलैंड और भारत के बीच और भारतीय स्वतंत्रता आदोलन में औपनिवेशिक शासन के प्रति सघन में आयरलैंड के प्रभाव का उल्लेख किया। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भाषा जाननेवाले भारतीयों को बर्नार्ड शॉ, जैम्स जॉयस, सैमुअल बेकर तथा आयरिश लेखकों की पुस्तकों में बहुत रचि है। मैंने इस बात का उल्लेख किया कि तत्र होने पर भारत के सामने कितनी कठिनाइयाँ थी, जिन्हें हमने किस सुनियोजित ढंग से हल किया और जितनी की। मैंने अपने देश की स्वतंत्रता, और लोकतन्त्र की दिशा में विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लक्ष्य को गा।



1. ससद के सट्टल हॉल में दिनांक 25 जलाई 1977 को नीलम सजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हुये भारत के चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग



2. राष्ट्रपति भवन दिल्ली में चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुये

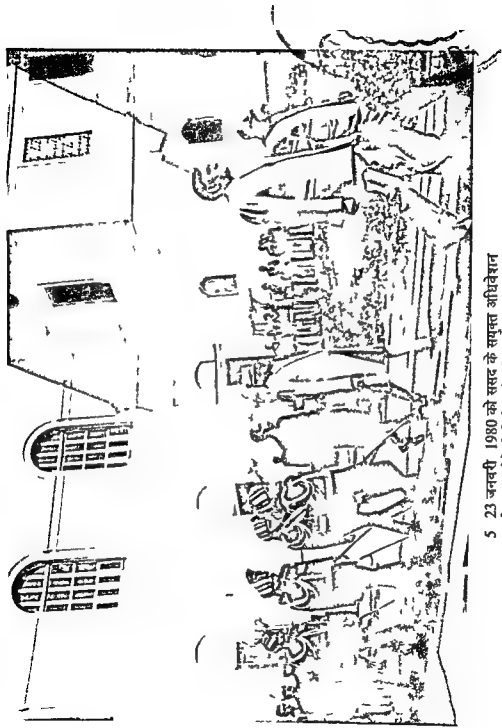


3 एम हिदायतुल्ला को उपराष्ट्रपति की शपथ
मिलाने दिये



4 14 जनवरी 1980 को राष्ट्रपति भवन में इंदिरा
गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हुये

5 23 जनवरी 1980 को ससद के समुक्त अधिवेशन
में भाषण देने के लिये जाते हुये

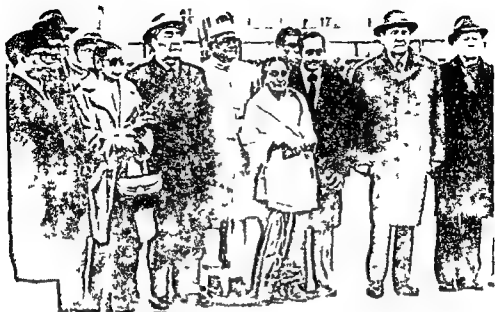




6 मदर टेरसा का राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न की उपाधि प्रदान करते हुये।



7 ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँ से भेट के कुछ मघर क्षण



8 मास्को से विदा होते समय सावियत रूस के सर्वोच्च नेताओं के साथ



9 राष्ट्रपति भवन में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थेचर से भेंट करते हुये



10 लुसाका में जाम्बिया के केनेथ कोडो के सम्मान में आयोजित भोज में



11 अपनी पोती को गोद में लेकर खिलाते हुये



12 नीलकण्ठ पर्वत चोटिया की पृष्ठ भूमि में अपने परिवार सहित बर्दीनाथ यात्रा के दौरान।



13 अगन्तपुर जिले के अपने गाँव इलूरु में माँ और पत्नी के साथ

14 महाबलिपुरम में सागर तट पर



(सभी फोटों टी अशोक के सौजन्य से)

आयरलैंड निवास में अथ कायन्मो के साथ आयरलैंड विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षात समारोह का आयोजन करके मुझे डा० ऑफ सॉ की जो मानद डिग्री दी गई उसका उल्लेख भी करना चाहूंगा। इस प्रकार का सम्मान प्राप्त करनेवाला मैं तीसरी भारतीय था। मुझे पहले जवाहरलाल नेहरू और डा० राधाकृष्णन को यह सम्मान दिया जा चुका था। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि इन दो महान् व्यक्तियों के समान मुझे भी सम्मानित किया गया। हम संक्षिप्त समारोह में आयरलैंड के राष्ट्रपति भी उपस्थित थे।

डब्लिन के मेयर तथा नगरपालिका के सदस्यों ने दो शताब्दियों से चले आ रहे मेयर के सरकारी आवास में मेरा स्वागत किया।

मेरा एक और कार्यक्रम वहाँ के वसंतोत्सव में शामिल होना था जिसे डब्लिन की रॉयल सोसायटी प्रतिवर्ष आयोजित करती है। यह समारोह वहाँ के लोगों में बहुत लोकप्रिय है। जिस दिन प्रातः काल मैं वहाँ गया, हजारों नर-नारी और बच्चे वहाँ घूम रहे थे और विभिन्न दुकानों पर चक्कर लगाते हुए आनन्द ले रहे थे। इस समारोह में मुख्य रूप से कृषि, बागवानी और पशुओं के विकास पर बल दिया गया था। इस भीड़ भड़के में मैंने बहुत आनन्द अनुभव किया। हमारा यह दो समाज के अतीत और वर्तमान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ एक सहभोज के साथ समाप्त हुआ।

आयरलैंड के दौरे के पहले तीन दिन डब्लिन नगर में बीते। मेरे दौरे के अंतिम दिन अर्थात् 9 मई को यूगोस्लाविया से रवाना होने से पहले मुझे आयरलैंड के सुंदर और शांत देहात को देखने का अवसर भी मिला। मुझे बोयन घाटी के निकट न्यू भोज नामक स्थान पर पुरातत्व संबंधी खुदाई देखने का अवसर भी मिला। यह स्थान डब्लिन से मोटर द्वारा एक घंटे की दूरी पर है। मैं ऐतिहासिक महत्व के सुप्रसिद्ध स्थान शिया महल भी गया। शिया पहाड़ी महा न निकट ही है और प्रायः जिसके संबंध में कहा जाता है कि सत्र पट्टिक ने पाचवीं शताब्दी में ईसाई मत की घोषणा इसी पहाड़ी से की थी। महत्वपूर्ण स्थानों को देखने के अतिरिक्त मुझे इस यात्रा की प्रसन्नता है कि मेरे आयरिश मेहमान नवाजों ने उस दिन प्रातः काल का जो कार्यक्रम बनाया था। वह बहुत ही सोच समझकर बनाया गया था जिससे मुझे डब्लिन के आसपास के सुंदर देहात को देखने का अवसर मिला।

मेरे इस दौरे को स्थानीय समाचारपत्रों ने प्रमुख स्थान दिया। वहाँ के सबसे अधिक छपनेवाले दैनिक समाचार पत्र 'आयरिश टाइम्स' ने भारत और आयरलैंड के आपसी सद्भावनापूर्ण संबंधों पर सम्पादकीय लिखा।

बृहस्पतिवार 6 मई को दोपहर बाद मैं बेलग्राद पहुँचा। वहाँ यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा उनके उच्च अधिकारी साथियों ने हमारा स्वागत किया। उसके बाद मैं उस व्हाइट पैलेस के लिए चला जहाँ किसी समय माशल टीटो रहा करते

थे। यूगोस्लाविया दोरे का यह समय बहुत उपयुक्त था क्योंकि वसंत का आगमन हो चुका था। हमारी यात्रा के अंतिम दिन को छोड़कर मौसम बहुत अच्छा रहा और धूप निकली हुई थी। न्हाइट पैलेस के आसपास का दृश्य भी अच्छा था और वृक्ष, पौधे अपनी पूरी बहार में थे।

यूगोस्लाविया पहुँचने के पौरन बाद मैं माशल टीटो की समाधि पर गुण्याजति अर्पित करने गया। मेरा दूसरा वायत्रम यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति तथा उनके सहायकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका के संबंध में विचार करना था। उसके बाद यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने मेरे सम्मान में एक भोजन का आयोजन किया। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने वहाँ भाषण में कहा कि फौरन ऐम प्रयत्न किये जान चाहिए कि तटस्थ राष्ट्रों के आपसी सघप समाप्त हो और उनकी समस्याओं का समाधान पूणत शांतिपूण ढंग से करने के उपाय खोजे जायें। उन्होंने विशेष रूप से ईरान और इराक के आपसी युद्ध का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आगामी सितम्बर मास में बगदाद में होनेवाले तटस्थ राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखात हुए यह युद्ध फौरन बंद होना चाहिए। मैंने अपने उत्तर में उनकी बात से सहमति प्रकट की कि तटस्थ राष्ट्रों के आपसी सघप समाप्त होने चाहिए। मैंने अपनी बात को अधिक जोर देते हुए कहा कि किसी भी समझौते के लिए पूणत शांतिपूण बातचीत हानी चाहिए। मैंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि विभिन्न शक्ति गुटा में जो अंतर्राष्ट्रीय तनाव और सघप बन रहा है इससे विश्व को आणविक सवनाश का खतरा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तटस्थ राष्ट्रों के नेता सदबुद्धि का प्रचार करें। मैंने यह स्पष्ट किया कि तटस्थ आंदोलन को प्रारम्भ करनेवाले भारत और यूगोस्लाविया ने सदैव आपसी सहयोग और सदभावना बढ़ाने का पक्ष लिया है। तटस्थ राष्ट्रों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे विकसित और विकासशील देशों को आपस में एक-दूसरे पर आश्रित रहन का विश्वास दिलायें। मैंने वस्तुओं और सवालों के जादान प्रदान के संबंध में स्पष्ट और पक्षपातपूण भेदभाव का उल्लेख किया और यह कहा कि इस प्रकार की बातें मानव समाज की शांति और प्रगति के माग में रखावट हैं। मैंने जवाहरलाल नेहरू और माशल टीटो के आपसी सहयोग और तटस्थ आंदोलन के निर्माण में उनके योगदान का स्मरण करवाया। मैंने स्पष्ट कहा कि भारत और यूगोस्लाविया में उनके बाद के नेताओं ने भी दोनों देशों की मत्री क उन सूत्रों को दब किया है। मैंने यूगोस्लाविया की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उस ने आर्थिक और औद्योगिक संस्थानों में काम करनेवालों को भागीदारी की भावना और उनके द्वारा प्रवर्ध समालने की व्यवस्था की है। मैंने यह कहकर अपना भाषण समाप्त किया कि राष्ट्रपति टीटो ने अपने पीछे जो एक समृद्ध परम्परा छोड़ी है वह यूगोस्लाविया के नेताओं और जनता का हर क्षेत्र में माग दर्शन करती रहेगी।

अगले दिन प्रातः काल मैं माउंट अवाला पर बजात सैनिकों की समाधि पर फूल चढ़ाने गया। यह स्थान वेलग्राड से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। यह समाधि पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और वहां से नगर का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। उसके बाद वेलग्राड के मेयर तथा नगर-सभा ने मेरा नागरिक अभिनन्दन किया और नगर का एक स्वर्ण चिह्न भेंट किया। यह मेरे लिए एक और अवसर था जब मैंने माशल टीटो और जवाहरलाल नेहरू के तटस्थ राष्ट्रों और विश्व शांति के लिए किये गये योगदान की प्रशंसा की। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि 1950 में माशल टीटो जब भारत के दौरे पर आये थे, तो हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उनकी अगुवानी की थी और मैंने उस प्रसन्नता का भी जिक्र किया कि यूगोस्लाविया के पहले दौर में मैं माशल टीटो से मिला भी था। मैंने वेलग्राड और नई दिल्ली नगरों की समानता का भी जिक्र किया जहां पर पुरातन ऐतिहासिक स्मारक और आधुनिक भवन साथ-साथ दिखाई देते हैं जिनसे हमें एक नजर में सदियों पुरानी ऐतिहासिक परम्परा का ज्ञान होता है। मैंने द्वितीय विश्व युद्ध में वेलग्राड में हुए विनाश का भी जिक्र किया और कहा कि उसका आधुनिक राजधानी के रूप में पुनर्निर्माण यहां के निवासियों के उत्साह और दृढ़ धारणा का प्रतीक है।

मैंने नगर के फ़ैडशिप पार्क में साल ओक वृक्ष का पौधा भी लगाया। यह पार्क 14 हेक्टेयर में फैला हुआ है। विभिन्न दशों के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने यहां वृक्षारोपण किया है। शाम के समय यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति से और आगे विचार विमर्श हुआ और रात्रि भोज का आयोजन किया गया।

11 मई की प्रातः काल में वेलग्राड से बोसनिया हर्जगोविना गणतन्त्र की राजधानी सेराजीवो के लिए चला। राष्ट्रपति ने वहां पहुंचने पर मेरी अगुवानी की। सेराजीवो अपने शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है और 1984 के ओलิมपिक के शीत ऋतु से संबंधित खेल वहां आयोजित होने वाले थे। मुझे वहां महत्त्वपूर्ण इंजीनियरिंग से संबंधित उद्योग दिखाए गए, जहां बहुत ही सूक्ष्म चीजों का निर्माण रूस तथा अन्य देशों को निर्यात के लिए किया जाता है।

यहां के विश्वविद्यालय ने मुझे डॉ॰ ऑफ साइंस की मानद डिग्री दी। कुछ समय पूर्व यह सम्मान माशल टीटो को दिया गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि वही सम्मान जो एक सुप्रसिद्ध देश भक्त स्वतंत्रता सेनानी और विश्व प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ को दिया गया था, उससे मुझे भी सम्मानित किया गया। जिस सभा में यह समारोह हुआ वह बहुत ही बढ़िया ढंग से सज्जित था। इस अवसर पर भाषण करते हुए मैंने भारत तथा अन्य विकासशील देशों से विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्र में प्रतिभा-प्रत्यायन का उल्लेख किया। मैंने यूगोस्लाविया की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने शिक्षा प्रक्रिया को समाजवादी विकास की व्यापक प्रक्रिया

से जोड़ दिया है। मैंने यूगोस्लाविया की प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था की भी प्रशंसा की जिससे बच्चा मे अपने कर्तव्य और दायित्व को समझने की भावना उत्पन्न होती है। यह बात अनुकरणीय है। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया कि वर्तमान की यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो देश को विश्वभर में फले विज्ञान सबधी उन्नत ज्ञान का पूर्ण लाभ प्राप्त हो।

मैंने राष्ट्रपति तथा वहाँ के अन्य महत्वपूर्ण प्रमुख अधिकारियों से अनवरत विषयो पर विचार विमर्श किया। उसके बाद मेरे सम्मान में दोपहर के भोज का आयोजन किया गया।

दोपहर बाद मैं वहाँ के क्रांतिकारियों से संबंधित सुप्रसिद्ध भवन गया। वहाँ आस्ट्रो हंगेरियन शासन के विरुद्ध प्रयुक्त की गई वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था। प्रथम विश्वयुद्ध के मूल में यहाँ की घटनाएँ थी। उसके भवन के पास ही बनी एक सौ साल पुरानी मस्जिद भी मैंने देखी। नगर की सड़कों पर दोनों ओर प्रसन्न भीड़ खड़ी थी। इस भीड़ से यह स्पष्ट दिखाई देता था कि यह पूर्व और पश्चिम का एक सुंदर मिश्रण है। उसके बाद हम एड्रियाटिक समुद्र तट पर बसे क्रोशिया गणतंत्र के स्थित नगर के लिए विमान से रवाना हुए।

स्थलित में, मैं समुद्रतट स्थित उस भवन में गया जहाँ प्रायः माशल टीटो ठहरा करते थे। स्थलित समुद्र तट बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। नगर में अन्य दर्शनीय स्थान भी हैं। इनमें यूगोस्लाविया के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार मैसतरोवीक द्वारा बनाई गई मूर्तियों की प्रदर्शनी और एक पुरातत्त्व संग्रहालय हैं।

अगले दिन नाव द्वारा निवृत्त स्थित त्रागिर द्वीप नगर में जाने का कार्यक्रम था परंतु बादलों और वर्षा के कारण इसे छोड़ देना पड़ा। शाम को क्रोशियन राष्ट्रपति जिन्होंने माशल टीटो के साथ एकजुट होकर आक्राताओं के विरुद्ध संघर्ष किया था—ने मेरे सम्मान में भोज का आयोजन किया। दोनों ओर से माशल टीटो और पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिनकी दूर दृष्टि और कूटनीति के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी जा सकी थी।

सोमवार १० मई को मैं भारत के लिए रवाना हुआ।

सार्वजनिक समारोह कुछ विचारणीय प्रश्न

मैं अगस्त 1981 के अन्त की अवधि में, सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में 31 अक्टूबर को 'सिटीजन काउन्सिल' नामक एक संस्था द्वारा आयोजित समारोह में भाग लेने तथा राष्ट्रीय एकता पर सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर देने के लिए सहमत हो गया। 'सिटीजन काउन्सिल' एक विशाल संस्था थी जिसमें दिल्ली के अनेकों प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल थे। 31 अक्टूबर का होने वाला समारोह 'सिटीजन काउन्सिल' के एक छोटे से समूह 'सिलीब्रेशन कमेटी', सरदार पटेल जयंती समारोह' द्वारा आयोजित किया जाने वाला था। इसमें धर्मवीर, कवर लाल गुप्ता और एक अन्य व्यक्ति थे। धर्मवीर जैसा कि सभी जानते हैं 'इंडियन सिविल सर्विस' के एक विशिष्ट सदस्य थे और अपनी लम्बी सेवा अवधि में वे अनेकों महत्वपूर्ण पदों, कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर भी रहे थे। वह उस समय पश्चिमी बंगाल के (गवर्नर) राज्यपाल थे जबकि राज्य एक राजनैतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था और नाजुक संवैधानिक एवम् राजनैतिक विषयों पर निर्णय लेने थे। वह राज्य उनके राज्यपाल की अवधि के एक भाग में राष्ट्रपति शासन के अधीन था। कवरलाल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और यह मैं जानता था।

अक्टूबर के मध्य या उसके आस पास एक सर्वोच्च सरकारी अधिकारी ने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से टेलीफोन पर बात की और जानकारी के लिए पूछा कि क्या मैं उक्त समारोह में सम्मिलित होने के लिए सहमत हो गया हूँ। उसने आगे कहा कि समारोह में मेरे शामिल होने से उत्पन्न राजनैतिक उत्पत्तियों से सरकारी क्षेत्रों में कुछ अप्रसन्नता है। मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उसको बताया कि मैं लगभग दो माह पूर्व उक्त समारोह में शामिल होना स्वीकार किया था, कि आयोजकों के राजनैतिक पार्टियों से सम्बन्ध राष्ट्रपति को समारोह में जाने से रोकने का कारण नहीं बनने चाहिए, कि समारोह का आयोजन राष्ट्र के एक विशिष्ट पुत्र सरदार पटेल के सम्मान में हो रहा है कि धर्मवीर जैसे सेवा निवृत्त कैबिनेट सेक्रेटरी

और पूर्ववर्ती राज्यपाल द्वारा समारोह को दिये जाने वाले सहयोग से यह पता चलता है कि समारोह राष्ट्रपति के स्तर योग्य होगा, और राष्ट्रपति के उसमें सम्मिलित होने से किसी प्रकार की आलोचना नहीं होनी चाहिए। उसने आगे कहा कि राष्ट्रपति कभी ऐसे समारोह में सम्मिलित होने को सहमत नहीं होंगे जब तक कि उन्हें यह विश्वास न हो कि इससे उनके पद की गरिमा कम नहीं होगी।

कुछ दिनों बाद केबिनेट मिनिस्टर पी० शिवशंकर ने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उनके विषय पर बातचीत की। पहले अवसर की भांति उनको भी सारी पष्ठ भूमि समझा दी गई। उनको सूचित किया गया कि क्योंकि यह कार्यक्रम लगभग दो माह पूर्व स्वीकार किया गया था, इस संबंध में इससे अधिक कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बाद में मुझे सूचित किया कि केबिनेट मिनिस्टर ने इस विषय पर अपनी आपत्ति तथा अप्रसन्नता प्रकट की है।

मैं नहीं जानता कि किसके कहने पर पहले उच्च अधिकारी ने और बाद में केबिनेट मिनिस्टर ने मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुझे समारोह में भाग न लेने की कोशिश करने के स्पष्ट उद्देश्य से बातें की। यदि किसी ने यह विचार था कि मुझे अपने कार्यक्रम को रद्द करने के लिए मनाया जा सकता है तो वह गलती कर रहा था। मैं नहीं सोचता कि इस विषय में प्रधानमंत्री किसी प्रकार से संबंधित रहेंगे। यह विचार जरूर उनकी व्यवस्था के किसी अत्यधिक द्वेषपूर्ण कार्यकर्ता का रहा होगा जिसे यह नासमझी भरा विश्वास होगा कि समारोह के आयोजकों में से एक जो जनता पार्टी का था, वह इस आयोजन से राजनैतिक लाभ उठा सकता है। उन्होंने शायद यह विचार होगा कि यदि भरा उसमें जाना रुक्वा दिया जाय तो उन्हें प्रशंसा मिलेगी। यह धारणा पूर्णतः मूर्खता भरी थी। मेरे समारोह में भाग लेने में मल्लत या असाधारण क्या था? स्वतंत्रता संग्राम में सरदार पटेल का योग और भारत को शक्तिशाली बनाने के उनके प्रयत्न निश्चित रूप से हमें उनके जन्मदिवस पर श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। वह कबल एक सम्मेलन था जिसमें पार्टी की वफादारी से ऊपर उठ कर सारे राष्ट्र को उन्हें और उनकी देश सेवा को स्मरण करना चाहिए था। यदि सत्ताधारी पार्टी और सरकार में स्वयं कोई समारोह आयोजित करने की कल्पना शक्ति नहीं थी तो इसके लिए वे स्वयं दोषी थे। एक राष्ट्रपति के रूप में, मुझे कोई सन्देह नहीं कि उस समारोह में जाना स्वीकार कर मैंने उसी प्रकार सही कार्य किया जिस प्रकार मुझसे पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियां ने 'सिटीजन वाउचर्स' द्वारा आयोजित सरदार पटेल के जन्म दिवसों पर जाकर किया था।

मेरे भाषण का विषय राष्ट्रीय एकता था। इस अवसर पर मैंने जो भाषण दिया उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि इसे अधिकांश ने सराहा, कुछ आलोचना

भी हुई। आलोचकों ने सत्ताधारी पार्टी के कुछ सदस्य भद्रसिंहिलिखित में यह दूसरे दिन पूर्ण विस्तार से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और अंग्रेजी भाषा के अधिकांश राष्ट्रीय दैनिकों और कुछ साप्ताहिकों ने अपने संपादकीय में इस पर अपने विचार प्रकट किए। विषय के महत्व तथा इसने उम्र समय जो ध्यान आकर्षित किया दोनों ही कारणों से मैं उस पर यहां संक्षेप में लिखना उचित समझता हूँ।

मैंने अपने भाषण के परिचय वाले अंश में सरदार पटेल के साथ अपने संपर्कों का तथा राष्ट्र के प्रति उनकी स्वतंत्रता सज्जानी और कैबिनेट मंत्री के रूप में की गई सेवाओं का वर्णन किया। मुख्यतः क्योंकि राष्ट्रीय एकता पर ध्यान देने के लिए कहा गया था, मैंने कहा कि इस विषय पर मायब विचार करने के लिए, मेरे लिए राज्य-केन्द्र के संबंधों की समस्या की जांच करना आवश्यक है। इस विषय पर मैंने जो विचार प्रकट किए उन्होंने ही विरोध पूर्ण आलोचना को आकर्षित किया। मैंने बहुत अधिक फैली हुई इस भावना को प्रकट किया कि राज्य सरकारों को सामाजिक सेवाओं और विकास के विषयों पर जो उत्तरदायित्व दिए गए हैं उनका अनुरूप विस्तृत और लचीले राज्य कर व साधन उनके पास नहीं। मैंने यह भी कहा कि केन्द्र की रक्षान विकास और शासन के अधिक स अधिक विषयों का उत्तरदायित्व स्वयं लेने की है जो कि विकेंद्रीकरण के स्वीकृत सिद्धान्त के प्रभाव को घटाती है। केन्द्र के पास राज्य में उपलब्ध सरकारी सत्त स अधिक कुशल और भिन्न तंत्र नहीं है और न अनुभव यह बताता है कि केन्द्र ने राज्यों की तुलना में अधिक बुद्धिमानी, योग्यता या बाह्य तत्वों के प्रभाव में स्वतंत्रता प्रदर्शित की है। राज्यों ने केन्द्र की इस प्रवृत्ति का कभी पसंद नहीं किया है कि वह अधिक से अधिक शक्ति लेता जाता है तथापि राजनैतिक और अन्य कारणों से उन्होंने अपनी इस भावना को प्रकट नहीं किया है। यदि इस प्रवृत्ति को रोका नहीं गया तो राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग बढ़ती के साथ उठायी जा सकती है। यह एक अवांछित विकास होगा। इसलिये मैंने तब दिया कि केन्द्र-राज्यों के संबंधों की पूरी समस्या का नया सिर स पिछले तीस वर्षों के अनुभवों के प्रकाश में अध्ययन होना चाहिए। प्रारम्भ में मैंने संविधान निर्मात्री सभा के वाद-विवादों और केन्द्र तथा राज्यों के संबंधों पर राजामानार कमेटी रिपोर्ट का उल्लेख कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद स देश का अपनी एकता से जो लाभ हुए हैं उनको बताने से भी मैं चूका नहीं था। दश में विभाजन करनेवाली शक्तियों के विकास पर मैंने गंभीर अप्रसन्नता प्रकट की थी। मैंने जा कुछ कहा था उसमें वास्तव में नया कुछ नहीं था। मैंने स्वयं उन बातों को उससे पूर्व भी कहा था और वंसा ही दूसरों ने भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसीडेंट रूप में, सन् 1960 के प्रारम्भ में कांग्रेस के 'प्लेनरी' सेशन में दिए गए मेरे भाषण का निम्नलिखित अंश मेरी

पुष्टि करेगा

एक प्रजातांत्रिक प्रणाली की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि सरकार जनता की ओर जनता के लिए ही नहीं धरन् जनता के द्वारा भी होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जनता जिसमें सर्वोच्च सत्ता निहित है उसको अवश्य ही ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वह अपने आपको शासित कर सके।

×

×

×

सन्देह नहीं कि हमारे गांव में लड़ाई झगड़े और विवाद होते हैं लेकिन लड़ाई-झगड़े और विवाद बदल गांवों में ही सामान्य नहीं।

×

×

×

एक बार जब जनता को बिना किसी प्रतिबंध के उत्तरदायित्व दे दिया जाता है, वह प्रायः अपने को उसके अनुकूल बना लेती है और मुझे विश्वास है कि वह अपने कर्तव्यों का पूरी तरह भली प्रकार पालन करेगी। और तभी हम इस देश में पूर्ण स्वतंत्रता ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि आंध्र और राजस्थान ने यह महान प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है जो कि अब एक वप पुराना है और जो एक उल्लेखनीय सफलता प्रमाणित हुआ है। मैं अवश्य आशा करता हूँ कि देश के दूसरे राज्य भी उनका अनुकरण करेंगे।

इस सम्बन्ध में कुछ दृष्टिकोण प्रकट किये गये हैं कि शक्ति के विकेंद्रीकरण का अर्थ केवल राज्य से जिले और ग्राम स्तर तक नहीं परन्तु उसके अनुसार ही दिल्ली और राज्यों के मध्य भी होना चाहिए। हाल ही में वर्धा में हुए सर्वोच्च सम्मेलन में कहा गया था कि जो स्वतंत्रता हमारे देश में आयी है वह नई दिल्ली में उसी प्रकार अटक कर रह गयी है जिस प्रकार गंगाजी भागीरथ के महान् प्रयत्नों से नीचे आने पर शिवजी की जटाओं में रह गयी थीं और यह आवश्यक है कि शिव जी पुनः इस गंगा को अपने कानों से निकलने की अनुमति दें और उसे कुमारी भूमि को उपजाऊ बनाने की आज्ञा दें। यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है और यह सत्य कि इस प्रकार के दृष्टिकोण प्रकट किये जा चुके हैं, यह बताता है कि लोगों के मस्तिष्क उस दिशा में विचार करने लगे हैं।

मेरे आलोचकों ने मेरे द्वारा अनुचित समय पर राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का तक दिये जाने का आरोप लगाया, एक ऐसे समय जबकि भारत सरकार के हाथों में आसाम में विदेशियों को लेकर उठे आन्दोलन से बनी समस्या और खालिस्तान की मांग से निपटने की समस्या है। उन्हें यह विचित्र लगा कि मैं राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता का तक ऐसा समारोह मँदिया जो शक्तिशाली केन्द्र के समर्थक सरदार पटेल की स्मृति में मनाया जा रहा था। उन्होंने गलत रीति से

यह धारणा बना ली थी कि शक्तिशाली केन्द्र का अर्थ दिल्ली में शक्ति का केन्द्रीकरण करने से है और राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना केन्द्र को कमजोर करना होगा। उसके विपरीत मेरा विश्वास है कि केन्द्र राज्यों से उनकी पहल कराने और नियंत्रण करने की शक्ति सेवर शक्तिशाली नहीं बनता, वह केवल सभी शक्तिशाली होता है जब राज्यों को अपनी प्रशासनिक और विवास की समस्याओं को स्वयं हल करने की क्षमता और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। केन्द्र को मुख्य रूप से अपना समय तथा ध्यान अखिल भारतीय समस्याओं को हल करने में लगाना चाहिए।

उस समय जो दूसरी घटना हुई उसका वर्णन करने की भी आवश्यकता यहाँ है—

सरकार के उच्च अधिकारी ने (जिसके संबंध में पहले जिन आ चुका है) मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताया कि कुछ क्षेत्रों में मेरे द्वारा मध्य प्रदेश की बार बार यात्रा करने पर कुछ भ्रम है। वह जानना चाहता था कि क्या मैंने सीधे ही ग्वालियर यात्रा करने की योजना बनाई है और उसके तीन सप्ताह के अन्दर राय पुर दोबारा जाने की? उसको बताया गया कि मैं नवम्बर के अंत में ग्वालियर जाने और वहाँ के स्थानीय बालिका स्कूल के रजत जयन्ती समारोह में भाग लेने के लिए सहमत हो चुका हूँ। ग्वालियर का स्कूल ग्वालियर की राजमाता से संबंधित था। वह एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है और उसकी नींव का पत्थर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा रखा गया था और उसका उद्घाटन श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा हुआ था। अपने राष्ट्रपति कायकाल में मेरी परंपरा प्रायः उन्हीं कार्यक्रमों में भाग लेने की सहमति देने की थी जिन्हें राज्य सरकार राष्ट्रपति के भाग लेने योग्य समझती थी। ऐसे सभी कार्यक्रमों में प्रायः राज्यपाल या मुख्यमंत्री अथवा दोनों ही सम्मिलित होते थे। इस घटना में मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने ग्वालियर स्कूल समारोह में भाग लिया और स्कूल की प्रशंसा में बोले। ग्वालियर की राजमाता के राजनैतिक संबंधों से मुझे कोई मतलब नहीं था। मेरे लिए उनका विरोधी दल का सदस्य होना ऐसा पर्याप्त कारण नहीं था जिसके आधार पर मैं एक ऐसे स्कूल के रजत जयन्ती समारोह में जाने से इंकार कर देता जिसका प्रारम्भ अच्छे उत्साहवादी भावों में हुआ था और जो अच्छी नीतियों पर चलने के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे स्कूल के समारोह में मेरी उपस्थिति से किसी का गलतफहमी में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी।

यह घटना मुहत्त्वहीन प्रतीत हो सकती है परंतु मैंने यहाँ इसका वर्णन यह दिखाने के लिए किया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय के कुछ अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से स्वयं अपने नियमों के आधार पर मेरे सावजनिक कार्यक्रमों को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। यह बोशिश पूर्णतः गलत रीति से विचारों गई थी और मैं केवल यह आशा कर सकता हूँ कि यह प्रधानमंत्री की जानकारी अथवा

सहमति से नहीं की गई थी। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता। किसी का यह विचारना कि राष्ट्रपति को केवल सत्ताधारी पार्टी द्वारा आयोजित समारोह में ही भाग लेना चाहिए केवल वचनमात्र है। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी समारोह में जाने के लिए स्वतंत्र है और हाना चाहिये। उसको केवल इस आधार पर नियम लेना चाहिए कि क्या समारोह उसके पद की गरिमा के अनुकूल है।

केन्द्र में सत्ता और नियम लेने की शक्ति के एकीकरण हो जाना संसदीय व्यवस्था की क्षति है वह केन्द्र और अधिकांश राज्यों में सत्तासीन कांग्रेस (आई) पार्टी की कार्यप्रणाली द्वारा देखी जा सकती है। राज्य की विधान सभा पार्टी का नेता विधान सभा पार्टी के सदस्यों द्वारा नहीं बरतें परन्तु आई कमण्ड या पार्टी नेता द्वारा चुना जाता है। जब इच्छानुकूल व्यक्ति मिल जाता है तब कुछ समय के लिए छोटे हुए ऐसे व्यक्ति का सदस्यो द्वारा चुनाव करने का आश्चर्य किया जाता है। इससे कोई धोखा नहीं आता, चुना गया प्रतिनिधि तब नहीं। इस प्रकार चुना व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है और राज्य में सरकार बनाता है। उस न तो अपन मंत्रिमंडल (केबिनेट) की शक्ति या निर्माण के संबंध में कोई स्वतंत्रता होती और न मंत्रियों को विभाग देने के बारे में ही। यह रीति जनतांत्रिक प्रणाली के सभी विचारों के इतने प्रतिबल है कि मैं अपन एक भाषण में उन्हें 'मनोनीत मुख्यमंत्री' कहने से स्वयं को रोक नहीं सका। (आशा के अनुरूप मेरी स्पष्ट आलोचना न सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को नाराज कर दिया) उनमें से कुछ जनता में यह घापित करते हुए सज्जित नहीं होते कि उनका पदासीन बने रहना पार्टी के विधान सभा सदस्यों या विधान सभा के विश्वास पर नहीं बरतें पार्टी प्रमुख पर निर्भर करता है। जनतंत्र की क्या विडम्बना है। पार्टी अवश्य ही अपने विधायकों पर यह विश्वास कर सकती है कि वे अपने में सबसे उभयुक्त व्यक्ति को अपना नेता चुनेंगे। यदि वह उन पर विश्वास नहीं कर सकती तो यह उसके द्वारा चुनाव के लिए खड़े किये जान वाला का मनोनीत करने की प्रणाली पर शका उठाता है।

पहले जो कुछ हाता था यह सब दुःखद रूप से उसके विपरीत है। मुझे स्मरण आता है कि सन 1946 में विस प्रचार टी० प्रकाशम न मद्रास में कांग्रेस विधान सभा पार्टी का नेता बनने के लिए महात्मा गांधी तक की इच्छा के विरुद्ध, जो कि उस पद के लिए राजगोपालाचारी के पक्ष में थे, चुनाव लड़ा और जीता था। संयुक्त मद्रास राज्य से आग्र के अलग होने के तुरंत बाद शेष बचे मद्रास राज्य की कांग्रेस विधान सभा पार्टी के नेतृत्व के लिए के० कामराज और सी० सुब्रह्मनियम के बीच निर्वाचन हुआ था। दिल्ली में पार्टी नेताओं द्वारा इस निर्वाचन को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। कामराज विजयी हुए और मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में सुब्रह्मनियम को ही नहीं बरतें अन्य अनुभवी व्यक्तियों को भी लिया। आंध्र प्रदेश बनने पर मैं स्वयं बी० गोपाल रेड्डी के विरुद्ध विधान

सभा पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ा और जीता था तथा मैं राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बना था। दिल्ली में पार्टी के नेताओं द्वारा इस चुनाव के प्रति किसी प्रकार की आपत्ति नहीं उठाई गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, 'जो भी निर्वाचित हुआ है, वह मेरा आदमी है।' चुनाव के बावजूद भी मैंने अपने मन्त्रिमण्डल में ऐसे कुछ लोगों को शामिल किया जिनके बारे में मुझे पता था कि उन्होंने मेरे विरुद्ध मतदान किया था। मुझे पार्टी को सगठित रखने में कोई कठिनाई नहीं हुई थी। जब मैंने गोपाल रेड्डी से मन्त्रिपरिषद् में शामिल होने का अनुरोध किया तो वह मान गये थे।

आज हम देखते हैं कि कांग्रेस (आई) के मनोनीत मुख्यमंत्री पार्टी को एकजुट रखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। यह आश्चर्यजनक नहीं क्योंकि उन्हें पार्टी विधायकों का विश्वास पाने के कारण नहीं बल्कि दिल्ली स्थित पार्टी हार्दिकमाह का विश्वासपात्र होने के कारण अपना पद प्राप्त होता है। ये मुख्यमंत्री प्रशासन काय करने के लिए बैठ नहीं पाते क्योंकि मन्त्रिमण्डल बनाना अपने आप में एक लम्बा काय है। मुख्यमंत्री के पदासीन होने के कुछ सप्ताहों के बाद ही विरोधी अपना सिर उठाने लगते हैं और यह स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री का सारा समय अपने पद को बनाये रखने के प्रयत्नों में व्यतीत हो जाता है। पार्टी के छोटे छोटे झगडा तथा पेशीदा विवादों के बारे में, तथाकथित पार्टी हार्दिकमाह अर्थात् पार्टी नेता से बात करने हेतु जनता के खर्चे पर अनगिनत दिल्ली यात्राएँ करनी पड़ती हैं। पार्टी नेता के रूप में प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के चुनाव में गहरा लगाव और उन लोगों का अपने पद पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री पर पूरी तरह निर्भर रहना केवल उनकी निणय लेने की शक्ति और आत्मिक प्रेरणा को रोकता ही है।

मैं पार्टी की काय प्रणाली के सबंध में और अधिक कह सकता था परन्तु राष्ट्रपति के रूप में इससे मेरा कोई सबंध नहीं था। सामान्यतः यह जानना कि पार्टी किस प्रकार काय करती है जनता की रुचि का विषय नहीं होता। तथापि पार्टी की काय प्रणाली के विविध तरीकों और सब निणयों को करने की शक्ति का एक व्यक्ति के हाथों में एकत्रीकरण होने से प्रशासन को इतनी हानि हो चुकी है कि जनता को सत्ताधारी पार्टी के कार्यों पर ध्यान देना ही पड़ेगा। यह अत्यंत दुःख का विषय है कि प्रधानमंत्री जिसको अपना ध्यान और समय देश की पेशीदा आर्थिक स्थिति, कानून तथा व्यवस्था की गम्भीर समस्याओं और बाधाएँ डालने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर देना चाहिए, उसे पार्टी के छोटे छोटे झगडों को निपटाने के लिए कहा जाये। यह कल्पना करना अवास्तविकता की अति है कि एक व्यक्ति चाहे वह कितना भी परिश्रमी तथा योग्य हो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पूरा भारत जैसे विशाल एवम् भिन्नतापूर्ण देश का प्रशासन चला सकता है। प्रशासन और पार्टी विषयों में विवेकीकरण तथा सच्ची जनतात्त्विक कायप्रणाली—केवल इनसे ही जनता को सन्तोष प्राप्त हो सकता है।

असम और दिल्ली दोहरे मानदण्ड

दिसम्बर 1979 में यह आवश्यक हो गया कि असम में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए क्योंकि मन्त्रिमंडल अपना बहुमत खो चुका था। राष्ट्रपति शासन दिसम्बर, 1980 तक रहा और जब राष्ट्रपति शासन समाप्त किया गया तो श्रीमती तैमूर के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) ने मन्त्रिमंडल बनाया। यह मन्त्रिमंडल जून, 1981 तक रहा फिर राज्य में दुबारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 30 जून, 1981 का हुई उस समय की घटनाओं के संबंध में यहाँ विचार की आवश्यकता नहीं है।

अक्टूबर, 1981 में असम राज्य के दौर पर गया। शनिवार 24 अक्टूबर को मैं काजीरंगा में था और असम के राज्यपाल भी मेरे साथ थे। उस शाम को असम विधानसभा के सदस्यों का एक दल, जिसे वामपक्षी और लोकतांत्रिक संयुक्त दल कहा जाता था मुझसे मिला और मुझे एक मांग-पत्र दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि विधानसभा में उनका बहुमत है और वे सरकार बनाने की स्थिति में है। उन्होंने इस बात का भय प्रकट किया था कि उनके बहुमत में होने पर भी इस बात की संभावना है कि अल्पमत सरकार बना दी जाएगी। उसी शाम श्रीमती तैमूर भी मुझसे मिली और उन्होंने भी मुझे मांग पत्र पेश किया जिसमें उन्होंने मांग की कि वे सबसे बड़ी पार्टी की नेता हैं इसलिए उन्हें मन्त्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया जाना चाहिए। इस मार घटनाक्रम में असम के राज्यपाल मेरे साथ थे। इन मांग पत्र पेश करने वालों से मैंने कहा था कि संविधान अनुसार यह राज्यपाल का अधिकार होता है कि वह स्थिति का जायजा लें और विभिन्न दलों तथा संयुक्त पार्टियों की स्थिति का पता लगाए कि बहुमत का समर्थन किसे प्राप्त है और किसके नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर दिया जाए, राज्यपाल ही स्थिति के अनुरूप इस बात की सिफारिश कर सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन समाप्त किया जाए।

13 जनवरी, 1982 को राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन समाप्त

किया गया। उसी दिन केशवचन्द्र गोर्गोई के नेतृत्व में कांग्रेस (आई) मन्त्रिमंडल बना। 17 फरवरी को वामपंथी और लोकतान्त्रिक संयुक्त दल, जिसमें असम के दो पूर्व मुख्यमंत्री शरतचन्द्र सिन्हा और गोपाल बारबोरा थे, मुझसे नई दिल्ली में मिले और मुझे एक स्मरण-पत्र दिया। जिसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नर ने 119 सदस्यों वाले सदन में 62 सदस्यों के बहुमत वाले एक दल की उपेक्षा की है और उम्मेद मन्त्रिमंडल बनाने का अवसर न दे करके अल्पमत को मन्त्रिमंडल बनाने का अवसर दिया है। उन्होंने शरतचन्द्र सिन्हा और राज्यपाल के मध्य हुए पत्र व्यवहार की प्रतिया भी मुझे दी।

मेरे आदेश अनुरूप मेरे सचिवालय ने यह सारे कागजात प्रधानमंत्री के सचिवालय को भेज दिए। उस समय इस घात का कोई संकेत दिखाई नहीं देता था कि असम विधानसभा का अधिवेशन निकट भविष्य में बुलाया जाएगा। प्रधानमंत्री के सचिवालय को कागजात भेजते हुए मेरे आदेश के अनुरूप मेरे सचिवालय ने 18 फरवरी, 1982 को यह लिखा

राष्ट्रपति की धारणा है कि मैमोरडम में किए गए दोपारोपणा पर विचार करने से कोई लाभ न होगा परंतु यह उचित होगा कि विधानसभा का अधिवेशन जितनी जल्द संभव हो बुलाया जाए ताकि इस प्रश्न का निणय हो सके कि जो मन्त्रिमंडल बना है, बहुमत उसके साथ है या नहीं। इसके अतिरिक्त आगामी वष का बजट भी शीघ्र पेश किया जाना है। इसलिए आवश्यक है कि अनुदान व एप्रोप्रियेशन आदि बिल माच की समाप्ति से पूर्व पारित कर दिए जायें। संवैधानिक आवश्यकता और सरकारी कार्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि विधानसभा का सत्र जल्द से जल्द इस महीने के अंत तक अथवा अगले महीने के प्रारंभ में बुलाया जाए।

8 मार्च को गृह मंत्रालय ने मेरे सचिवालय को यह सूचना दी कि असम विधानसभा की बैठक 17 मार्च को होगी और इस बात की सूचना प्रसारित कर दी गई है।

17 मार्च को विधानसभा का सामना किए बिना ही उस मन्त्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। अगले दिन राज्यपाल ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी और मुझे यह सुनाव दिया कि विधानसभा भंग करके राज्य में फिर से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। उनका तर्क था कि विधानसभा सदस्यों की अपनी पार्टियों के प्रति आस्था बदल चुकी है और बहुत से सदस्यों का रुख बहुत ही लचीला अथवा अस्थिर है। इसलिए शासक दल और विपक्षी सदस्या के संयुक्त दल के बहुमत का पता लगाना कठिन और बेमानी होगा। इसलिए राज्य में किसी स्थाई सरकार के बनने की संभावना नहीं है।

केन्द्रीय सरकार ने असम राज्यपाल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और धारा 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निणय ले

लिया। उसने राज्य विधानसभा को भी भग्न कर दिया।

मेरे विचार में भोगोई मन्त्रिमंडल त्यागपत्र के बाद वामपंथी संयुक्त विधायक दल अथवा विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर न देना गसती थी। विपक्ष के बहुमत के दावे का परीक्षण उन्हें मन्त्रिमंडल बनाने का अवसर देकर ही किया जा सकता था। यह विधानसभा पर छोड़ दिया जाना चाहिए था कि वही इस बात का निर्णय करें कि उनका बहुमत है अथवा नहीं, या उनकी बात में कोई दम है या नहीं। यदि विपक्षी दल विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध न कर पाता तभी राज्यपाल को विधानसभा भग्न करने की सिफारिश करनी चाहिए थी। विपक्ष को सरकार बनाने का अवसर न देना मेरे विचार में भयकर गसती थी।

राज्यपाल की सिफारिशों को केन्द्रीय मन्त्रिमंडल द्वारा स्वीकार किए जाने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सूचना 18 मार्च की शाम को मेरे सचिवालय पहुंची और अगले दिन प्रातःकाल यह कागजात मेरे सामने रखा गया। अत्यन्त अनिच्छापूर्वक मैंने राष्ट्रपति शासन घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए।

प्रातःकाल प्रधानमंत्री को मुझसे मिलना था। मैं इस अवसर का लाभ उठा कर बहुत स्पष्ट शब्दों में राज्यपाल की सिफारिशों और मन्त्रिमंडल की सिफारिश के संवध में अपने विचार उनके सामने प्रकट कर दिए। कांग्रेस (आई) को दो बार सरकार बनाने का अवसर दिया गया जब कि विधानसभा में वह बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया। यह बात पहले प्रकट हो चुकी थी। विपक्षी दलों ने बहुमत दर्शाते हुए अपने समर्थकों की एक सूची पेश की थी, उसे यह तक देकर रद्द कर दिया गया कि विधानसभा के सदस्य अपनी वफादारी बदलते रहते हैं। इससे मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि यह घटना दोहरे मानदण्डों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रमाण थी। इसलिए मैंने असम राजनैतिक गतिविधियों और दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनावों के बार-बार स्पष्ट करने के प्रति अपनी अप्रसन्नता प्रकट कर दी (इस विषय के संवध में इस पुस्तक में मैंने अगस्त स्थान पर भी उल्लेख किया है)।

मैं चाहता तो इन दोनों मामलों के कागजात प्रधानमंत्री को यह कहकर लौटा देता कि मन्त्रिपरिषद् इस पर पुनः विचार करे, परन्तु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि मन्त्रिपरिषद् अपने पूर्व निर्णय पर स्थिर रहेगी और उस समय मन्त्रिपरिषद् की सलाह मानने के अतिरिक्त मेरे सामने कोई विकल्प न रहेगा। इसलिए पुनः विचार के लिए कागजात वापस भेजने से, कोई लाभ न होता। इसके बदले मैंने यह सोचा कि यह अच्छा है कि मैं अपने विचार और भावनाओं से व्यक्तिगत रूप में प्रधानमंत्री को अवगत करा दूँ और ऐसा मैंने किया।

असम में विदेशियों के मामले का प्रश्न चार साल से हमारे सामने था। परन्तु इसका कोई सत्ताप्रद हल नहीं निकल रहा था। प्रधानमंत्री बार-बार इस समस्या के हल की खोज के लिए विपक्षी दलों से सहयोग की मांग कर रही थी। संयुक्त

विपक्षी दल को असम में सरकार बनाने का अवसर न देकर उनसे सहयोग का कामना कैसे की जा सकती थी।

मार्च, 1980 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी कि दिल्ली प्रशासनिक धारा 1966 के अधीन केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में शासन चलाना असम्भव है इसलिए उनका मत है कि दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल को भग कर दिया जाए और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट की कुछ धाराएँ स्थगित कर दी जाएँ। उनके अनुसार रिपोर्ट भेजने से पहले 33 महीने के समय में दिल्ली प्रशासन एक्ट की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यकारी कौंसिल ने अपना कार्य योग्यतापूर्वक पूरा नहीं किया और उसने अपने अधिकारों का प्रयोग प्रशासनिक और तरीकों की अवहेलना द्वारा किया है। उन्होंने आगे कहा कि 1980 में दिल्ली मेट्रोपोलिटन क्षेत्र में हुए लोकसभा चुनावों में यह दर्शा दिया है कि कार्यकारी परिषद में लोगों को विश्वास नहीं रहा है। उन्होंने इस बात की सिफारिश की कि लोगों को अपने नये प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाए। उपराज्यपाल की सिफारिशों का मुख्य कारण सम्भवतः अंतिम ही था क्योंकि इस समय जिन राज्यों में जनता-पार्टी की सरकारें थी वहाँ विधानसभाएँ भग कर दी गई थी, जबकि उन राज्यों में मध्यावधि चुनाव करवाए गए, परन्तु दिल्ली मेट्रोपोलिटन के चुनाव नहीं हुए थे।

उपराज्यपाल की रिपोर्ट पर सरकार ने 21 मार्च, 1980 से 6 मास के लिए दिल्ली मेट्रोपोलिटन कौंसिल को भग करने का निणय लिया। मैं भी उसके अनुरूप आज्ञा दे दी। सितम्बर, 1980 में दूसरी बार 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए कहा गया जिसके लिए तक यह दिया गया कि दस साल बाद होने वाली जनगणना में प्रशासन का ध्यान और समय लगेगा और इसलिए मेट्रोपोलिटन क्षेत्र का मतदाता सूचियाँ का भी संशोधन करना होगा। इसके साथ यह भी कहा गया कि दिल्ली के प्रशासन को सुचारु बनाने के प्रयत्न किए जा रहें हैं। फिर सरकार ने 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई (20 सितम्बर, 1981 तक)। अगस्त 1981 में उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की, अवधि बढ़ाने की सिफारिश दोहराई, (20 मार्च, 1982 तक), उन्होंने इस बार यह तक दिया था कि केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली में सितम्बर और अक्टूबर में वादे आने की संभावना रहती है और अक्टूबर-नवम्बर में हिन्दू और मुसलमानों के बहुत से त्योहार भी पड़ते हैं, इसलिए सांप्रदायिक तनाव की संभावना भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली में प्रायः हर साल वादे आते हैं, त्योहार भी हर साल आते हैं और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनके कारण हर वर्ष अथवा हर स्थान पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं। इस प्रकार की अशांति तो त्योहारों के अतिरिक्त भी हो सकती है। फरवरी 1981 में दिए गए तक भी वेबुनियाद थे। प्रशासन को यह

पता था कि फरवरी, मार्च 1981 तक जनगणना होगी। इसलिए चुनाव या तो उससे पहले हो सकते थे या बाद में। मतदाता सूचियों का सशोधन एक स्थाई प्रक्रिया है, इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए तक आधारहीन थे। केन्द्र सरकार ने उपराज्यपाल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 20 मार्च, 1982 तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का निणय कर लिया। उही दिनों समाचार पत्रों में यह समाचार छपा कि गृहमन्त्रालय दिल्ली में जल्दी ही चुनाव कराने की योजना बना रही है। इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए और यह सोचकर कि यह राष्ट्रपति अवधि बढ़ाने का आखिरी अवसर होगा, मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरी स्वीकृति की सूचना देते हुए मेरे सचिव ने गृहमन्त्रालय को यह निर्देश भी दिया

"अपनी सहमति व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति का विचार है कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार गृहमन्त्रालय जल्द ही चुनाव करवाना चाहता है, उनका यह विश्वास है कि चुनाव राष्ट्रपति शासन की इस अवधि से पूरा हो जाने चाहिए और इस संबंध में आदेश जारी किया जाए।"

मुझे आश्चर्य और निराशा हुई कि उपराज्यपाल ने मार्च 1982 में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए फिर सुझाव भेजा। इस बार यह तक दिया गया था कि मतदाता सूचियों का सशोधन बड़े पैमाने पर चुनाव आयुक्त के आदेश पर इसलिए किया जा रहा है कि अनेक नई बस्तियां बनी हैं और लोग भारी तादाद में अपने पूर्व स्थानों से वहां चले गए हैं। इसके साथ ही केन्द्रीय शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के निर्धारण के लिए कुछ योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ताकि प्रशासन अधिक सुगठित रहे और अनेक प्रक्रियाएं बार-बार न दोहरानी पड़ें जिसके कारण इस केन्द्र शासित प्रदेश में अनेक विभागों का निर्माण करना पड़ा है। सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और मेरे लिए इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और चारा न था।

इस बात पर पुनः विचार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि गृहमन्त्रालय द्वारा सितम्बर 1981 तक चुनावों की आशा की झलक दी गई थी उसे उस रूप में नहीं मानना चाहिए था। उसका अभिप्राय केवल सरकार के मार्च 1982 तक राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने के प्रति की जा रही आलोचना को नरम करना था। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि मार्च 1980 से - नवंबर 1982 तक तो दो साल की अवधि में परिस्थितियां कभी भी चुनाव करवाने के उपयुक्त नहीं हुई। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि विपक्ष के राजनतिक दल आक्रोश से भर उठे।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विरोधी दल

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को निश्चित अवधि पर आपसी विचार विमर्श लिए मिलना एक स्वस्थ परम्परा है, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देश-राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त अन्य घटनाओं से परिचित कर हैं। मेरा विश्वास है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सप्ताह में एक बार वहां के शासक नियमित रूप से मिलते हैं। आपसी बातचीत का स्थान नोट या चिट्ठी पत्री न से सकती। मोरारजी देसाई और इन्दिरा गांधी प्रायः मुझसे भेंट करते रहते हैं। इंदिरा जी की बजाय मोरारजी भेंट के लिए अधिक आते थे। मैं यह समझता कि प्रधानमंत्री को नियमित रूप से राष्ट्रपति से मिलना एक परम्परा बन चुक ताकि सरकार और राष्ट्र के मुखिया में पूर्ण स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान हो सके। मुझे याद है इस तरह की भेंट मुलाकातों में मैं मोरारजी देसाई यह बात प्रकट करता रहा कि असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच में संचार सा को जल्दी-से-जल्दी विकसित किया जाये ताकि उस क्षेत्र को आने वाली बाढ़ होने वाली हानि से बचाया जा सके। मैं प्रशासनिक मामलों तथा हाईकोर्ट में निस्थानों को भरने, राज्यपालों की नियुक्ति तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति आदि पर भी विचार विमर्श करता रहा हूँ। मैं उनसे विदेशी मेहमानों के और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के संबन्ध में भी विचार करता रहा।

इन्दिरा जी के काल में इस तरह की भेंट घटनाओं में काफी कमी आई। देश तथा विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का ज्ञान मुझे केवल समाचार पत्रों से ही हो पाता था। उदाहरण के रूप में विदेश मंत्रालय के सचिव के दौरे का ज्ञान मुझे समाचार-पत्रों से ही हुआ और मुझे इस बात का भी पता लगा कि इस भेंट का क्या परिणाम निकलता। इसमें सन्देह नहीं कि प्रधान और मन्त्रिपरिषद् नोटियों का निर्धारण करते हैं और निष्पत्ति लेते हैं, परन्तु यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण राष्ट्रपति को दिया जाय,

उनका ज्ञान हो। इसलिए मैंने अपने प्रथम सचिव को दिसम्बर, 1981 में प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखने के लिए कहा कि प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके सबध में सरकार के विचार से राष्ट्रपति को यथाशीघ्र कसे सूचित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पत्र के बाद भारत-सरकार के कुछ मंत्री और सचिव महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए मेरे पास आने लगे, परन्तु यह प्रक्रिया बहुत थोड़े समय तक चली। परन्तु मैं यह कहूँगा कि प्रधानमंत्री कुछ समय बाद मुझसे भेंट करने लगे। मेरा यह विचार है कि प्रमुख घटनाओं और उनके प्रति सरकार के दृष्टिकोण से राष्ट्रपति को अवगत कराना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से विचार विमर्श के लिए उसी प्रकार मिलते रहना चाहिए जिस प्रकार ब्रिटेन के शासक से वहाँ के प्रधानमंत्री मिलते रहते हैं।

अपने राष्ट्रपति काल में, विशेष रूप से जनवरी 1980 में इन्दिरा जी के लौटने के बाद, मैंने विपक्ष और प्रधानमंत्री के बीच सम्पर्क बनाये रखने का प्रयत्न किया। मैंने कभी भी विपक्ष के सदस्यों को राष्ट्रहित के मामलों पर अपने विचार प्रकट करने के लिए भेंटयार्ता से इन्कार नहीं किया, उन्हें सदा मिलने का अवसर दिया। राज्य विधानसभाओं के विपक्षी सदस्य भी अनेक बार मुझसे मिलते रहे। मैंने इस पुस्तक में किसी अत्यन्त महत्वपूर्ण विपक्षी सदस्यों के मुझसे भेंट करने और सरकार बनाने के दावे का उल्लेख किया है। विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली मेट्रोपोलिटन काउंसिल के चुनावों के बार-बार स्थगित किए जाने के सबध में भी मुझसे मिलते रहे और इस बात की ओर मेरा ध्यान दिलाते रहे।

नवम्बर, 1981 में गडवाल लोकसभा सीट का चुनाव स्थगित किए जाने से भी विपक्षी दलों में असन्तोष था और इस सबध में उनके प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाक़ात भी की। मेरा कहना है कि इस चुनाव के स्थगित किए जाने पर मुझे भी अप्रसन्नता अनुभव हुई। इसलिए मैंने इस सबध में अपने विचार प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा सूचित किए। इस पत्र में मैंने उनका ध्यान उन बातों और उनके परिणामों की ओर दिलाया जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कर रही थी।

मई, 1982 में चुनावों के सबध में हरियाणा के राज्यपाल ने राज्य विधान सभा के सबध में जो कुछ किया मेरे विचार में वह जल्द बाजी में उठाया गया गलत कदम था। इस सबध में भी विपक्षी दलों के सदस्य मुझसे मिले और हस्तक्षेप के लिये प्रार्थना की। मैंने उन्हें अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर दिया और अपने विचार भी उनको बताये परन्तु साथ ही मैंने अपनी सीमाओं का भी उल्लेख किया। उसके बाद मैंने इस सबध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और विचार करने के लिए आमंत्रित किया। मैंने इस सबध में सही कदम उठाने और कार्यवाही करने का सुझाव भी दिया।

इन उदाहरणों से यह प्रकट होता है कि सत्ता दल का विपक्षी दलों के प्रति अनुचित असहिष्णुतापूर्ण रवैया था। सत्ता दल द्वारा प्रत्येक संभव उपायों से उन्हें सत्ता में आने से वंचित रखना यह प्रकट करता है कि लोकतांत्रिक मान्यताओं के प्रति उनमें आदर की भावना नहीं रह गई और भविष्य में इससे हानि की संभावना है।

मुझे इस बात का अहसास था कि विपक्षी दलों के नेताओं से मेरा मिलना विशेष रूप से सत्ता पक्ष गलत समझ सकता है। समाचार पत्रों में भी इस बात का अनुमान लगाया जाने लगा था कि विभक्त विपक्ष को एकत्र करने का मैं केन्द्र बिन्दु बन जाऊंगा। निस्संदेह यह संभावनाएँ अवांछित थी क्योंकि मैं राष्ट्रपति काल के अंतिम समय में दलगत राजनीति में नहीं पड़ना चाहता था। यदि मैं विपक्षी दलों से मिलकर सामयिक विषयों पर उनके विचार सुनना और जानना चाहता था तो ऐसा मैं इसलिए करता था कि मैं इसे सामंदायिक समझता। मैं वे विचार प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता था और उसके साथ उनके संबंध में अपने विचार भी। इसमें संदेह नहीं कि विपक्षी सदस्य अपनी शिकायतें और विचार राज्य विधानसभाओं में प्रकट कर सकते थे और सुनाने दे सकते थे। ऐसा नहीं कि वे यह न समझते हों कि मैं उनकी शिकायतें दूर कर सकूंगा। उन्हें राष्ट्रपति के अधिकारों और सीमाओं का अच्छी तरह ज्ञान है परन्तु उनके लिए राष्ट्रपति एक ऐसा अधिकारी है जिसके समक्ष वे अपने विचार प्रकट कर सकें और इस प्रकार निराशा से बच सकें।

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार

सामान्य जन-जीवन में भ्रष्टाचार की समस्या देश के अनेक लोगों के लिए चिन्ता का विषय रही है। मैं लम्बे अर्से तक कांग्रेस में रहा हूँ और अत्यन्त सामान्य स्थिति से दल की उच्चतम स्थिति तक पहुँचा हूँ। ग्रामीण कांग्रेस समिति के साधारण सदस्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद तक अनेक अवसरों पर चुनावों के लिए पार्टी को तैयार करने और संगठित करने के लिए मैं उत्तरदायी भी रहा हूँ। ऐसा राज्य स्तर और अखिल भारतीय स्तर तक करना पड़ा है। इसलिए मैं पूर्णतया परिचित हूँ कि चुनाव लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है। कांग्रेस पार्टी से मेरे सहयोग के समय तक कुछ ही व्यक्ति थे जिन्हें पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया था। जितना धन इकट्ठा किया जाता था, वह विरहसनीय रूप से पार्टी के हिसाब में जमा करवा दिया जाता था। पार्टी के दो प्रमुख अधिकारी समुक्त रूप से बैंक से संबंधित काम करते थे। धन संग्रह का कार्य पार्टी अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष के नाम से सभी व्यक्ति नहीं कर सकते थे।

गत कुछ वर्षों में ऐसे कुछ उदाहरण देखने में आये हैं कि उच्च पदों के अधिकार सम्पन्न नेता मनमाने ढंग से धन इकट्ठा करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते रहे हैं। इतना ही नहीं उन्होंने सरकारी मशीनरी का भी इस कार्य के लिए दुरुपयोग किया है। इस बात के लिए उन्होंने कई बार यह सफाई दी है कि व्यापारिक संधी, उद्योगों और दानियों से धन इकट्ठा किया है और यह धन स्वेच्छापूर्वक दिया गया है। अनेक बार उन्होंने इन बातों को भी अनावश्यक समझा और उन्होंने व्यापारियों, ठेकेदारों तथा अन्य लोगों से धन इकट्ठा किया और उसके बदले में इन 'दानियों' को सरकारी सरक्षण दिया गया। स्थिति यहाँ तक पहुँची कि पार्टी के लिए इस प्रकार धन इकट्ठा करना एक सामान्य बात समझी जाने लगी। इस बात का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता कि किस व्यक्ति ने किससे कितना धन एकत्रित किया। और इस बात के लिए भी आवश्यक नहीं किया जा सकता कि वह रूपया जिस बात के लिए इकट्ठा किया गया उस ध्येय के लिए खर्च भी

हुआ है या नहीं। वास्तव में जिस व्यक्ति और संगठन के लिए यह रुपया इकट्ठा किया गया है, वह इन धन संग्रह करने वालों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या दायित्व नहीं लगा सकता। इस प्रकार जनता का यह सोचना कि यह अधिकारों का दुरुपयोग है और इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि प्रमुख नेताओं को भी इन सब बातों का ज्ञान होता है, व सब कुछ जानते हैं क्योंकि अनक खुफिया एजेंसियों द्वारा उन्हें इन सब बातों का पता लगता रहता है। जब इस प्रकार की बातों पर कोई नियंत्रण नहीं रह पाता तो किसी को भी दोष देने का कोई लाभ नहीं रहता।

कुछ लोग इस बात का तक दे सकते हैं कि इस तरह के समाचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और स्थिति इतनी भयावह नहीं है। वे यह भी कह सकते हैं कि विरोधी समाचार पत्र एक सामान्य सी भूल को पार्टियों और सरकार को बदनाम करने के लिए इतना अधिक उछालते हैं। यह भी कहा जाता है कि अनुत्तरदायी तत्त्व जनता में असंतोष फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ लोग इससे आगे चलकर यह तक दे सकते हैं कि गैर-कानूनी ढंग से पैसा देने के लिए विवश किए जाने वाले व्यक्ति इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं परंतु ऐसा क्यों नहीं करते। प्रथम बात स्पष्ट यह है कि उन्हें इस कार्य से कुछ लाभ हुआ है। इसलिए वे संरक्षण देने वालों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं करना चाहते। दूसरी बात यह कि यदि वे उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हैं तो भविष्य में उनके व्यापार के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने की संभावना रहती है। वे इस बात की उचित ढंग से शिकायत तो नहीं करते परंतु वे व्यक्तिगत रूप से एकांत में इन मामलों पर बात करन से हिचकिचाते भी नहीं। इस प्रकार जनता तथ्यों से परिचित हो जाती है। सामान्य जन-जीवन में भ्रष्टाचार इतने व्यापक रूप में है जिससे सबध में सब जानते हैं। इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह तक देते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग ही ऐसा नहीं करते वरन् विपक्षी भी अवसर प्राप्त होने पर इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की बातें व्यर्थ हैं इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के तर्क से भेरे इस सिद्धांत की पुष्टि ही होती है कि हमारे देश का राजनीतिबाना बाना भ्रष्ट हो चुका है। देश को इस बात में कोई रुचि नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्षी एक दूसरे पर दोषारोपण द्वारा कीचड़ उछालते रहें। देश के प्रबुद्ध व्यक्ति राजनीति के इन कारनामों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं।

जनवरी, 1980 में इंदिरा जी द्वारा सत्ता सभालने के फौरन बाद मैंने इस विषय पर उनसे बातचीत की। मैंने पार्टियों के कामों के लिए, विशेष रूप से धन के अनियंत्रित संग्रह पर रोक लगाने के लिए कहा। सत्ता में उनकी पार्टी का बहुमत था। अधिकार राज्य विधानसभाओं में भी उनके दल का बहुमत था और उनकी

सरकारें थी। इस प्रकार वह एक सुदृढ़ स्थिति में थी। मैंने उनसे कहा कि वे इस स्थिति का लाभ उठाकर इस बुराई से छुटकारा पाने का प्रयत्न कर सकती हैं। मुझे आशा थी कि वे अपनी सुदृढ़ स्थिति का उपयोग राजनीति को स्वच्छ बनाने में करेंगी। परन्तु इस सबंध में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। स्पष्ट है उन्होंने इस बुराई की रोकथाम के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया।

देशबासी इस बात से पूर्ण परिचित हैं कि ए० आर० अतुले ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते समय दो ट्रस्ट बनाये और उनके लिए धन इकट्ठा करने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाये। इन बातों को याद करने में मुख्य मुद्दा इन ट्रस्टों का नियंत्रण व्यक्तिगत रूप से उनके हाथ में था, मुख्यमंत्री के रूप में सरकारी ढंग पर नहीं। जब किसी उपभोक्ता वस्तु की कमी होती है तो उसने वितरण पर नियंत्रण करना ही पड़ता है। जबकि ये नियंत्रण भ्रष्टाचार के मुख्य कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार का कत्तब्य होता है कि सबूद्ध अधिकारियों के लिए निर्देशक सिद्धांत बनाये जायें और उन निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और उनकी देखभाल के लिए उच्चाधिकारी नियत किए जाएं। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तथा मंत्रियों के लिए सीमेट अथवा कमी वाली उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण स्वयं करना इतना आवश्यक नहीं जितना अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की तरफ ध्यान देना। मुख्यमंत्री के लिए अपनी इच्छा से वितरण करने के लिए किसी चीज का कोटा निर्धारित करना, किसी सही सोच वाले व्यक्ति को उचित प्रतीत नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री को भी ऐसी चीज के वितरण के लिए किसी उचित बसोटी का पालन करना आवश्यक है, केवल एक तरफा नियंत्रण करना उसके लिए उचित नहीं।

यदि इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है तो मुख्यमंत्री के लिए अलग कोटा निर्धारित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मुख्यमंत्री द्वारा अपनी इच्छा से सीमेट वितरण करने के लिए अलग कोटा निर्धारित करना उचित नहीं था। बम्बई उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष था कि सीमेट की आपूर्ति और ट्रस्टों के लिए दान देने में कोई आपसी संबंध है। ट्रस्ट का व्यय कितना भी उच्च और आदश पूर्ण हो परन्तु सीमेट वितरण करके ट्रस्टों के लिए धन इकट्ठा करना स्पष्ट रूप से अधिकारों का दुरुपयोग था। साध्य और साधनों के बीच की मर्यादा को हम व्यक्तिगत और जन जीवन में उपेक्षित नहीं कर सकते।

मैं चीनी मिलों द्वारा इस शत पर रुपया इकट्ठा करने पर अधिक कुछ नहीं कहूंगा कि यह कारखाने गंने की आपूर्ति करने वाले लोगों को कम प्रमेट करक अपनी पूर्ति कर लेंगे। यह बात आपत्तिजनक थी। समाचार पत्रों से पता चला कि कारखाने को जो गंना दिया गया, कई मामलों में उसके दाम कम दिए गए। सीमेट के बदले में धन प्राप्त करने की ओर लोगों का ध्यान गया और इस बात की आलोचना हुई। मुख्यमंत्री के रूप में अतुले ने प्रदेश सरकार से दो करोड़ रुपया ट्रस्टों के लिए

दिए जाने की बात अपन आप में अप्रुव है और इसका कोई उदाहरण नहीं, कठोर से कठोर शब्दों में इसकी आलोचना की जानी चाहिए। यदि यह बात चुनौती दिए बगैर चली जाती तो अर्थ प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को जनता के बोझ से व्यक्तिगत ट्रस्टों के लिए रुपया हटाने के लिए कैस रोका जा सकता था। जब कि वह रुपया व्यक्तिगत ट्रस्ट में होने पर उनका मुख्यमंत्री न रहने पर भी उनके अधीन रहता। ऐसी स्थिति में यह सही उत्तर नहीं है कि इन ट्रस्टों का ध्येय बहुत महान् था और इनके ट्रस्टी सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे। सरकार जो रुपया खर्च करती है उससे लिए जनता के प्रतिनिधि उत्तरदायी होते हैं और वह सही ढंग से खर्च करना पड़ता है परन्तु यह बात इस प्रकार के ट्रस्टों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए और इन ट्रस्टों के नियंत्रण से अतुल्य को अलग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं इस सारी बात पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। परन्तु मुझे दुःख है कि स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये।

स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी

गांधीजी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद कुछ वर्षों में ही देश की राजनीतिक गतिविधियों में महान् परिवर्तन आया। इससे पहले भारत की जनता राजनीतिक रूप से जागृत नहीं थी। गांधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देश की राष्ट्रीयता का एक प्रभावपूर्ण राजनीतिक साधन बनाया। वे राजनीतिक क्षितिज पर छा गये और उनके नेतृत्व में विदेशी शासन से मुक्ति की भाग्य जन आन्दोलन में बदल गई।

भारत के कौन-कौन से लाखों नर नारियाँ ने गांधीजी द्वारा चलाये गये असहयोग, नमक सत्याग्रह तथा अन्य आन्दोलनों में भाग लिया। अनेक छात्रों ने अपनी पढ़ाई त्याग दी, अनेक व्यवसायियों ने उज्ज्वल भविष्य की ओर ध्यान न देकर गांधीजी के आन्दोलन में भाग लेने के लिए सब कुछ त्याग दिया और सम्झी अवधि तक जेलों में बंदी रहे। उनके पीछे उनके परिवारों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। उनके बच्चे उपेक्षित रहे। अपना काम धंधा छोड़ देने के कारण लोगो को केवल पैतृक आय से ही काम चलाना पड़ा। इस प्रक्रिया में अनेक परिहार निघन हो गये, परन्तु उन्हें इस बात का सन्तोष था कि उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए देश के महान् नेता के आह्वान को स्वीकार किया है। जब वे लोग गांधीजी के सहयोग में आये उन्हें किसी प्रकार के पुरस्कार पाने का विचार नहीं था। उन्हें यह भी आशा नहीं थी कि देश उनके जीवन काल में ही स्वतन्त्र हो पायेगा। इनमें से अधिक व्यक्ति भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व ही स्वर्ग सिंघार गये और जो बहुत से भारत को स्वतन्त्र देखने के लिए बचे वे बिना किसी मान्यता, पुरस्कार, सम्मान अथवा किसी प्रकार के पद की प्राप्ति के बिना स्वतन्त्र भारत में रह रहे हैं। उन्हें जो पुरस्कार देश की स्वतन्त्रता की रजत जयंती के अवसर पर दिये गये वह या एक ताम्र-पत्र और पेंशन।

मैं यह अनुभव करता हूँ कि जिन सब लोगो ने स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लिया और जो भारत के स्वतन्त्र होने के समय जीवित थे, उन सबमें किसी सत्ता,

अधिकार या कोई पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं की। इन सब में 1947 अथवा उसके बाद किसी पद को समालने की न योग्यता थी और न साधन। हममें से कुछ लोगों का यह सौभाग्य भी था कि देश के स्वाधीन होने के समय हम जीवित थे और कुछ दशकों के बाद देश के शासन में हमें महत्व प्राप्त हुआ और उच्च पदों पर पहुँचे। हम स्वतंत्रता आन्दोलन के अज्ञात देश भक्तों के प्रति अद्वैतसत्ता के दोषी होने, यदि हम उनकी इस निस्वार्थ देश सेवा की भूरि भूरि प्रशंसा अथवा सराहना न करें।

यहाँ मैं टी प्रकाशम का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता जिन्हें तैलुगुभाषी लोग सम्मान से 'आम्म केशरी' कहकर पुकारते थे। वे बैरिस्टर थे और उनकी प्रैक्टिस मद्रास में बहुत अच्छी चल रही थी। वे अपने व्यवसाय की उस स्थिति तक पहुँच गए थे जब उन्हें न्यायाधीश बनाये जाने की संभावनाएँ हो गई थी। वे गांधी जी के आह्वान पर अपने उज्ज्वल भविष्य का बलिदान करके स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े। मद्रास में साइमन कमिशन के बहिष्कार के समय पुलिस की गोलीमारी के सामने उन्होंने अपना सीना बड़ा दिया था। उन्होंने मद्रास की अपनी सम्पत्ति से होनेवाली आय से अंग्रेजी में 'स्वराज्य' नामक एक दैनिक निकाला। उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ध्यान न देकर अपना सारा समय, शक्ति और धन स्वतंत्रता के लक्ष्य के लिए अर्पित कर दिया। अविभक्त मद्रास और आंध्र में बहुत बड़े समय के लिए वे रेवेन्यू मंत्री तथा मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कभी कोई पद नहीं सभासा। 1957 में उनकी मृत्यु के समय उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी, जिसे वह अपनी कह सकें। अपनी मृत्यु से लम्बे समय पूर्व से वे अपने मित्रों और प्रशंसकों द्वारा की गयी सहायता से ही काम चलाते रहे। मैं उनके परिवार के अनेक सदस्यों को जानता हूँ जो आज भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं। उनके सबब में यह कहना सही है कि उन्होंने स्वतंत्रता की वेदी पर अपने आपको पूर्ण रूप से कुर्बान कर दिया।

मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि इसी प्रकार का बलिदान करनेवाले अन्य हजारों व्यक्ति होंगे जिन्हें हम नहीं जानते।

हम ऐसे अनेक व्यक्तियों के नाम जानते हैं जिन्होंने अपना उज्ज्वल भविष्य बलिदान करके बिना किसी पुरस्कार की आशा के स्वतंत्रता आन्दोलन में सहयोग दिया। आज भी उनके परिवार के सदस्यों को कठिन परिस्थितियों में देखा जा सकता है। इन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, यद्यपि वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेनेवाले प्रमुख व्यक्तियों के वंशज हैं।

जैसा कि पहले मैंने जिक्र किया है एक बर्सा पहले मैंने प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को जन-जीवन में भ्रष्टाचार के सबब में लिखा था कि किस प्रकार नेता लोग गलत ढंग से धन इकट्ठा करने के लिए अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। और

विस प्रकार हमार प्रशासन मे जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। उन्होंने अपने उत्तर मे लिखा था कि उनका परिवार सदा से भ्रष्टाचार के विरुद्ध रहा है और अपनी सासारिक सम्पत्ति के बारे मे उनके विचार सारे ससार को ज्ञात हैं। उनके पिता और दादा ने अपनी शानदार वकालत, अपना पुराना घर, सम्पत्ति और कोठी सब कुछ दान कर दिया था। प्रधानमंत्री ने लिखा था कि "यह बताना कोई आवश्यक नहीं कि मैंने अपना घर जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, उसका आस पास की भूमि, पुस्तके, कागजात तथा अन्य वस्तुओं के अमूल्य समूह को भी दान कर दिया है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि मेरे पिछले रिकार्ड ॥ भ्रष्टाचार के सबंध मे मेरे विचार पूर्णतया स्पष्ट हैं। इसके उत्तर में मैंने लिखा कि मैं उनके पिता और दादा के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मे महयोग से पूर्ण परिचित हूँ। मैंने उनके साथ यह भी लिखा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व मे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजाजी, राजेन्द्र बाबू और सुभाषचन्द्र बोस आदि ने स्वतंत्रता आंदोलन मे सम्मिलित होने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जबकि उनके (इन्दिराजी) परिवार का देश के वर्तमान इतिहास मे प्रमुख स्थान है। हमें टी० प्रकाशम तथा अन्य देश के हजारों नर-नारियों को भी नहीं भूलना चाहिए और उनके बलिदान के लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। मैंने यह भी लिखा कि इन लोगों के सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्रता आंदोलन मे भाग लिए बिना देश स्वतंत्र नहीं हो सकता था। मैंने उन्हें स्मरण कराया कि उनमें से कितने लोगों ने अपनी सम्पत्ति बेचकर अपने परिवार का पालन किया है। केवल इतना ही नहीं कि वे अपने जीवन मे कष्ट उठाते रहे परन्तु उनके परिवार के लोग आज भी भयकर निधनता मे जीवन बिता रहे हैं। मैंने उन्हें स्मरण कराया कि उन्हीं मे से कुछ हम लोग आज भी जीवित हैं और उनके बलिदानों के कारण ही लाभ उठा रहे हैं।

जब मैंने देश मे व्याप्त भ्रष्टाचार के सबंध मे इन्दिराजी को लिखा तो वस्तुतः उस समय उनके दादा, पिता अथवा उनके द्वारा की गयी कुर्बानियों को याद करवाने का कोई अवसर नहीं था। उनके परिवार अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कुर्बानियों का भ्रष्टाचार के प्रश्नों से कोई सबंध नहीं। वे प्रायः भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन मे अपने परिवार द्वारा की गई कुर्बानियों का उल्लेख किया करती थी। यह तो उनके लिए ही विचार की बात थी कि वे देश के लिए की गई उनके अथवा उनके परिवार द्वारा की गई कुर्बानियों का जिक्र करें परन्तु उन्हें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए था कि उन्होंने अथवा उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने केवल अपनी कुर्बानियों का ही नहीं बल्कि हजारों अन्य व्यक्तियों की कुर्बानियों का भी प्रचुर लाभ उठाया है।

मैं बार-बार यह बात कह चुका हूँ कि मैंने अपने जीवन मे जो भी सफलता

प्राप्त की उसका कारण महात्माजी का नेतृत्व था जिनमें यह योग्यता थी कि वे किसी को भी धूल से उठाकर एक मानव बना सकते थे। मुझे अपनी जवानी के दिनों में जवाहरलालजी की इस उक्ति से भी प्रेरणा मिली है कि, सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है जो हौसला करके आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। वस्तुतः यह उक्ति मेरे जीवन के लिए आदर्श वाक्य रही है। मैं जवाहरलाल जी की दूरदर्ष्टि और भारत की समृद्धि के लिए उन्होंने जो सुदृढ़ आधार बनाए, मैं उनका बहुत प्रशंसक हूँ। परन्तु हमारे लिए ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भारत की स्वतन्त्रता और आर्थिक प्रगति के लिए किए गए योगदान को भूल जाना अपवाद कम करके देखना गलत होगा।

राष्ट्रपति और भारतीय रैडक्रास

भारतीय रैडक्रास सोसायटी अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की एक प्रमुख संस्था है। संस्था के ध्येय काफी व्यापक हैं। इसके ध्येय में भारत तथा किसी भी अन्य देशों में युद्ध के कारण बीमार अथवा घायल हुए व्यक्तियों को सहायता पहुंचाना, सेना की सहायता लिए रेडक्रास डिपो की स्थापना, गभवती महिलाओं और बाल कल्याण के लिए भी कार्य करना, महामारियों, भूचालों, अकालों, बाढ़ों तथा अन्य विपदाओं में प्रस्तुत लोगों के लिए अन्य सुविधाएं मुहैया करने के साथ-साथ कपड़े आदि देना भी है। यह अस्पतालों तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की भी सहायता करता है। इस सोसायटी के कार्यों का निष्पादन इंडियन रैडक्रास सोसायटी नियम 20 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। इन नियमों का निर्धारण रैडक्रास सोसायटी की व्यवस्थापक समिति करती है। भारत का राष्ट्रपति इस सोसायटी का अध्यक्ष होता है। वार्षिक जनरल मीटिंग में वही अन्य सदस्यों के अतिरिक्त सोसायटी के चेयरमैन को नामजद करता है।

सोसायटी की आम सभा की बैठक वार्षिक 1978 की 5-6 अप्रैल को होगी थी। 30 मार्च अर्थात् इस बैठक के एक सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने मुझे एक पत्र लिखा—

भारतीय रैडक्रास सोसायटी की संसद में तथा बाहर काफी आलोचना हुई है। हमें इस बात की काफी चिन्ता है। मैं समझता हूँ कि इसके कार्य को ठीक दिशा देने के लिए किसी हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्तर के एक स्वतंत्र व्यक्ति को जो यह उत्तरदायित्व संभाल सके, नियुक्त किया जाय। मैं बी० एम० श्री तारकुंडे, जिन्हें संभवतः आप भी जानते हैं—भारतीय रैडक्रास सोसायटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की सिफारिश करता हूँ। श्री रगनाथन ने अभी इस पद से त्यागपत्र दिया है।

न्यायाधीश तारकुंडे के संबंध में सिफारिश को स्वीकार करते हुए 3 अप्रैल को मैंने प्रधानमंत्री को लिखा कि मैंने इस विचार से इंडियन रैडक्रास सोसायटी

के संविधान को देखने के लिए मगाया है ताकि भारत के राष्ट्रपति को उससे अलग रखा जा सके। मैंने प्रधानमंत्री से प्रार्थना की कि वे इस विषय में अपनी राय मुझे दें।

प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल को अपना उत्तर मुझे भेजा। उन्होंने मेरे सुझाव का उत्तर देते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रपति को सोसायटी के अध्यक्ष पद से अलग रहना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा कि सोसायटी की प्रबन्ध समिति को चाहिए कि वह रैंडक्रास सोसायटी एक्ट 1920 की धारा 5 के नियमों को संशोधित करे। उन्होंने सभापति के अनुरूप यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि आपकी पत्नी सोसायटी की महिला अध्यक्ष हो, ऐसी स्थिति में यह करना भी आवश्यक होगा। उनका विचार था कि चूंकि इस संस्था का प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष होता है, इसलिए उसकी नामजदगी सोसायटी के प्रेजिडेंट द्वारा होनी चाहिए और यह नियुक्ति सरकार के अधीन रहनी चाहिए। यदि आप सोसायटी के प्रेजिडेंट पद से मुक्त होना चाहते हैं तो सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि मन्निमडल का कौन-सा सदस्य अध्यक्ष की नामजदगी करे।

सोसायटी की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष बंगलादेश के शरणार्थियों से संबंधित सहायता कार्यक्रमों पर संसद और समाचार-पत्रों में लगाए गए दोषारोपणों से बहुत चिन्तित थे। प्रबन्ध समिति ने निश्चय किया कि भारत सरकार के प्रमुख सत्तता आयुक्त एम० जी० पिमपुटकर से यह प्रार्थना की जाए कि सोसायटी की कार्य पद्धति के संबंध में जो गम्भीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी छानबीन करें। पिमपुटकर ने रैंडक्रास सोसायटी के विरुद्ध लगाए गए दोषारोपणों के संबंध में अपनी रिपोर्ट 9 अगस्त, 1979 को प्रधानमंत्री को दी।

जनवरी 1980 में केन्द्रीय सरकार के बदल जाने पर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के परामर्श पर 29 अप्रैल, 1980 को आम समिति की सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्यमन्त्री एन० आर० लस्कर को रैंडक्रास सोसायटी का अध्यक्ष नामजद कर दिया। एक नई प्रबन्ध समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने सोसायटी की कार्यप्रणाली पर लगाए गए आरोपों के संबंध में पिमपुटकर की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की। तीन सदस्यीय इस समिति का निष्कर्ष था कि सोसायटी के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार हैं। 17 फरवरी, 1981 को हुई बैठक में समिति की इस रिपोर्ट को कुछ स्पष्टीकरणों के साथ स्वीकार कर लिया। इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव भी पारित किया गया।

सोसायटी के प्रेजिडेंट के नाते राष्ट्रपति ने अपने सचिव को सोसायटी की प्रबन्ध समिति के लिए नामजद किया। 17 फरवरी, 1981 को हुई प्रबन्ध समिति की बैठक में राष्ट्रपति के सचिव ने कहा कि तीन सदस्यीय समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वह अभी प्राप्त हुई है। उस पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सदस्य

रिपोर्ट का अध्ययन कर सर्वे, इसलिए प्रबन्ध समिति की बैठक एक सप्ताह बाद बुलाई जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उस बैठक में वित्त सचिव (प्रबन्ध समिति के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामजद एक और व्यक्ति जो सोसायटी का बोधाध्यक्ष भी होता था) भी उस बैठक में उपस्थित रहें ताकि उस पर विचार के लिए उनकी सहायता प्राप्त हो सके। उनका यह भी विचार था कि प्रस्ताव का जो विस्तृत मसौदा स्वीकार करने के लिए प्रचारित किया गया है, उसमें सोसायटी के पूर्व प्रेजिडेंट और प्रधानमन्त्री का उल्लेख उचित नहीं। परन्तु उनके यह सुझाव स्वीकृत नहीं हुए। राष्ट्रपति के सचिव द्वारा प्राथना करने पर भी इन बातों को रिकार्ड में भी सम्मिलित नहीं किया गया।

बाद में राष्ट्रपति के सचिव ने वित्त सचिव से इस बात पर विचार किया। वित्त सचिव इस बात से सहमत थे कि प्रबन्ध समिति ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया वह उचित नहीं। उनका विचार था कि एक संक्षिप्त प्रस्ताव किसी भी सबद्ध व्यक्ति के उल्लेख के बिना तैयार किया जाए। इस प्रस्ताव तथा 17 जनवरी, 1981 को हुई बैठक की कार्यवाही पर भी विचार किया जाए। उनका विचार था कि अध्यक्ष प्रबन्ध समिति के सदस्यों को पूर्व प्रस्ताव के स्थान पर इस संक्षिप्त प्रस्ताव पर विचार के लिए परामर्श दें। मेरे सचिव ने इन सब बातों से मुझे सूचित किया और वित्त सचिव द्वारा सुझाए गए संक्षिप्त प्रस्ताव का मसौदा भी मुझे दिखाया। इस प्रस्तावित कार्यवाही पर मैंने अपनी सहमति प्रकट की।

इसके बाद मेरे सचिव सोसायटी के अध्यक्ष (राज्यमन्त्री एन० आर० लस्कर) से मिले और उन्हें सशोधित प्रस्ताव का मसौदा दिया तथा उसे स्वीकार करने के लिए कहा।

श्री लस्कर 18 अप्रैल, 1981 को मुझसे मिले। मैंने उन्हें वित्त सचिव के संक्षिप्त प्रस्ताव के मसौदे को स्वीकार करने की आवश्यकता बताई। मेरा यह भी विचार था कि मंत्री महोदय इस मामले पर 24 अप्रैल, 1981 को होनेवाली प्रबन्ध समिति की बैठक में विचार करें। परन्तु वित्त सचिव द्वारा सुझाए गए सशोधित मसौदा पर विचार किये बिना ही प्रबन्ध समिति ने पूर्व पारित विस्तृत प्रस्ताव की ही पुष्टि कर दी।

मैं तो 2 वर्ष पूर्व से इस निणय पर पहुँच चुका था कि मुझे इंडियन रैडक्रास सोसायटी तथा अन्य सबद्ध हिंदू कुष्ठ निवारण संघ आदि संस्थाओं का अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। इंडियन रैडक्रास सोसायटी तथा उससे सबद्ध संस्थाओं से मेरे सबद्ध न रहने के निणय की सूचना सोसायटी के महामंत्री को 8 जून, 1981 को दी गयी थी। उन्होंने इसकी सूचना सोसायटी के अध्यक्ष को भेज दी। 10 जून, 1981 की शाम को सोसायटी के अध्यक्ष मुझसे मिलने आये। मैंने उनके सामने भी अपना निणय दोहराया। अगले दिन 11 जून 1981 को इंडियन रैडक्रास सोसायटी के

महामंत्री को लिखित रूप में यह सूचना भेज दी गई कि सोसायटी के निरंतर असंतोषजनक ढंग सहाय करने के कारण राष्ट्रपति सोसायटी तथा उससे संबंधित सस्याओं से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते। उनसे इसी बात की प्राप्ति की गई कि वे सोसायटी के नियमों में ऐसा आवश्यक संशोधन करें ताकि राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का सोसायटी से किसी प्रकार का संबंध न रहे। नियम संबंधी किसी समस्या से बचने के लिए राष्ट्रपति ने इस बात की सूचना भी भेज दी कि चालू समय के लिए एन० आर० लस्कर सोसायटी के अध्यक्ष रह सकते हैं।

इस सूचना से इंडियन रेट्रान्स सोसायटी के लिए यह संभव हो गया कि 11 जून, 1981 के लिए निर्दिष्ट की गई आम सभिति की वार्षिक बैठक कर-सके। मैंने प्रबंध समिति के सदस्यों को भी नामजद नहीं किया, जिनके नाम प्रधानमंत्री ने 10 जून, 1981 के अपने पत्र में मुझे सुझाये थे। 30 जून को प्रधानमंत्री मुझसे मिलीं। विचार के दौरान प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि नामजद सदस्यों के बिना प्रबंध समिति काम करने में असमर्थ रहेगी। इसलिए मैंने उनके द्वारा सुझाये गये नामों की 1981-82 की प्रबंध समिति के लिए स्वीकृति दी थी।

इंडियन रेट्रान्स सोसायटी के कार्यकारी महामंत्री ने अगले वर्ष के प्रारंभ में मेरे सचिव को यह सूचना दी कि मेरी इच्छाओं के अनुरूप तथा अन्य औपचारिक-साए पूरी करके नियमों में संशोधन कर दिया गया। उपराष्ट्रपति को सोसायटी का अध्यक्ष और उनकी पत्नी को सोसायटी की महिला अध्यक्ष बनाया गया।

इंडियन रेट्रान्स सोसायटी स्वायत्त संस्था है। सरकार का इसके कार्य पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं। यह ठीक है कि सोसायटी के अध्यक्ष (जो भी हाल के समय तक भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे) प्रबंध समिति के सदस्यों और चेयरमैन को नामजद करते थे। इतने पर भी इसके प्रबंध में सरकार का कोई विशेष महत्त्व नहीं था। सरकार उसने कार्यों की देखभाल करने की स्थिति में भी नहीं। इस स्थिति में राष्ट्रपति का सोसायटी का अध्यक्ष बने रहने में कोई रुकावट नहीं थी क्योंकि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि वे उनके संरक्ष में प्राप्त शिकायतों की जांच करवा सकें अथवा कोई आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकें।

भारत के राष्ट्रपति का रेट्रान्स सोसायटी के अध्यक्ष के नाते कर्तव्य के संबंध में भी मैं सहमत नहीं था। नियमों के अधीन सोसायटी का प्रेजिडेंट अध्यक्ष और प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों की नामजदगी करता है। क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सोसायटी की नियुक्तियों और नामजदगियों के संबंध में अपने मंत्रिमंडल के परामर्श का स्वीकार करने के लिए वह सकता है। इस संबंध में स्थिति अस्पष्ट है। परन्तु निश्चय ही मैं समझता हूँ कि इस बात का उत्तर नकारात्मक है।

इहीं सब बातों के कारण मैंने इंडियन रेट्रान्स सोसायटी तथा उससे संबंधित संस्थाओं से अपने आपको अलग करने का निश्चय किया था।

विश्वविद्यालय और भारत का राष्ट्रपति

विश्वविद्यालयों से संबद्ध नियमों के अनुरूप भारत का राष्ट्रपति केन्द्र के अधीन विश्वविद्यालयों का 'विजिटर' होता है और राज्यपाल अपने प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या कोई राज्यपाल जो किसी विश्वविद्यालय का कुलपति भी है, जिसे सविधान की धारा 163 के अनुरूप अपने मंत्रिमंडल के परामर्श और सहायता से कार्य करना होता है, क्या वह कोई स्वतंत्र नियम भी ले सकता अथवा काम कर सकता है। इस प्रकार का प्रश्न पहली बार पूना और आंध्र विश्वविद्यालयों के संबंध में उठा। उस समय के महान्यायवादी का मत था कि कुलपति राज्यपाल की स्थिति में काम नहीं कर सकता, भले ही वह उस प्रदेश का राज्यपाल होता है। वह कुलपति के रूप में ही विश्वविद्यालयों के संबंध में कोई नियम ले सकता है, राज्यपाल के रूप में नहीं। यही प्रश्न 1964 में सामने आया। इस अवसर पर महान्यायवादी ने देश के कुछ विश्वविद्यालयों पर लागू नियमों पर विचार का परामर्श दिया। इन नियमों में एक सामान्य बात का उन्होंने उल्लेख किया और कहा कि इन नियमों में कुलपति और सरकार पर काम का दायित्व सौंपा गया है। कुलपति विश्वविद्यालय का एक भाग होता है जब वह उसके संबंध में अपने कार्यों का पालन कर रहा होता है तो वह सरकार के मुखिया के रूप में नहीं, परंतु अपने दायित्व पर काम करता है।

कई बार यह विचार भी प्रकट किया गया है कि राज्यपाल को कुलपति इस लिए बनाया जाता है कि सरकारी नियंत्रण रहेगा। ऐसा असंभव है क्योंकि इस स्थिति में कुछ कार्यों के लिये प्रदेश सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। राज्यपाल सामान्य रूप से विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। वह उस पर सरकारी नियंत्रण को सुरक्षित रखने के लिये नहीं बल्कि उसे सम्मान प्रदान के लिए है। इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुलपति अपने मंत्रियों और मंत्रियों के परामर्श और सहायता से काम करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय

को अपना प्रवर्ध करने के सबध मे स्वायत्त सस्था माना जाता है। और यदि कही सरकार को कुलपति के माध्यम से परोक्ष रूप से कुछ विश्वविद्यालयों पर अपना नियन्त्रण रखन की चाह होती तो उसके लिए विशेष नियम की व्यवस्था की गई होती।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के कार्यों पर विचार का अवसर आया क्योंकि विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी ने इस सबध मे अपील की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कहना था कि भारत के राष्ट्रपति और 'विजिटर' का पद एक व्यक्ति मे समाहित हो गया है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वह अपने मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है और विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के रूप में वह मंत्रियों के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं।

इस निणय के प्रभाव पर विचार करने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति के रूप में मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श पर जब वह कार्य करता है तो उसके कार्यों के प्रति दायित्व सरकार का होता है। अपने मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करने की आवश्यकता न समझी जाए तो उसका दायित्व क्या होगा। ऐसी स्थिति में उसने विवाद में फँस जान की सम्भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह वाछनीय नहीं कि भारत के राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के रूप में भी किसी भी विधान में फँसाया जाए। राष्ट्रपति के विश्वविद्यालय के 'विजिटर' के रूप में और अपनी सरकार से स्वतंत्र रहकर काम करने के कानूनी परिणामों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। इस सबध में अधिकारिक निणय ही सग के लिए इस विवाद को समाप्त कर सकती है।

मेरा अतिम गणतन्त्र दिवस सदेश

अपने राष्ट्रपति काल में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र की जनता को पाँच बार और गणतंत्र दिवस पर तीन बार संबोधित करने का अवसर मिला। आमतौर पर यह भाषण आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में ही रिकार्ड करने की परंपरा रही है और इस भाषण को राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर प्रसारण करने के लिए विभिन्न केंद्रों को भेजा जाता रहा है। यह परंपरा रही है कि मेरे सचिवालय द्वारा इस भाषण की सूचना प्रधानमंत्री के सचिवालय को रिकार्डिंग से एक-दो दिन पहले दी जाती थी। अतिम अवसर के अतिरिक्त उससे पहले मुझे कभी भी अपने भाषण में कुछ जोड़ने तथा परिवर्तन करने के लिए सुझाव नहीं दिया गया।

अतिम अवसर अर्थात् 1982 के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो कुछ हुआ उसका संक्षेप में, मैं वर्णन करना चाहूंगा।

14 जनवरी की संध्या को प्रधानमंत्री मुझे यह सूचना देने के लिए मिली कि वे अपने मंत्रिमंडल में कुछ सदस्य बढ़ाना चाहती हैं और उनके विभागों में भी परिवर्तन करना चाहती हैं। उस समय मैंने सरसरी तौर पर उन्हें यह सूचित कर दिया कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के नाम दिया जानेवाला भाषण मैं उन्हें कुछ दिन में भेजने वाला हूँ। इसके अनुसार मेरे सचिवालय ने मेरा भाषण प्रधानमंत्री के सचिवालय को 18 जनवरी को भेज दिया। अगले दिन 12.30 बजे प्रधानमंत्री मुझसे मिली और मुझे अपने भाषण में कुछ अक्षर बढ़ाने और परिवर्तन का सुझाव दिया।

अपने भाषण के प्रथम भाग में मैं राष्ट्र द्वारा पिछले 30 साल की उपलब्धियों का वर्णन किया था और कहा था कि हमें उस पर गर्व है। उसके बाद मैंने राष्ट्र की उन बातों का उल्लेख किया था जिनके संबंध में हम सब चिंतित थे कि पंचवर्षीय योजनाओं पर भारी खर्च के बावजूद पिछले दशक में हम प्रतिव्यक्ति आय में बहुत ही नगण्य वृद्धि कर पाए हैं। इसके साथ ही सभी आवश्यक उप

भोक्ता वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती रही हैं। (उपभोक्ताओं का ध्यान केवल इसी बात पर जाता है) जबकि मूल्य सूचकांक में थोका दामो पर कमी हुई है जिसके आधार पर सरकार मुद्रास्फीति की दर निवालीती है। इसके साथ ही मैंने छोटे किसानों, खेतिहर मजदूरों और नगरों में रहने वाले निधनों की स्थिति, कानून और व्यवस्था के बिगड़ने, देश में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने और कुछ समय पूर्व गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्र सेवा और बलिदान की जो भावना थी उससे लोप होने और जन-नेताओं के स्तर में गिरावट आने और इन सारी बातों के हमारे जीवन में प्रवेश पा लेने के कारण सच-आत्म निरीक्षण के लिए कहा था। भाषण में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे सब सहमत न हो। इसके बावजूद प्रधानमंत्री कुछ परिवर्तन चाहती थी। उनका कहना था कि इस भाषण का मूल रूप में प्रसारित होने पर सत्ता में उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। उन्होंने अनुभव किया कि संभवतः यह भाषण कुछ स्थानों पर अधिक कठोर हो गया है। उनके द्वारा सुझाये गए परिवर्तनों के बाद भी जो बातें मैं कहना चाहता था वे उस भाषण की भावना में मूलरूप से विद्यमान थी। उन्होंने आशा प्रकट की कि सुझाये गये संशोधनों को स्वीकार कर लूंगा। दोपहर बाद जब मैं उनके द्वारा सुझाये गये परिवर्तनों का अध्ययन किया तो मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया। मेरे परिवर्तन करने के बाद भी मेरे भाषण का मुख्य भाव पूर्ववत् ही था, केवल प्रतिव्यक्ति आय के संबंध में दिया गया आंकड़ा निचाले गये थे। मैंने प्रधानमंत्री को टेलीफोन पर यह बताया कि मैं उनके द्वारा सुझाये गये सब संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। इस स्वीकृति पर उन्होंने मुझे अतिशय धन्यवाद दिया।

परंतु बाद में पता चलने पर मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मन्त्रिमंडल के प्रमुख सदस्यों और स्वयं प्रधानमंत्री का मेरे भाषण से अप्रसन्नता हुई। मेरे भाषण में ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे सरकार और सत्ता दल की सीधी आलोचना होती हो। यह तो राष्ट्र के पिछले 30 साल के कार्यों का एक प्रकार से लेखा-जोखा-सा था, जिसके संबंध में मेरा विचार था कि राष्ट्रीय दिवस के अपने अंतिम भाषण में मैं इस पर अपने विचार प्रकट करूँ। मैं सरकार के अच्छे कार्यों की सराहना की और उसकी कमजोरियों को उजागर करने में भी नहीं हिचकिचाया। दूसरे आश्चर्य की बात यह थी कि मैं प्रधानमंत्री की इच्छा का अनुरूप अपने भाषण में परिवर्तनों को भी स्वीकार कर चुका था जैसा कि इससे पूर्व अवसरों पर मैंने कभी नहीं किया था। ऐसी स्थिति में मुझे खेद है कि मेरे भाषण का गलत समझा गया।

भारतीय परिदृश्य : चिन्तनीय निष्पत्ति

हमारे देश के लोगों की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि आवश्यक पोषक पदार्थ, भोजन, स्वास्थ्य चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं प्राप्त हों। कुपोषण, सामाजिक रूप से आवागम सुविधाओं की असंतोषजनक स्थिति में अमा भी लाखा-कौड़ियों में रह रहे हैं। हमारे देश की 30 प्रतिशत जनता किसी-न किसी प्रकार के अभाव से ग्रस्त है। निश्चय ही यह स्थिति हमारे लिए चिन्ता का कारण है।

हमारे देश के 30 प्रतिशत निम्न-आय व्यक्तियों पर 15 प्रतिशत व्यय होता है जबकि ऊपर की श्रेणी के 30 प्रतिशत लोगों पर 50 प्रतिशत खर्च किया जाता है। इस प्रकार के आधार पर 48 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा के नीचे है। निम्न-आय के 30 प्रतिशत लोगों पर जो व्यय होता है, उससे उनके निम्न पोषण स्तर का पता चलता है। विभिन्न वर्गों द्वारा जिन उपभोक्ता व्यय का मैंने उल्लेख किया है उससे आय के असमान वितरण का वादा होता है। कुछ समय पूर्व किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ऊपर की श्रेणी के 5 प्रतिशत परिवारों के हिस्से में 23 प्रतिशत आय आती है जबकि नीचे की श्रेणी के 5 प्रतिशत पर बस एक प्रतिशत आय और धन के वितरण में स्पष्ट असमानताएं विकासशील और विकसित देशों में भी हैं और संभवतः उनके लिए भी यह चिन्ता की बात है। यहाँ भारत में हमारे लिए इस बात की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि हम सुनिश्चित अर्थ व्यवस्था द्वारा आर्थिक विकास और असमानताओं को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में बहुत प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बार इस बात का उल्लेख किया था कि पहली दो योजनाओं के काल में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। परन्तु उन्होंने यह विचार भी प्रकट किया था कि इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि उन योजनाओं से हुई अतिरिक्त आय कहाँ गई और इसका वितरण कैसे किया गया। अक्टूबर, 1960 में प्रोफेसर महालनोबिस का अध्ययन में एक कमिटी इस बात का अध्ययन करने के

लिए बनाई गई कि आय और सम्पदा के वितरण में क्या रद्धान है और उन्हें इस बात का भी पता लगाना था कि वित्तीय व्यवस्था की काय प्रणाली से सम्पदा किस सीमा तक कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी हुई है। इस प्रकार इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आय के असमान वितरण की समस्या नई नहीं है। 1960 के प्रारम्भ में सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर गया।

दश के वित्तीय माधनों का कुछ लोग के हाथ में एकत्र हो जाने से लोकतंत्र पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। समय बीत जाने के साथ-साथ चुनावों पर खर्च बढ़ता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, भले ही वह कितना धनी क्यों न हो, अपने वित्तीय साधनों से चुनाव नहीं लड़ सकता। मशीन प्रकार के राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ अपने चुनाव के लिए बड़े उद्योगों तथा अन्य दलीय स्वायत्त व्यक्तियों से वित्तीय सहायता लेते हैं। अपने विशाल वित्तीय साधनों के कारण जिनमें से कुछ का कोई हिस्सा वित्तों में नहीं होता, वे अपना दलगत स्वार्थों के कारण चुनावों के परिणामों और देश की वित्तीय और आर्थिक नीतियों का प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों के हाथ में सम्पत्ति जमा होने के कारण समाज विरोधी परिणाम निकलते हैं और उसका प्रभाव लोकतंत्रीय व्यवस्था की काय प्रणाली पर भी पड़ता है। इसलिए हमें भी हमें ही कुछ लोगों के हाथ में आर्थिक सत्ता इकट्ठा होने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे।

एक और विचारणीय मुद्दा सावधानी जयन्ता प्राइवेट और उससे बाहर के क्षेत्रों के अप्रशिक्षित मजदूरों के अतनमान में असमानता का है। मुझे याद है कि एक बार एक सभा में प्रधानमंत्री साहबजी देसाई ने यह कहा था कि वर्गों ने किसी सरकारी क्षेत्र के प्राधिकरण में एक महिला सफाई कमाली को प्रशिक्षित उद्योग में भी मजदूरों का वतन लगभग इतना ही है। संगठित जयन्ता उससे बाहर के क्षेत्र के अप्रशिक्षित मजदूरों की समृद्धि और शैक्षणिक पठ्यभूमि लगभग एक जैसी होती है जबकि संगठित क्षेत्र के मजदूरों का जय क्षेत्र ने मजदूरों से कई गुना अधिक वेतन मिलता है। संगठित क्षेत्र के मजदूरों को काफी सुरक्षा भी प्राप्त है जबकि अन्य मजदूरों की किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिलती। अतएव उनमें से अधिकांश प्रकार रहते हैं। यह बात सब जानते हैं कि अध्यापकों तथा सफेदपोश मजदूरों ने अपनी शिक्षा तथा अन्य योग्यताएँ प्राप्त करने के लिए काफी खर्च किया होता है। उन्हें राष्ट्रीयकृत उद्योगों तथा सरकारी प्राधिकरणों और व्यक्तिगत उद्योगों के संगठित कमचारियों से बहुत कम वेतन मिलता है जबकि असंगठित क्षेत्र के कमचारियों की योग्यता इनके मुकाबले में बहुत अधिक होती है। कुछ राष्ट्रीयकृत प्राधिकरणों के कमचारियों को अपेक्षाकृत अधिक वेतन के साथ-साथ मकान और चिकित्सा सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं जबकि ऐसी सुविधाएँ और लाभ हमारी

अधिकांश जनता की पहुँच से बाहर हैं।

सच्चे समय स समाज के इस संगठित और मुखर कमचारी वर्ग की समस्याएँ और माँगें हमारे लिए चिन्ता का विषय रही हैं। हमने सदा इन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, जबकि व निधनता के इस महासागर में एक छोटे स समृद्ध द्वीप के समान प्रतीत होते हैं।

राष्ट्रीयकृत प्राधिकरणों, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के तथा छोट और बड़े उद्योगों—विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के कमचारियों की संगठित करना अपेक्षाकृत सरल कार्य होता है। जब राजनीतिक दल और व्यावसायिक मजदूर नेता उन्हें और अधिक सुविधाएँ दिलवाने के लिए उनकी बात उठाते हैं, उस समय उन लोगों को इन सब बातों का ध्यान नहीं रहता कि उनकी माँगें पूरी करवाने से देश की वित्तीय तथा असंगठित मजदूरों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं, प्रायः अपने अनेक साम्यवादी दोस्तों से इस बात का जिक्र किया है कि व देहात में रहनेवाले मतदाता को प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि उनके दल का संगठित क्षेत्र के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करनेवाला ही समझा जाता है।

वित्तीय साधना के इस विकृत स्वरूप और आय के वितरण तथा लोगों के जीवन स्तर की असमानता के प्रति लोग अब अधिक देर तक उदासीन नहीं रह पायेंगे। इसकी प्रतिक्रिया होगी।

पंचवर्षीय योजना में अत्यधिक पूँजीनिवेश के बावजूद प्रतिव्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में अनेक बार उतार चढ़ाव आये हैं और इस स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वर्तमान मूल्यों के अनुसार स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दिखाई गई है परंतु इस प्रगति नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के रूप में, वर्तमान मूल्यों के अनुसार 1977 में प्रति व्यक्ति आय 1094 रुपये थी। 1980 में यह 1379 रुपये थी परंतु स्थिर मूल्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 1971 में 635 रुपये थी, 1977 में 650 रुपये और 1980 में 678 रुपये। थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि का स्थिति कुछ भी हो, उपभोक्ता वस्तुओं के दाम निरंतर बढ़ते रहे और यही बात सबकी चिन्ता का केन्द्र बिंदु है। केवल आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य ही धीरे धीरे बढ़ते नहीं रहे हैं वरन् लोगों को रेल और सड़क यातायात तथा बिजली और पानी के लिए भी अधिक खर्च उठाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में लोग सरकार की मुद्रास्फाति को पूर्णतया राब देने के दाव को मजाम ही समझे। हमें ज्ञान है कि मुद्रास्फाति विश्वव्यापी समस्या है और लोग इसके प्रति जागरूक हैं, इसलिए इस सहते रहना उनके लिए आसान काम नहीं। हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इस मूल्य वृद्धि का कारण कहा तक तेल के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि आदि अन्तर्राष्ट्रीय हैं और कहा तक हमारी अपनी गलतियाँ और असफलताओं के कारण।

हमारे देश ने जितनी प्रगति की है वह जनसंख्या की वृद्धि के कारण अधिकांश रूप से अप्रभावी हो जाती है। नई नौकरियों के उचित अवसर न होने के कारण पिछले श्रेकार लोभ और धार्मिक क्षेत्र में नये आनेवाले भजदूरो के कारण बेकारी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद बढ़ती बेकारी, उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें, जीवन स्तर में सुधार की कमी आदि कारणों से अधिकांश लोगों में असंतोष फैल रहा और इस प्रकार सरकार बठोर और दमनपूर्ण कदम उठाने के लिए विवश होगी।

इन वर्षों में, विशेष रूप से देश के कुछ भागों में, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ने से सभी देशभक्त भारतीय चिंतित हैं। वे मायताएँ और मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं जिनके कारण भूतबाल य हम शान्तिपूर्ण आपस में मिलकर रहते थे। कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान और किसी के जीवन और सम्पत्ति के प्रति सुरक्षा भावनाओं का प्रभाव हमारे चरित्र में से समाप्त होता जा रहा है। दुबल और भोले भाले बग के लोगों पर अत्याचार करने और स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार और उन्हें परेशान करने के संबंध में हम प्रायः मुनते रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति और नतिकता का हम पर जितना दिपावटी प्रभाव रह गया। परंपरागत मायताएँ विश्व भर में कमजोर हुई हैं परन्तु इस बात के कारण समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न रोके नहीं जा सकते।

इस पुस्तक में किसी अन्य स्थान पर मैंने राजनीतिक भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। अपने पांच साल के राष्ट्रपति काल में मैंने सावजनिक जीवन में गिरावट आने का कई बार उल्लेख किया है।

इसे सभी ने स्वीकार लिया है कि राष्ट्रीय जीवन की जिन बुराइयों अथवा कमजोरियों का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, उन्हें शीघ्र ही दूर किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अथवा दल यह नहीं कह सकता कि वही देशभक्त है और सामाजिक तथा धार्मिक रूप से दुबल बग की भलाई की चिन्ता केवल उसी को है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि प्रत्येक दल में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान किये हैं और जिन्हें धन और सत्ता के प्रति कोई आकर्षण नहीं। अपने राजनीतिक विरोध के कारण ऐसे लोगों को विश्वसनीयता में सन्देह करना एक भयंकर भूल है। इसलिए प्रायः मैंने यह अनुभव किया है कि यदि सत्ता पक्ष को राष्ट्रीय समस्याओं के सामा य और उचित हल की खोज है तो उसके लिए अपनी पार्टी के प्रभाव से हटकर देश के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों से विचार करना चाहिए। इससे लाभ होगा।

इसमें सन्देह नहीं है कि हमने राष्ट्रीय एकता और समन्वय परिपद आदि समस्याओं का निर्माण किया है। परन्तु व अपने आचार और सदस्यों के अपन क

कारण सामंदायत विचार विमर्श में महायव मिद्ध नहीं हो गयी।

अभी हाल के वर्षों तक शेख मोहम्मद अदुल्ला भारतीय मुसलमानों में अद्वितीय रहे हैं। उन्हीं द्वारा उठाये गये कुछ कदमों व कारण दुर्भावपूर्ण विचारों के उठने पर भी उनकी ऐश भक्ति और धर्मनिरपेक्ष मान्यताओं के सबंध में किसी ने उन पर सन्देह नहीं किया। ज्याति रगु केवल वामपंथ के या दोनोंपक्षा ही नहीं है, उन्होंने सभी स्तरों के बंगालिया का प्रेम प्राप्त किया है। ई० एम० एस० मन्मूदीपाद की योग्यता और देशभक्ति पर सन्देह नहीं किया जा सकता। मैंने केवल कुछ नामों का बणार किया है परन्तु बहुत से योग्य और ध्येय के प्रति समर्पित अन्य बहुत से व्यक्ति हैं जिनका परामर्श सरकार और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

यदि गता पक्ष के उच्च नेता सच्चाई से विरोधी दला से सहयोग चाहेंगे तो मुझे सन्देह नहीं कि सस्वच्छापूर्वक ऐसा करने के लिए तयार होंगे। उस प्रकार के दृष्टिकोण से देश का राजनीति का नापरण व्यापक रूप से सुधरेगा। यहाँ मैं उन भावनाओं को स्मरण करना उपयोगी समझता हूँ जो मैंने राष्ट्रपति पर महाभारत के समय राष्ट्र ने नाम अपन प्रारम्भिक तापण में प्रकट की थी। मैंने आपसी सदभावना को अपनाते के लिए कहा था। जिससे जनता के व्यापक स्पर्धन और राष्ट्र की शक्ति का समर्थन करके हानिप्रद राजनीति में बचा जा सके।

